हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 जनवरी, 1974

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

सोमवार, 14 जनवरी, 1974

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8) 31
दी हरियाणा ऐप्रिएशन बिल, 1974	(8) 31
वर्ष 1974–75 के बजट पर सामान्य चर्चा	(8) 33

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 14 जनवरी, 1974

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चन्डीगढ में 1400 बजे हुई । अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उतर –

Mr. Speaker : Question Hour.

Electric Connections for Tubewells

***545. Chaudhri Ram Lal Wadhawa :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state -

(a) the district-wise total number of applications received for electric connections for tubewells during the year 1973;

(h) the district-wise total number of electric connections given to the applicants referred to in part (a) above together with the number of applications otherwise disposed of ; and

(c) the number of applications for electric connections to tubewells lying pending as on 1st January, 1973 ?

State Minister for Irrigation & Power : (Sardar

Harmohinder Singh Chatha) : (a), (b) and (c) : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The district-wise information is not available as the boundries of divisions/ circles of H. S. E. H. are not coterminous with revenue boundries of the tehsil/districts. However, the circle-wise numbers of applications for tubewell connections received uptil 31.12.1973 are as under:—

Sr. No.	**Name of Circle**	**No. of applications received for T/ Wells connections.**
1.	Chandigarh.	2,328
2.	Karnal.	4,078
3.	Faridabad.	1,705
4.	Delhi.	4,044
5.	Hissar.	2,240
6.	Rohtak.	3,533
	Total :	**17,928**

(b) The number of electric connections given from

1st January, 1973 to 31st December, 1973 out of the applications referred to in (a) above is not available. However. the total number of tubewell connections given and the applications disposed of during the period from 1st January, 1973 to 31st December, 1973 are as under—

Sr. No.	Name of Circle	No. of Applications cancelled/ connections withdrawn for non-completion of formalities.
1.	Chandigarh.	2,042	319
2.	Karnal	3,523	1,197
3.	Faridabad	1,101	223
4.	Delhi	2,185	436
5.	Hissar	1.287	733
6.	Rohtak	2,218	472
	Total :	12,356	3,380

(c) 8,242

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि रोहतक में कम कनैक्शन्ज दिये जाने के क्या कारण हैं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, जिस हिसाब से टैस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, उसी हिसाब से कनैक्शन्ज दिये जा रहे हैं । ऐसी बात नही है कि एक जिले को कम कनैक्शनज दिये जाएं और दूसरे को ज्यादा दिये जाते हों ।

मलिक सतराम दास बतरा : क्या मिनिस्टर साहब बताएगे कि रोहतक और महेन्द्रगढ जिलों से सब से ज्यादा एप्लीकेशन्ज आई हैं? क्या इस आधार पर कनैक्शन्ज वगैरह दिए जाने की सरकार की कोई पालिसी है

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, हम जिलावार ऐसा नहीं करते सर्कलवाईज किया जाता है डेढ़ जिला का हमारा सर्कल होता है । और जहां तक महेन्द्रगढ का सवाल है, वह हमारा सर्कल नहीं है इसलिए इस बारे में नहीं बताया जा सकता ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मिनिस्टर साहब, बतलाएगे कि कनैक्शन्ज देने में जो देरी हो जाती है, इसके लिए सरकार कोई कदम उठा रही है जिस से कनैक्शन्ज वगैरह मे देरी न हो ।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जमीदार को जल्द से जल्द कनैक्शन्ज दिये जाएं ।

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अपने सवाल के जवाब में पार्ट (सी) में बताया कि ट्यूबवैलज के कनैक्शन्ज के लिये 1 जनवरी, 1973 को 8,242 एप्लीकेशनज पैनडिंग थी । तो क्या वे बताएगे कि इन टयूबवैल्ज को कब तक कनैक्शन्ज दे दिये जाएगें?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, हमारे पास जो डिटेल है, उस बारे मैं बता देता हूं । हमारे पास 1.1.73 से 31. 12. 73 तक कुल 17, 928 एप्लीकेशन्ज आई थीं, जिन में से हमने 12,356 को कक्तैशन्ज दे दिये और बाकी 3380 एंप्लीकेशन्ज जो थीं, वे कैंसल हो गई ।

चौघरी दल सिंह : क्या मिनिस्टर साहब बतलाने की कृ पा करेंगे कि क्या यह दुरुस्त है कि मैटीरियल की कमी के कारण कनैक्शन्ज नहीं दिये गए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कारण है कि कनैक्शन्ज वगैरह देने भै देरी की जाती है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, मैटीरियल की कमी के कारण भी ऐसा हुआ है । लेकिन फिर भी हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जमीदारों को जल्द से जल्द कनैक्शन्ज दिये जाएं ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मिनिस्टर साहब बतलाएंगे कि रोहतक सर्कल से कुल कितनी एप्लीकेशन्ज आई थीं और उन में से कितनों को कनैक्शनज दे दिये गये हैं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चटठा : स्पीकर साहब, रोहतक सर्कल से हमें कुल एप्लीकेशन्ज 2, 218 आई थीं जिन में से 472 को कनैक्शनज दे दिये गये, बाकी कुछ गल्त थीं, इसलिये नहीं दिये गये ।

Mr. Speaker : This not a supplementary question to the question answered.

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : स्पीकर साहब, आज अखबार में हने पढ़ा है कि हरियाणा को भाखडा मैनेजमैंट बोर्ड से 2.7 मिलियन यूनिट बिजली की कमी होने का मुकाम है, क्या इसके लिए सरकार बिजली में कोई और ज्यादा कटौती तो नहीं करेगी?

चौधरी शिब राम वर्मा : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब बतलाएगे कि जो कनैक्शनज वगैरह दिये जा रहे है उन पर यह गारन्टी भी दी गई है कि जरूरत के मुताबिक बिजली दी जाएगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठाः स्पीकर साहब, जरूरत के मुताबिक दे रहे हैं और देते रहेंगे ।

श्री हरि सिंह : क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाएगे कि टैस्ट रिपोर्ट जब दे दी जाती है तो उसके दिये जाने के कितने दिनों के बाद कनंक्यानज दे दिये जाते हैं? इसके लिये कोई टाईम भी फिक्सड होता है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : टाईम फिक्स नहीं हो सकता । जब टैस्ट रिपोर्ट आती है तो कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द कनैक्शन दे दिये जाएं ।

चौधरी दल सिंह : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जो एप्लीकेशन्ज आती हैं, उनका इन्दराज नहीं किया जाता जिस की वजह में एप्लीकेशन्ज काफी देर तक पैडिंग पड़ी रहती हैं तो क्या गवर्नमैंट इस वात को ध्यान में रखते हुए यह हिदायतें जारी करेगी कि टैस्ट रिपोर्ट लेते समय उसकी पावती रसीद दी जाए?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता) : स्पीकर साहब, इससे पहले मैंने एक प्रश्न के उत्तर में आश्वासन भी दिया था कि जो भी टैस्ट रिपोर्ट बिजली बोर्ड के पास आएंगी, उसकी रसीद दी जाएगी ।

चौधरी राम लाल वधबा : स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि टयूयवैल्ज के लिये जो बिजली आजकल जमीदार को मिल रही है, वह कितने घण्टे मिल रही है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, आजकल दिन में 12 घण्टे विजली जमीदार को दी जा रही हैं । लेकिन पिछले साल की एवरेज निकाल कर यह देखा गया है कि जमीदार सिर्फ 6 घण्टे ही बिजली यूज करता है ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो टैस्ट रिपोर्ट है यह सब–डिविजन–वाईज ली जाती है या कि डिर्स्टक्ट–वाईज ली जाती है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : सब–डिविजन–वाइज ।

श्री अमर सिंह : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जो एप्लीकेशन्ज पैंडिंग पड़ी हैं उन मे से कितनी टैस्ट रिपोर्ट की एप्लीकेशनज ऐसी है जोकि ह महीने से ज्यादा की है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, ऐसी इन्फर्मेशन मेरे नोटिस में नही है लेकिन 31. 12. 73 तक जो एप्लीकेशनज हमारे पास पैंडिंग होगी, वे हम 50 मार्च तक कलीयर कर देंगे ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसे सरकार ने 12 घण्टे विजली देने का आश्वासन दिया है, पर करनाल में वह आश्वासन पूरा नही हो रहा है, वहां पर कभी दो घण्टे मिलती है, कभी चार घण्टे मिलती है, तो इसका क्या कारण है?

श्री बनारसी दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारी यह पूरी कोशिश है कि आज की स्थिति में टयूबवैल्ज को कम से कम 12 घण्टे बिजली दी जाए । चाहे इंडस्ट्री पर जितनी कट लगानी पड़े पर टयूबवैल्ज को हम कम से कम 12 घण्टे बिजली देंगे, कही फाल्ट की वजह से अगर बिजली बन्द हो जाए तो उसको दूसरे दिन कम्पनसेट कर दिया जाएगा ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : स्पीकर साहब, अभी यहां पर बिजली की कमी की बात चल रही थी । क्या मिनिस्टर साहब यह एग्जामिन करने की कृपा करेंगे कि पिछले 4, 5 दिनों में कितनी बिजली दी गई?

श्री बनारसी दास गुप्ता : स्पीकर साहब, हमारे पास तो डेली रिपोर्ट आती है । अगर आनरेबल मैम्बर यह रिपोर्ट देखना च हि तो देख सकते हैं ।

श्री प्रेम सुख दास : स्पीकर साहब, हमारे हल्के में 8 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं दी जाती, क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि इस के क्या कारण हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ता : ऐसी बात तो नहीं लेकिन फिर भी हम एग्जामिन कर लेंगे । अगर ऐसी बात होगो तो पिछले दिन की कमी को हम अगले दिन कम्पैनसेट कर देंगे ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : स्पीकर साहब, अभी यहां पर बिजली की सप्लाई के बारे में जो चर्चा चल रही है कि 8 घटे तो

विजली दी ही जाती है लेकिन मैं अपने हल्के के बारे में बता सकता हूं कि पिछले चार पांच दिनों से वहां पर दो–तीन घण्टा से ज्यादा बिजली नहीं दी जा रही है ।

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

चौधरी शिव राम वर्मा स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब पड़ताल करवाएंगे कि पिछले ए क हफते में कितनी बिजली मिल रही है जबकि करनाल में सिर्फ 2 घण्टे से ज्यादा नही है ।

श्री बनारसी दास गुप्ता स्पीकर साहब, हम तो पड़ताल करवाते ही रहते हैं ।

Civil Hospital, Jind

***630. Shri Dhaja Ram :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to convert 50 beds Hospital at Jind into 200 beds Hospital ?

State Minister for Home & Health (Shrimati Sharda Rani) : No.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहिबा ने अपने सवाल के जवाब में कहा है कि 'नहीं' तो क्या वे बतलाने की कृपा करेंगी कि जींद के साथ उन्हें कोई नाराजगी है या कि उनके पास इस काम के लिए रुपया नही हँ?

श्रीमती शारदा रानी : स्पीकर साहब, 50 बैडज का हस्पताल ही अभी पूरा नहीं हुआ तो 200 बैडज का हस्पताल बनाने की बात तो इसके बाद ही सोची जाएगी ।

श्री धजा राम : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर महोदया यह बतलाने की कृपा करेगी कि जींद में जो 50 बैडज का हस्पताल पिछले 8 महीने से बन रहा है उस पर कितना काम किया गया है और वह कब तक बन कर तैयार हो जाएगा?

श्रीमती शारदा रानी : 8 महीनों में अभी थोड़ा ही काम हुआ है, कन्ट्रैक्टर और पी. डब्ल्यु.डी. वालों के बीच झगड़ा पड़ गया है, वे लोग काट में चले गए हैं । कोर्ट में जाने के कारण उस हस्पताल का काम रुका पड़ा हे?

Cement

***643. Shri Om Parkash Garg** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state :

(a) the month-wise quantity of cement quota allotted to the District Kurukshetra;

(b) the quantity of cement received during the last four months, i.e. September to December, 1973 ;

(c) whether the full share of the cement quota required to be allotted to the Haryana State was not given during the above said four months; if so, the action being taken by the Government to get its due share ; and

(d) the criteria, if any, adopted for distributing the cement to different districts ?

Social Welfare and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) :

A cut of 10% was imposed by the Govt. of India on the above allocations.

(b) September, 73 October, 73 November, 73 December, 73

439.5 tonnes. 114.5 tonnes. 648.5 tonnes. 522.2 tonnes.

(c) The share of cement for Haryana State is not being met in full, by the Govt. of India and all possible efforts are being made at all levels to get the State quota increased.

(d) Recommendations under FREE SALE CATEGORIES are made by the State Government for different Districts, by and large, on population basis, but minor adjustments are made by the Regional Cement Officer, Government of India, New Delhi, while making allocations on various factories keeping in view the Cement production of each Cement Factory. As regards quantities of Cement earmarked for Panchayats/Small Scale Industries in each District, it is done on the recommendations of the Director of Panchayats/Director Industries.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 71 में गवर्नमैंट आफ इंडिया ने हरियाणा को कितना कोटा दिया और जनवरी में कितना दिया?

Shri Shyam Chand : Sir, the question pertains to district Kurukshetra.

चौधरी दल सिंह : क्या मिनिस्टर साहब, यह बताने की कृपा करेंगे कि आया सरकार की तरफ से कोई ऐसा आर्डर है कि जिला जींद में जो लोग स्माल सेविंग स्कीमें ज्यादा पैसे जमा कराएंगे उनको ही सीमेंट मिलेगा तो क्या सरकार का अधिकारियों को ऐसी हिदायत करने का विचार है कि इस किस्म का हुकम जारी न किया जाए?

Shri Shyam Chand : Sir, in the allotment of cement, priority is given only to those who have given more wheat for procurment. There is no other priority .

चौधरी राम लाल वधबा : क्या मत्री महोदय बताने को कृपा करेंगे कि अरबन एरिया में और रूरल क्या में असग–अलग कितना सीमेंट दिया गया?

Shri Shyam Chand : Sir, the question was asked about the Kurukshetra district.

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मत्री महोदय बताएंगे कि जब वे हरिजनों की कांफ्रेंस अटैंड करने के लिए हल्के में जाते हैं

तो वहां तो वे हिन्दी में बोलते है लेकिन यहां अग्रेजी में क्यों बोलते है?

Mr. Speaker : Order please.

श्री अमर सिंहः सवाल के पार्ट ''बी'' में मंत्री महोदय ने चार महीनों की फिर्गज बतलाई कि इतना–इतना सीमेंट मिला । तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि जिला कुरूक्षेत्र की एक्चुअल रिक्वायरमैंट क्या थी?

Shri Shyam Chand : Sir, requirement is much more than we get quota for each district.

मलिक सतराम दास बत्तरा : क्या मिनिस्टर साहब बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें जो मान दण्ड लिखा गया है क्या इसको जिला अफसर अपनाते भी हैं या नहीं?

Shri Shyam Chand : Every instruction is adhered to by the authorities.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके नोटिस में ऐसी भी शिकायत आई है कि सीमेंट ब्लैक में बेचा जाता है और अगर नोटिस में आई हो तो क्या ऐक्शन लिया गया?

Shri Shyam Chand : If any complaint was brought to the notice of the Government, we have taken action under the D.I. R.

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या चीनी की तरह कुछ सीमेंट की परसैटेज भी की सेल के लिए अलाऊ को जाएगी?

Shri Shyam Chand : We are making experiment for two months.

श्री गौरी शंकरः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सीमेंट की सप्लाई कम क्यों रहती है?

Shri Shyam Chand : Less production of cement in the factories.

श्री के० एन० गुलाटी : क्या मत्री महोदय बताएंगे कि सीमेंट की शार्टेज होने की वजह से अर्बन एस्टेट वाले प्लाट जल्दी वनाने के लिए दिए गार नोटिस वापिस ले लेंगे? ऐसा कोई विचार है?

Shri Shyam Chand : That is a different question.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मंत्री महोदय बनाएगे कि डिस्ट्रिक्ट–वाईज अलाटमैंट की बजाए तहसील–वाईज एलाटमैंट करने का कोई विचार है?

Shri Shyam Chand : I could not follow it.

Chaudhri Phool Chand (Mullana) : May I know from the Hon. Minister as to what steps are being taken to meet the shortage of cement ?

Shri Shyam Chand : We have approached the Government of India for increase in our quota of cement.

चौधरी पीर चन्दः क्या मत्री महोदय बताएंगे कि सीमेंट की कमी होने के कारण हरियाणा में कोई और सीमेंट फैक्टरी लगाने का विचार है?

Shri Shyam Chand : Not at the moment.

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मत्री महोदय बताएंगे कि कुरूक्षेत्र जिला के जिन किसानों ने गवर्नमैंट को गन्दम दे दिया है क्या उन सब को सीमेंट दे दिया गया है या नहीं?

Shri Shyam Chand : We are giving priority to those people Sir.

Consumption of Electricity

***661. Chaudhri Ishwar Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state

(a) the average daily consumption of electricity in the State in March, 1968;

(b) the average daily consumption of electricity in the State in March, 1973; and

(c) whether the average daily consumption is likely to increase in 1973-74; if so, the sources from which the same will be met with ?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha)

(a) 2.03 Million Units.

(b) 5.33 Million Units.

(c) Yes, Sir. This will be met by getting additional power from Ranapartap Sagar Atomic Power Plant, Rajasthan and Badarpur Thermal Plant, Delhi.

चौधरी दल सिह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट–वाईज कंजम्पशन कितनी है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : मैंने पहले भी अर्ज किया था कि यह हम सर्कल वाईज लेते हैं ।

चौधरी राम लाल वधवा : मत्री महोदय ने सवाल के जवाब 'बी' में मार्च 1973 की फिंगर्ज दी हैं, तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि मार्च 72 की फिगर्ज क्या हैं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, सवाल में मार्च 68 और 73 के बारे में पूछा गया था लेकिन मार्च 72 के बारे मे नहीं पूछा गया था, इसलिये नहीं बताई जा सकतीं ।

Conversion of Sikandarpur Minor

***667. Chaudhri Phul Singh Kataria :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under

consideration of the Government to convert Sikandarpur Minor

from Lift scheme to normal flow scheme in Jhajjar Tehsil; if so, the period within which it is likely to by materialised

State Minister of Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): Yes, sir. The Scheme is under consideration. No date however, can, be given at present by which the scheme is likely to materialise,

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस पर कुल कितना खर्च आएगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिह चट्ठा : 16 लाख 11 हजार ।

Liquor Shops

Chaudhri Shiv Ram Verma :Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state—

(a) the districtwise number of Country liquor and Indian made foreign liquor shops, separately, in the State as on 31st March, 1968;

(b) the districtwise number of Country liquor and Indian made foreign liquor shops, separately, as on 31st March, 1973; and 30th November, 1973, respectively;

(c) the districtwise number of bottles of Country liquor and Indian made foreign liquor, separately, consumed during the year 1967-68; and

(d) the districtwise consumption of Country liquor and Indian made foreign liquor, separately, during the year 1972-73?

Social Welfare and Taxation Minister : (Shri Shyam Chand) : (a), (b), (c) and (d) A statment is laid on Table of the House.

Statement

(a) District-wise number of Liquor shops as on 31st March, 1968:—

Name of District.	Country Liquor Shops	Indian made Foreign Liquor shops
Hissar	45	14
Rohtak	28	9
Gurgaon	18	10
Karnal	47	9
Ambala	29	14
Mohindergarh	45	3
Jind.	28	2
Total :	240	61

(b)

31st March 1973			30 Nov. 1973	
Name of	Country	Indian made	Country Liquor	Indian made

Distt.	Liquor shops.	Foreign Liquor shops.	shops	Foreign Liquor shops.	
Hissar	44	41	59	44	
Rohtak	28	26	30	33	
Sonepat	14	22	14	16	
Gurgaon	26	55	29	78	
Karnal	33	30	34	32	
Kurukshetra	29	16	31	20	
Ambala	43	33	48	37	
Mohindergarh	*5	5	31	8	*Rewari Tehsil only. Rest of the Distt. was dry.
Bhiwani	11	3	44	10	
Jind	33	13	33	10	
Total:—	266	244	353	288	

(c) District-wise consumption of liquor during the year 1967-68 in bottles:—

Name of District	Country Liquor	Indian made Foreign Liquor
Hissar	14,45,968	35,192
Rohtak	16,38,534	55,916
Gurgaon	6,73,472	73,696
Karnal	1,346,184	29,632
Ambala	1,449,400	1,847,76
Mohindergarh	2,29,933	1,864
Jind	4,02,013	8,468
Total:—	71,85,504	3,89,544

(d) District-wise consumption of liquor during 1972-73 in bottles:—

Name of District	Country Liquor	Indian made Foreign Liquor
Hissar	25,66,184	1,31,716
Rohtak	23,55,656	1,33,972
Gurgaon	21,91,973	2,47,696
Karnal	22,69,427	1,29,360
Ambala	18,66,666	4,30,452
Mohindergarh	(Dry)	(Dry)
Jind	7,71,344	23,872
Total:—	1,20,21,250	10,97,068

चौधरी शिव राम वर्मा : मन्त्री महोदय ने सवाल के जवाब में बताया .है कि 31 मार्च 1968 को 240 देसी शराब की दुकानें थीं और अब 30 नवम्बर 1973 को वे 358 दुकानें हो गई हैं, दूसरी ओर अंग्रेजी शराब की दुकानें 1968 में 61 थीं और अब 288 हो गई है यानी देसी शराब की दुकानें पहले से डेढ गुना से भी ज्यादा हो सई हैं और अंग्रेजी की लगभग 5 गुना हो गई है इस तरह दुकानों के बढने से हरियाणा के अन्दर शराब की खपत ज्यादा हो गई है । क्या इससे चरित्र गिरता नहीं जा रहा है?

Mr. Speaker : It is not a supplementary. Please put a supplementary question.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि 1974– 75 में और कितनी शराब को दुकानें खोलने की योजना है?

Shri Shyam Chand : That depends upon the demand of the people.

मलिक सतराम दास बत्तरा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस वर्ष ऐडलटैशन के कितने कितने पकड़े गये हैं? क्या यह दुरुस्त है कि जब पुलिस केस पकड़ने लगती है तो आपका डिपार्टमैंट दखलअन्दाजी करता है?

Shri Shyam Chand : This is not the fact.

श्री अमर सिंह : मन्त्री महोदय ने अभी सवाल के जवाब में बताया है कि 1967– 68 में 71,85, 504 देसी शराब की बोतलें और 3,89, 544 अंग्रेजी शराब की बोतलें बेची गई । इसके मुकाबले में 1972– 73 में देसी शराब की 1, 20, 21, 250 बोतले बेची गई और अग्रेजी शराब को 10, 97,068 बेची गई । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि 1967– 68 के मुकाबले में 1972– 73 में यह तादाद बढ़ने का क्या कारण है?

Shri Shyam Chand : There are so many factors. First is the increase in population. Secondly, there is increase in the number of ex-servicemen. Then, there is great demand from the people because of good quality stuff and great rush of tourists in the State. Because of these we have abolished the monopolistic tendency in the liquor trade. We have liberalised our policy also.

चौधरी दल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि वजीर साहबान को भी कछ कोटा मिलता है ?

श्री श्याम : मैं तो पीता नहीं, अगर चौधरी दल सिंह जी ने पीनी हो तो इनको दिलवा देंगे । (हंसी)

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा में ज्यादा शराब पीने के कारण लोगों का चरित्र खराब हो गया है ? क्या इसे कम करने की कोशिश की जाएगी?

Mr. Speaker : It is not a supplementary. It is a matter of opinion.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वजीर साहब बताएंगे कि अगले साल में कोई शराब का नया कारखाना खोलने का विचार है ताकि इस अमृत से लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके?

श्री श्याम चन्द : यह अण्डर कन्सिड़ेशन है ।

श्री हरि सिंह : क्या वजीर साहब वताने की कृपा करेंगे कि शराब के नशे में और अफीम के नशे में क्या फर्क है?

श्री श्याम चन्द : वह तो मैंबर साहब खुद इस्तेमाल कर के देख ले ।

चौधरी शिव राम बर्मा : क्या वजीर साहब बताएंगे कि शराब के बारे में जो महात्मा गांधी जी की शिक्षा थी, उस पर अमल करेंगे?

Shri Shyam Chand : I have already clarified the policy of my Government. Now, we have taken up this matter with the Prohibition Council also. It was decided there that prohibition can be imposed only where prohibition is in force in the neighbouring States. If there is no prohibition in the neighbouring States, we will not succeed. We did not experiment like other States and commit the same Mistake. If the neighbouring States are not dry, we cannot go dry.

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या वजीर साहब बताएंगे कि जैसे शहरों में अंग्रेजी शराब की दुकाने हैं ऐसी दुकानें खोलने का वे देहातों में भी लाईसंस दे सकते है?

श्री श्याम चन्द : हां जी, जहां डिमांड होगी हम दे देंगे ।

Indira Gandhi Canal

***586. Shri Behari La1 Balmiki :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the total length of Indira Gandhi Canal together with the area through which it passes;

(b) the total expenditure incurred on the construction of the said canal together with the total area of land irrigated by it during the years 1971,1972 and 1973, separately;

(c) the sources from which the water is obtained in this canal, and;

(d) the time by which it is likely to become perennial ?

State Minister for Irrigation & power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) About 325 miles. Feeder passes through Rohtak District but the canal system passes through Bhiwani District.

(b) Rs. 1166.50 lakhs (upto 30/9/1973).

Area Irrigated

Year 1971 4298 Acres.

Year 1972	13433 Acres.
Year 1973 (booked up to 15/12/73)	24,000 Acres.

(c) Surplus water available in River Jumuna at Tajewala and flood water of Drain No. 8.

(d) The supplies will be made perennial when Haryana gets its share in the Ravi-Beas surplus waters.

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मत्री महोदय बताएंगे कि यह कैनाल कहां से शुरू हो कर कहां पर खत्म होती हे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब नाई नाला आगे जाकर ड्रेन नम्बर 8 बनता है । ड्रेन नम्बर 8 और भालोट सब–ब्रांच जहां मिलती है वहां–वहां ऊपर से इन्दिरा गांधी कैनाल बनती है ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि रूल्ज के मुताबिक पानी कब तक मिल जाएगा और जो रावी ब्यास का पानी है वह कब तक मिलने की सम्भावना है ।

सरदार हरमोहिन्द्र सिह चट्ठा : जब रावी ब्यास का पानी मिला, उस से पहले हमारा सिस्टम तैयार होगा और वह पानी मिलते ही नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा ।

College for Women

***601. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Education he pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a College for Women at Jind in the near future, if so, when?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : नही ।

चौधरी दल सिंह : क्या मिनिस्टर साहिबा बताएंगी कि वे खुद औरत होते हुए औरतों के कालेज खोलने से क्यों नफरत करती है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : इस में नफरत की बात नहीं है । वहां पर गवर्नमैंट कालेज में को–एजुकेशन है और उस के इलावा दो प्राईवेट कालेज हैं जिन में एक लड़कियों का कालेज है । इस लिए कोई नया कालेज खोलने की जरूरत नहीं है ।

चौधरी दल सिंह : क्या वजीर साहिबा बताएंगी कि जो यहां पर हिन्दू कालेज फार गर्ल्ज है वह अगर दरखास्त दे तो गवनमेट उस को लेने के लिए तैयार होगी?

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक) : स्पीकर साहब, उनकी कोई दरखास्त नही आई है । दरखास्त आने के बाद ही गौर किया जा सकता है ।

श्री के. एन. गुलाटी : क्या हायर सैकड्री स्कूलों को इन्टर और डिगरी कालेज बनाने को कोई योजना है?

श्री माडू सिंह मलिक : नहीं जी, ऐसी कोई योजना नहीं है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : चौधरी दल सिंह जी ने जो दोनों सवाल पूछे हैं उन का दोनों महिला मिनिस्टरों ने 'न' में ही जवाब दिया है । क्या मैं पूछ सकता .हूं कि इसकी क्या वजह है?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए यह सप्लीमैंटरी नहीं बनता ।

श्री हरि सिंह : स्पीकर साहब, सम्भालका कान्स्टीच्यूएंसी में लोग खेतीबाड़ी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, क्या वहां पर सरकार कोई एग्रीक्लचर कालेज खोलने की कृपा करेगी?

श्री माडु सिंह मलिक : यह सवाल तो इस से पैदा नही होता ।

श्री अमर सिंह : वजीर साहब ने यह बताया था कि हिन्दू कालेज फार विमैन को तरफ से मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई, लेकिन नेहरू कालेज हांसी ने एप्लीकेशन दे रखी है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे उस कालेज को लेने के लिए तैयार हैं?

श्री माडू सिंह मलिक : यह बात मेरे नोटिस में नही है ।

चौधरी दल सिंह : क्या वजीर साहब बताएंगे कि हरियाणा प्रान्त में सन् 1974–75 में कोई विमैन कालेज खोला जाएगा?

श्री माड़ सिंह मलिक : जी नहीं ।

Shri Shyam Chand : I have already clarified the policy of my Government. Now, we have taken up this matter with the Prohibition Council also. It was decided there that prohibition can be imposed only where prohibition is in force in the neighbouring States. If there is no prohibition in the neighbouring States, we will not succeed. We did not experiment like other States and commit the same Mistake. If the neighbouring States are not dry, we cannot go dry.

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Mobile Dispensaries

***677 Chaudhri Mehar Chand :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

a) the total number of mobile dispensaries which are functioning in the State as on 1st July. 1973;

b) the number of villages which fall in the beat of dispensaries as referred to in part (a) above; and

c) whether the Government intends to increase such mobile dispensaries ?

गृह एंव स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(ए) 3

(बी) एक वर्ष में एक डिस्पैंसरी लगभग 100 गावों को कवर करती है।

(सी) नहीं ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या वजीर साहिबा यह बताएंगी कि इन मोबाईल डिस्पैंसरीज ने जुलाई, 1973 से लेकर दिसम्बर 1973 तक जो काम किया है उस की तफसील क्या है?

श्रीमती शारदा रानी : जुलाई 73 से दिसम्बर 1 973 तक की तफसील तो सवाल में मांगी नहीं गई थी लेकिन अब तक की जो टोटल तफसील है वह दी जा सकती है । 1 जनवरी 1971 से पहले 700 गांव गुडगावा में कवर किए, भिवानी में 12. 71 से 147 गांव कवर किए, इसी तरह नारनौल में 10.3.75 से 29 गाव कवर किए और जो नम्बर आफ बैनीफिशरीज 1971 में थे उनकी डिटेल इस तरह है रू–

1971 :	गुड़गांव	5090
	भिवानी	5810

नारनौल 7721 (जबकि मौबाईल डिस्पैंसरी

रोहतक में थी)

1972 गुड़गांव 2,000

भिवानी 3,074

नारनौल 8,321 (जबकि यह डिस्पैंसरी रोहतक

में थी)

1973 गुडगांव 5,800

भिवानी 8,417

नारनौल 9,203

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या वजीर साहिबा बताएंगी कि वह मोबाईल डिसपैंसरी रोहतक से नारनौल क्यों चली गई?

श्रीमती शारदा रानी : रोहतक में बहुत बड़ा मोबाईल, हास्पिटल चितरन्जन मोबाईल हास्पिटल खोल दिया गया है, यह तो एक मौबाईल डिस्पैसरी ही थी जो नारनौल भेजी गई है ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या वजीर साहिबा बताएंगी कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में मोबाईल डिस्पैसरी क्यों नहीं खोली गई? इ सके इलावा यह भी बताने को कृपा करें कि जो इस वक्त मौबाईल डिस्पैसरीज हैं क्या वे सभी फुली इक्विपड है?

श्रीमती शारदा रानीः हिसार डिस्ट्रिक्ट ही केवल ऐसा जिला नहीं हैं बल्कि और भी बहुत से जिले है जहां पर मोबाईल डिस्पैसरी नहीं हैं । जहां तक इक्विप होने का सवाल है शायद एक आध वैकैसौ कहीं हो वर्ना जितना प्रोविजन इक्विप करने के लिए रखा था, उतनी वे इक्विपड हैं ।

चौधरी दल सिंह : क्या वजीर साहिबा बताएंगी कि 1974– 75 मैं आपकी कहीं मौबाईल डिस्पैसरी खोलने की तजवीज हैं ।

श्रीमती शारदा रानी : जी नहीं, इस वक्त कोई प्रोपोजल नहीं है ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वजीर साहिबा बताएगी कि जुलाई 1973 के बाद भी कोई मोबाईल डिस्पैसरी खोली गई हूं?

श्री मती शारदा रानी : स्पीकर साहब 10.3.73 के वाद को ई डिस्पैसरी नहीं खोली गई ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहिबा बताएंगी कि वे कौन से सात जिले हैं जहां पर मोबाईल डिस्पैसरीज नहीं है?

श्रीमती शारदा रानी : गुड़गांव, भिवानी, नारनौल और रोहतक को छोड कर बाकी सब जगह नहीं है ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि यह जो उन्होंने तीन मोबाईल डिस्पैसरीज बताई हैं क्या इ न में लेबर मोबाईल डिस्पैसरी भी शामिल है या नहीं?

श्रीमती शारदा रानी : लेवर की तो कोई नहीं पूछी गई है । जो यह डिस्पैसरीज हैं वह सभी के लिए हैं ।

चौधरी फूलसिंह कटारिया : क्या वजीर साहिबा बताएंगी कि यह जो रोहतक के लिए डिस्पैसरी बनी है क्या यह झज्जर तहसील को भी कवर करती है?

श्रीमती शारदा रानी : वह पूरा हस्पताल है और पूरे जिले को कवर करता है और अलग–अलग जगह में जा कर कैम्पस लगाते हैं और अगर आप कहेंगे तो झज्जर में भी कैम्प लगवा देंगे ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या वजीर साहिबा बताएंगी कि मोरनी हिल्ज में भी यह स्कीम थी कि वहां पर भी यह चलाई जाएगी? तो क्या वह स्कीम है या नही है और अगर है तो कब तक चालू होगी?

श्रीमती शारदा रानी : मुझे तो पता नही कि वहां के लिए ऐसी कोई स्कीम थी भी या नही थी ।

श्री अमर सिंह : क्या वजीर साहिबा बताएंगी कि इन मोबाईल डिस्पैसरीज के स्टाफ और मैडीसज पर सालाना कितना खर्चा पड़ता है?

श्रीमती शारदा रानी : खर्च के बारे में तो सवाल में पूछा नहीं गया है इस के लिए सैपेरेट नोटिस दे तो बता देंगे ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहिबा बताएंगी कि जब तक हमारे इन सात जिलों में यह मोबाईल डिस्पैसरिया नहीं खोली जातीं तब तक इस अर्सा के लिए यह डिपैंसरीज वहां पर भी भेजी जायेंगी?

श्रीमती शारदा रानी : वहां कुरूक्षेत्र में कहेंगे तो इन में से भेजदेंगे लेकिन इसके वहां भेजने का कोई लाभ नहीं है ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या वजीर साहिबा बतायेगी कि यह जो तीन डिस्पैसरिया जहां खोली गई, वहां ही खोलने का क्या रीजन है और दूसरे जिलों में क्यों नहीं खोली गई और उनके न खोलने की क्या वजह है?

श्रीमती शारदा रानी : यह बैकवर्ड इलाके थे, कहीं पर रेत ज्यादा था और कहीं पर पानी ज्यादा था ।

Bunds

***693. Chaudhri Surjit Singh Mann :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number and the location of bunds constructed in the State by the Government from 1st November, 1966 to-date to check soil erosion and to provide basin irrigation; and

(b) the area likely to be irrigated by these bunds ?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chadha)

(a) 25 Bunds.

Districts	No. of Bunds
Bhiwani	2
Mohindergah	12
Gurgaon	11

(b) 26,218 Acres.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वजीर साहब बताएंगे कि हरियाणा में और कितने ऐसे स्थान हैं जहां पर बांध बनाने की योजना हे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां–वहां जरूर बनाए जायेंगे ।

चौधरी सुरजीत सिंह मान : क्या वजीर साहब बताएंगे कि हरियाणा में सायलइरोजन को रोकने के लिए क्या स्टैप्स उठाए जा रहे हैं ।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : हर साल बारिशें आने से पहले और बाद देखा जाता है कि कहां–कहां सायल इरोजन का डर है और जहां डर हो वहां बांध बनाने की कोई न कोई योजना बनाई जाती है ।

श्री बिहारी लाल बाल्मीकि : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि मेरे हलका हसनपुर में मुरतजबाद और मोहोली के गांवों में दरिया जमना से काट हो रही है और इस बारे में लोगों ने डी० सी० को दरखास्ते भी भेजी हैं, तो क्या वहां पर कोई बांध बनाने की योजना है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिह चट्ठा : इन दोनों गावों को नुक्सान नहीं होने देंगे ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या वजीर साहब बताएंगे कि हमारे नारायणगड़ में टांगरी और मारकंड़ा से बहुत सायल इरोजन हो गया है तो क्या वहां पर अगली बरसात से पहले बांध बना देंगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : जरूर कोशिश की जायेगी ।

Chaudhri Mehar Chand : May I know from the Hon'. Minister the position of soil erosion in the State as a whole i. e. how much_ area is affected by soil erosion in the State ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, हर साल बारिशों की इनटैसिटी पर डिपंडं करता है । अगर बारिशे ज्यादा आज्गी तो इरोजन ज्यादा होता है और अगर बारिशें कम आती हैं तो कम होता है । इस लिए कोई डैफिनिट फिगज इस बारे मे नही है जा सकती हैं ।

लाला रुलिया राम : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जो बड़ी जमना है उस से हरियाणा की बहुत जमीन कटती जाती है और बहां पर बांध बनाने की बहुत जरूरत ह क्यसा वहां पर बांध लगाया जाएगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिह चट्ठा : जहा–जहां जरूरत हैं वहां पर लगाए जाएंगे और जहां जरूरत थी वहां लगाए भी गए है ।

Live Stock-Farm Hissar

***699. Diwan Hans Raj Suri :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state -

(a) the total number of milch cattle in the Government Livestock Farm, Hissar, as on 1st April, 1972 and as on 1st April, 1973, separately ; and

(b) the steps, if any, taken to further increase the production of milk in the said Farm ?

कृषि मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

क) (i) 1– 4– 1972 को 1996 ।

(ii) 1–4– 1975 को 1965 ।

ख) इस विभाग ने आस्ट्रलिया से आयात किए गए तीन जर्सी सांड और 90 बहडियों के साथ खालस जर्सी गायों को ब्रीडिंग का कार्यक्रम शुरू किया है । इसके अतिरिक्त हरियाणा तथा थारपारकर गायों का जर्सी साडो के साथ कासब्रीडिंग का कार्यकम आरम्भ किया गया है । इसके साथ ही संतती परीक्षण स्कीम के अन्तर्गत प्रोवन सांडों का विस्तृत रूप से प्रयोग करके हरियाणा तथा मुर्राह झुण्ड में दूध की पैदावार मे बढ़ोतरी की जा रही है ।

श्री अमर सिंह : क्या वजीर साहब बताएंगे कि क्या यह हकीकत है कि कास ब्रीडिंग से दूध बढता हँ और नसल बिगड़ती हे?

चौधरी भजन लाल : क्रास ब्रीडिंग से नसल भी सुधरती है और दूध भी बढ़ता है ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वजीर साहब बताएंगे कि इस फार्म से सालाना आमदनी और खर्च कितना–कितना होता है?

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमैंटरी क्वैश्चन इस से पैदा नहीं होता ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या वजीर साहब बताएंगे कि उन्होंने जो मिल्च कैटल के फिगर दिये हैं उन में गायें कितनी हैं और भैस कितनी ह?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस में ऐसा है कि दूध देने वाले पशुओं की तादाद 1– 4– 72 को गाये 877 और भैंसें 248 और कुल तादाद 1125, 1– 4– 73 को यह तादाद गायें 822 और भैंसें 233 और कुल तादाद 1055 थी ।

चौधरी दल सिंह : क्या वजीर साहब बताएंगे कि यह जो दुधाक पशु हैं इन से इस अर्सा में सालाना कितनी आमदनी हुई है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम ने साल में चालीस लाख रुपये के करीब का दूध और पशु बेचे हैं ।

चौधरी पोर चन्द : क्या वजीर साहब बताएंगे कि हिसार में कितना दूध रोजाना तैयार होता है और उसके बेचने का क्या प्रबन्ध किया हुआ है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 1972– 73 में हिसार फार्म में 16,16,575 लिटर दूध बना और जहां तक बेचने का सवाल है यह को–आपरेटिव सोसाईटीज के थ्रू तकसीम करते हैं

। इस के लिए टैडंर मांगे जाते हैं और जो लोयस्ट टैंडर होता है और जिसका ठीक होता है उसे तकसीम करने का काम देते हैं ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि को–आपरेटिव सोसाइटीज की मारफत ही यह मिल्क डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, डायरैक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है और डायरैक्ट करने में क्या हर्ज है ?

चोधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक तकसीम करने की बात है मैं जहां तक समझता हूं इन्डिविजुअल आदमियों की बजाये को–आपरेटिव सोसाइटीज ठीक काम करती हैं और यह काम ठीक चल भी रहा है ।

मलिक सतराम दास बत्तरा : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि मुर्राह नसल की भैसों पर और हरियाणा नसल कि गायों पर स्टेट से बाहर जाने पर पाबंदी लगाने का विचार सरकार रखती है ताकि यह बाहर न जा सके?

चौधरी भजन लाल : जहां तक पाबंदी लगाने का सम्बन्ध है यह पाबंदी प्रांतीय सरकार नही लगा सकती है, भारत सरकार से पूछ कर ही लगानी पड़ती है । इस वक्त ऐसी कोई स्कीम जेरे गौर नहीं और ऐसा कोई विचार नहीं कि पांबदी लगाई जाय ।

चौधरी पोर चन्द : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि आज सोसायटीज की मारफत दूध अच्छी तरह से तकसीम नहीं होता है

और इस बात की शिकायतें आती हैं तो इसके बारे में क्या प्रबन्ध किया गया हे?

चौधरी भजन लाल : हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है अगर मैंबर साहब के पास आई हो तो उसे हमारे पास भेजें, हम इन्कवायरी करायेंगे और अगर गलती पाई गई कि ठीक तरह से काम कहीं होता है तो सजा देने की पूरी कोशिश करेंगे ।

चौधरी दल सिह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इस फार्म में अधिक से अधिक कोई गाय कितना दूध रोजाना देती हे?

चौधरी भजन लाल : वहां अलग–अलग नसल को गायें हैं और अलग–अलग मिकदार में दूध देती हैं । हरियाणा नसल की गाय औसत दूध रोजाना देती है चार किलो, साहीवाल नसल की गाय की औसत पड़ती है सात किलो, थारपारकर नसल की गाय की औसत है पांच प्वायंट सात किलो और सबसे अच्छी जो जरसी नसल की गाय है उसकी असित सात प्वायंट सात किलो है ।

राव बंसी सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि अच्छी जो सबसे नसल उन्होंने जरसी की बताई है उसकी बछिया को इन्डिविजअल बेसिज पर किस तरह से देते है ।

चौधरी भजन लाल : उनकी बछडी इन्डिविजुअल बेसिज पर किसी को नहीं देते हैं । एक कमेटी बनाई हुई है और वह

कमेटी देखती है कि अगर कोई बछिया जो थोडी सी कास ब्रीडिंग के हिसाब से ठीक न बैठती हो उसे नीलाम करते हैं । इसी तरह से गाय भी जिसके थन चढ़ जाते है दूध देना कम कर देती है उसे भी नीलाम कर देते हैं ।

चौधरी मेहर चन्द : स्पीकर साहब, दूध का डिस्ट्रिब्यूशन को–आप्रेटिव सोसायटियों के थ्रु होता है । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि दूध खरीदते समय कंज्यूमर्ज को ज्यादा पैसे नही देने पड़ते?

चौधरी भजन लाल : 6 पैसे लिटर तो को–आप्रेटिव सोसायटियों का कमिशन है । फामं में 1. 19 पैसे प्रति लिटर रेट रखा हुआ है । कंज्यूमर तक पहुंचने में यह 1.25 पैसे पड़ता है क्योंकि ह पैसे पर–लिटर उनका कमिशन है ।

लाला रुलिया राम : स्पीकर साहब यहां से जो पशु यू ० पी० भेजे जाते ढँ' उनमें से बहुत सारे पशु दूध दैने वाले होते हैं । क्या मन्त्री महोदय दूध देने वाले पशुओं पर पाबन्दी लगाने पर विचार करेंगे?

चौधरी भजन लाल : पाबन्दी भारत सरकार लगाती है, हम नहीं लगा सकते । भारत सरकार से पूछ कर लगानी पड़ती है मगर अभी ऐसा विचार सरकार का नहीं है ।

Schools

***703. Shri Jagjit Singh Tikka :** Will the Minister for

education be pleased to state—

(a) the district-wise total number of Middle and High/Higher Secondary Schools which existed in the State as on 1st May, 1968 and as on 31st December, 1973; separately; and

(b) the district-wise total number of the Primary Schools likely to be upgraded to Middle Schools and Middle Schools to High/ . Higher Secondary Schools during the next financial year i. e. 1974-75 ?

शिक्षा एव परिवहन राज्य मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : (क) सूची सभा–पटल पर रखी जाती है ।

(ख) कोई नहीं ।

सूची

Sr. No.	Name of the District	No. of Schools as on 1-5-1968		No. of as on 31-12-1973 Schools	
		Middle	High/Higher Sec.	Middle	High/Hr. Sec.
1 .	Ambala	78	102	84	133
2 .	Gurgaon	125	115	80	137
3 .	Hissar	152	123	144	136

4.	Jind	46	32	52	72
5	Karnal	118	126	60	106
6.	Mohindergarh	80	57	83	91
7.	Rohtak	148	158	74	160
	Total	747	713		
8.	Bhiwani	These three Districts		74	103
9.	Kurukshetra	came into existence only in the		59	81
10.	Sonepat	year 1972-73		69	79
				779	1098

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इनमें प्राईवेट स्कूल कितने हैं और सरकारी कितने हूं?

शिक्षा मन्त्री (श्री माडु सिंह मलिक) : स्पीकर साहब, यह पूछा ही नही गया, जो पूछा गया था उसका जवाब दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष : इन्फर्मेशन गवर्नमैंट स्कूलों की थी या टोटल ?

श्री माडू सिंह मलिक : टोटल पूछी थी ।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जितने स्कूल स्टेट में चल रहे हैं, क्या इनमें स्टाफ पूरा है या कम, अगर कम है तो कितना?

श्री माडू सिंह मलिक : स्टाफ के 'बारे में सवाल ही पैदा नहीं होता

चौधरी मेहरचन्द : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने सवाल के पार्ट (दी) का जवाब दिया है ' 'नन'' । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या वह शुभ घड़ी आएगी जब यह काम शुरू होगा?

श्री माडू सिंह मलिक : जरूर आएगी ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो प्राईवेट स्कूल खोले हैं, उनको लेने की तजवीज है?

श्री माडू सिंह मलिक : नहीं ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि 1 मई, 1968 को गवर्नमैंट और प्राईवेट स्कूल कितने–कितने थे?

श्री माडू सिंह मलिक : नाटिस दें तो बता दिया जाएगा ।

Development Plans

***708 Shri Girish Chander Joshi :** Will the Minister for Social Welfare & Taxation be pleased to state—

(a) whether the Government has prepared any Development Plan for any towns in the State

(b) if so, the names of such towns for which the plans have been prepared during the period from 1-1.1968 to 31-12-1973 ; and

(c) the steps, if any, so far taken to execute the said plans ?

Social Welfare and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) :

(a) Yes Sir,

(b) A statement is laid on the table of the House.

(c) Both regulatory and positive steps are being taken to execute the plans. On the regulatory side, it is being ensured that no construction which violates the provisions of the Development Plan comes up. On the opposite side, the land is being acquired, developed and sold in conformity with the provisions of the Development Plan.

Statement

The Development Plans of the following towns have been prepared during the period from 1-1-1968 to 31-12-1973 :-

District Sonepat	1.	Sonepat
	2.	Kamla Nehru Shiksha Kender, Rai

	3.	Murthal
	4.	Ganaur
District Kurukshetra	5.	Kurukshetra
	6.	Shahabad
	7.	Kaithal
District Karnal	8.	Karnal
	9.	Panipat
District Gurgaon	10.	Gurgaon
District Hissar	11.	Hissar
	12.	Fatehabad
District Rohtak	13.	Rohtak
	14.	Bahadurgarh
District Ambala	15.	Ambala Cantt.
District Jind	16.	Jind
District Bhiwani	17.	Bhiwani

Shri Girish Chander Joshi : May I know from the Hon. Minister as to, on the positive side, what are the places where land is being acquired, developed and sold ?

Shri Shyam Chand There is a plan to develop the important towns of the State. We acquire the land, develop it and sell it out.

श्री के ० एन० गुलाटी : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि मास्टर प्लान में और डिवैल्पमैंट प्लान में क्या फर्क है और ये कहां–कहां चल रही हैं?

Shri Shyam Chand : The Master plan is with a view to develop the entire cities in the State and that is a long term plan covering all the cities for a maximum period of 20 to 30 years.

Starred Question No. 692.

As the hon. Member was not present in the House, this question was not put.

Dacoity Cases

***546 Chaudhri Ram Lal Wadhwa** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) the district-wise total number of dacoities committed in the State during the year 1973; and

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above, which have been detected so far ?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(ए) वर्ष 1973 में डकैती के कुल 5 मामले दर्ज हुए वे, जिन में से एक जिला रोहतक, एक गुड़गावां, एक नारनौल, एक जीन्द और एक सोनीपत का था ।

(बी) इन 5 डकैतियों में से 4 डकैतियों में सफलता प्राप्त हो चुकी है और बाकी एक केस जो कि नारनोल जिले का है अभी ट्रेस नहीं हुआ जिस में तफतीश जारी है ।

चौधरी शभ लाल वधवा : क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि जो केस बरामद हुए हैं, क्या इनमें खुद का माल भी बरामद हुआ है?

श्रीमती शारदा रानी : जी हां, ट्रेस करने का यही मतलब है ।

Mini Secretariat at Jind

***631. Shri Dhaja Ram :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Mini Secretariat at Jind; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) : Yes, it will be known as the District Administrative Centre and Judicial Complex. It is not possible at this stage to indicate the time by which it is likely to be completed, as that depends on the availability of funds.

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, मली महोदय ने बताया कि यह नहीं वता सकते कि कब तक मुकम्मल हो जाएगा । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसको शुरू कब करवाएंगे और क्या इसके लिए जमीन एक्वायर हो चुकी हूँ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : I have already submitted that it all depends upon the availability of funds. Judicial complex and Mini Secretariats are already in progress in Hissar and Gurgaon districts and shortly we are going to begin construction of such centres in Sonepat, Kurukshetra and Bhiwani.

श्री धजा राम : स्पीकर साहब, जींद एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है । वहां पर पी ० डबल्वू ० डी० का आफिस कहीं है, इरीगेशन का कहीं है, यानी दफ्तर इकट्ठे नहीं हैं इसलिए लोगों को बड़ी दिक्कत होती है । जब यह डिस्ट्रिक्ट बना था तो मिनी–सैक्रेटेरिएट बनाने का वायदा किया गया था । मेरा मतलब यह है कि क्या जींद जिला को सोनीपत से पहले मिनी–सैकेटेरिएट बनाने की प्रायरिटी दी' जाएगी?

Pandit Chiranji Lai Sharma : No. The question of giving priority to Jind does not arise. It is not a new district. It is an old district and accomodation for offices is available in Jind as compared with these three new districts .

चौधरी पीर चन्द : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हिसार में जो बिल्डिंग बन रही है, वह कब तक मुकम्मल हो जाएगी?

Pandit Chiranji Lal Sharma : It is nearing completion. So far as the judicial complex is concerned, it has already been inaugurated by the Governor.

चौधरी पीर चन्दः हिन्दी में बता दीजिए ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : हिसार का जुडिशियल कम्पलैक्स कमप्लीट हो चुका है और पिछले महीने की 16 तारीख को गवर्नर महोदय ने उसकी इन–आगुरेशन की है ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब, जींद जूनियर और रोहतक सबसे सीनियर जिला है इसीलए सबसे पहले रोहतक में बनना चाहिए ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : I fail to understand as to what the hon. Member means by seniority and juniority in districts.

श्री ओम प्रकाश गर्ग : मंत्री महोदय ने बताया है कि सोनीपत, कुरुक्षेत्र और भिवानी में मिनी–सैक्रेटेरिएट बनाये जाएंगे?

मुख्य मन्त्री (चौधरी बंसी लाल) : नये जिलों में पहले कुरूक्षेत्र में काम शुरू होगा ।

Cattle Feed Plant

***644. Shri Om Parkash Garg :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether the Haryana Agro-Industries Corporation has set up any 'Modern Cattle Feed Plant' in the State, if so, the place where such Plant has been set up;

(b) the total production capacity of the said Plant per hour; and

(c) whether there is any scheme under

consideration of the Government to set up 'Poultry Feed Plant' in the State, if so, the location of the Plant ?

कृषि मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(ए) जी हां, जीन्द में ।

(बी) पांच टन प्रति घण्टा ।

(सी) जी नहीं ।

चौधरी दल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जींद में जो कैटल फीड प्लांट लगाया है उस पर कितना खर्चा हुआ है ?

चौधरी भजन लाल : 45 लाख रुपया खर्च आयेगा ।

श्री ओमप्रकाश गर्ग : कया मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह प्लाट कब से चालू हुआ है?

चौधरी भजन लाल : यह इसी साल मार्च से पहले पहले चालू हो जायेगा ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसकी सालाना कितनी कपैसिटी होगी?

चौधरी भजन लाल : 30 हजार टन की होगी ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मंत्री महोदय कैटल फीड प्लाट दूसरे जिलो में खोलने का भी विचार रखते हैं?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी नहीं ।

चौधरी पीर चन्द : हिसार में दूध बहुत ज्यादा होता है । क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वहां पर भी कोई घी वगैरा बनाने की स्कीम चालू करने का विचार है?

चौधरी भजन लाल : हिसार में मिल्क प्लांट लगाने जा रहे हैं ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जीद को क्यों सिलैक्ट किया गया?

चौधरी भजन लाल : वहां पर मिल्क प्लांट पहले से लगा हुआ है इसलिए छांटा गया और इसके अलावा जींद, रोहतक, हिसार में दूध देने वाले पशु अच्छे और ज्यादा हैं । इस हिसाब से भी जींद बीच में पड़ता है ।

Construction of Bridges

***662. Chaudhri Ishwar Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of major bridges constructed over rivers and canals in the State during the period from 1st May, 1968 to December, 1973 ?

State Minister for In igation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : Two major bridges have been constructed on rivers and none on canals.

Bus Service

***668. Chaudhri Phul Singh Kataria :** Will the Minister for Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide bus service from Rewari to Haridwar via Jhajjar-Sonepat ?

शिक्षा एंव परिवहन राज्य मत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): रिवाड़ी–हरिद्वार एक अन्तर–राज्य मार्ग है । इस मार्ग पर बस सेवा उपलब्ध करने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करने का प्रस्ताव है ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि कब तक इसका फैसला हो जाएगा और कब तक यह बस चलने लग जाएगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी । जय बातचीत कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद चालू कर दी जाएगी ।

श्री अमर सिंह : क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि हिसार से हरिद्वार वाया हांसी कोई बस चलाने का मामला अन्डर कंसिड्रेशन है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : जी नहीं ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : स्पीकर साहब, कुरूक्षेत्र में नया जिला बनने के कारण रश बहुत बढ़ गया है । क्या मंत्री महोदया

बताने की कृपा करेगी कि वहां बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : सभी जगह जहां–जहां भीड़ महसूस होती है, बसे चलाने की कोशिश की जा रहो है ।

श्री गुलाब सिंह जैन : क्या मंत्री महोदया इस तजवीज पर कि जब तक हिसार से हरिद्वार के लिए नई बस शुरू नहीं होती तब तक रोहतक से हरिद्वार चलने वाली बस को ही हिसार वाया रोहतक चालू करने पर विचार करेंगी?

परिवहन मंत्री (कवल महा सिंह) : स्पीकर साहब, रोहतक से भी हरिद्वार को कोई बस नहीं चलती ।

श्री के० एन० गुलाटी : स्पीकर साहब, हरियाणा के लगभग सभी स्थानों से चंडीगढ़ को बसें आती और जाती हैं । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद से चंडीगढ़ को भी एक बस देंगे?

Mr. Speaker : The Question Hour is over.

दी हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन बिल, 1974

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation Bill, 1974.

I also beg to move—

That the Haryana Appropriation Bill be taken into

Consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question Is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

The Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital) ; I beg to move—

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

The motion was carried.

वर्ष 1974–75 के बजट पर सामान्य चर्चा

चौधरी दल सिंह (जींद) : माननीय स्पीकर साहब, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट 10 तारीख को प्रस्तुत किया, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण 'के पेज एक पर ठीक ही लिखा हे कि हरियाणा की इकोनोमी, आर्थिक व्यवस्था जो है वह खेती पर निर्भर करती हे । इसमें कोई दो राय नहीं होसकतों । मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी अपने विचार रखे थे उस रोज समय के अभाव के कारण स्पीकर साहब, जो बातें मैं कह नहीं सका था उन बातों की तरफ आख मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इससे पहले कि मैं कोई बात शुरू करूं, स्पीकर साहब, यह बात देखने में आई है कि विरोधी दल का कोई सदस्य चाहे कोई बात ठीक ही क्यों न कहे लेकिन हमारे शासक दल के भाई उस बात को पसन्द नही करते और आम तौर पर उसे उलट सिद्ध करके झुठलाने की कोशिश करते हैं और अपनी ही बात को ठीक सिद्ध करने को कोशिश करते हैं । जहां तक स्पीकर साहब, मैं समझता हूं यदि हरियाणा की उन्नति होती है तो लाजमि तौर पर उसका हमें गर्व होता है और यदि गलत काम होते हैं तो लाजमी तौर पर उसका असर भी हरियाणा की जनता के हर व्यक्ति पर और खास करके हम

नुंमायदो पर होता है. तो जहां तक अनाज की पैदावार के आंकड़ों का ताल्लुक है, हमारे वित्त मंत्री ने खुद ही वह बात कही है कि –

"Adverse weather conditions had resulted in a decline in foodgrains production in the State from 45.46 lakh tonnes in 1971-72 to 39. 43 lakh tonnes in 1972-73 ....."

स्पीकर साहब, इन्होने खुद ही इस बात को माना है कि अनाज के अन्दर कमी हुई हं । स्पीकर साहब, किसी व्यक्ति के काम की तुलना जिस प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति के काम से की जा सकती है उसी तरह किसी एक सरकार के काम की तुलना किसी दूसरी सरकार के काम से ही की जा सकती है । तो मैं आपका ध्यान सन् 67–68 की ओर दिलाना चाहता हूं जब हरियाणा प्रान्त के अन्दर विरोधी सरकार थी । यह तुलना करके स्पीकर साहब, मैं यह बताना चाहता हूं कि उस एक साल में जबकि विरोधी सरकार थी उस वक कितनी पैदावार थी और उरुके बाद मन् 68 से लेकर आज तक जब से लगातार यह सरकार है, कितनी पैदावार बढी है । वित्त मत्री महोदय मे स्वयं ही माना है कि राज्य में खाद्यान्न उत्पादन 1971– 72 के 45.46 लाख टन से घटकर 1972– 73 में 39.46 लाख टन रह गया सन् 1967– 68 में हरियाणा प्रान्त में 39. 70 लाख टन अनाज पैदा हुआ था और इनके अपने कद्रने के मुताबिक तथा स्टैटिस्टीकल ऐबस्टूंक्ट आफ हरियाणा 1972– 73 जो किताब इन्होने छापी है उसके मुताबिक सन् 1972– 73 में 39. 43 लाख टन अनाज पैदा हुआ तो चार साल में 27 हजार टन अनाज कम हुआ और कब हुआ जब इस हरियाणा के अन्दर

ट्यूबवैल्ज की तादाद लाखो बड़ी, जब हरियाणा के अन्दर करोडों रुपए नहरो पर खर्च हुए । लेकिन फिर भी हमारी सरकार ढिंढौरा पिटती है कि बडी भारी तरक्की हुई हूँ हरी क्रान्ति 'और सफेद कान्ति लाने जा रहइ हैं । ये कहानी यहां हाउस के सामने पेश होती है ।

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल) : इसमें चने के बारे में भी तो बता दो कितनी पैदावार हुई थी ।

चौधरी दल सिंह : इस बारे में आप बता देना । मैं स्पीकर साहब, यह बताना चाहता हूं कि कितने ट्यूबवैल्ज सरकार ने लगाए और उनके लगाने से कितनी पैदावार मैं बढौतरी हुई । मैं दूसरे पैदावार के आंकड़े भी पेश करना चाहना हूं कि हमारी कितनी पैदावार बढ़ी है । कितने साल के अन्दर कितनी पैदावार वढी है? सन् 1971 – 72 मे 45 लाख 46 हजार टन की पैदावार हुई है इसके मुकाबले मे सन् 1967– 68 मे 39 लाख 70 हजार टन को पैदावार हुई थीं । अब आप देखिए चार साल के अन्दर 5 लाख 76 हजार टन की बढौत्तरी हुई है । यह चार साल की बढौत्तरी है, इसका मतलब यह हु आ कि एक साल के अन्दर एक लाख 44 हजार टन की बढौत्तरी गई हुई । अब आप इ सका दूसरा पहलू भी देखिए । इस अर्से के अन्दर हरियाणा प्रान्त की सरकार कहती हूँ कि एक लाख 49 हजार 150 टयूबबैल्ज और पम्पिंग सैट्स लगाए । दूसरे इसी अर्से के अन्दर हरियाणा सरकार मे करोड़ों रुपया नहरों पर खर्च किया । स्पीकर साहब आप यह

बात सुन कर हैरान होंगे कि इसका यह मतलब हुआ कि एक ट्यूबवैल पर या ए क पम्पिंग सैट पर एक टन रो भी कम अनाज हुआ एक साल के अन्दर और फिर यह सरकार यह क्लेम करे कि हरियाणा ने पैदावार के अन्दर बड़ी भारी बढौतरी की है । यह बड़े अ.सोस की बात है कि ए क ट्यूबवैल पर एक टन भी अनाज यह सरकार पैदा नहीं कर सकी फिर ये दावा करते हैं कि हम यह कर रहे हैं वह कर रहे है । मे री तो समझ में नही आता है कि कौन सी इन की बात दरुस्त है मेरी तो समझ से बाहर है । जहां तक इनके सब्जबाग दिखाने का सम्बन्ध है, यह बात ठीक नहीं है । इन सा बातों से साफ मालूम है ' कि हरियाणा सरकार की पालिसी गलत है । यह सरकार अन–प्लांड ढंग से चली है जिसके कारण से ये कमियां बनीं । स्पीकर साहब इन्होंने क्या किया है? जहां कम पानी से ज्यादा पैदावार हो सकती थी वहां पर तो पानी दिया नही और जहां पर ज्यादा पानी देने से कम पैदावार हुई वहां पर ज्यादा पानी दिया । इसी तरह बिजली भी ज्यादा पैदावार वाले इलाकों में कम दी है, जिसका नतीजा यह हुआ कि हरियाणा प्रान्त में कम पैदावार हुई । इस सरकार ने इतने ट्यूबवैल्ज लगाए, नहरें चालू की, करोड़ों रुपया लगाया लेकिन फिर भी पैदावार नही बढ़ी तो मैं यह कहूंगा कि ये सरकार चलाने के भधिकारी नहीं हो सकते । यह बात इनके साफ ध्यान में आनी चाहिए ।

स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए इस सरकार का व्यान उस रकबे की तरफ भी दिलाना चाहना ह कि कितना रकबा

फूड–ग्रेन के तहत लाये है वे आकड़े भी मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं । सन् 1967– 68 मे फूड–ग्रे न सीरियल के तहत 3951 हजार हैक्टेयर रकबा काश्त किया गया जब कि सन् 1971 – 72 मे 395 ते हजार हैक्टेयर रकबा काश्त हुआ । इसके अन्दर चार हजार हैक्टेयर रकबा ज्यादा काश्त हुआ । ये चार साल के अन्दर चार हजार हैक्टेयर रकबा फालतू काश्त के लिए कर सकें, यह हालत कछ । अब आप आयल सीडज की पोजीशन देखिए । सन् 1967– 68 के अन्दर 212 हजार हैक्टेयर रकबा आयल सीड्ज के लिए काश्त किया जब कि सन् 1971– 72 के अन्दर 175 हजार हैक्टेयर रकबा काश्त हुआ । 37 हजार हैक्टेयर रकबा कम काश्त हुआ है । इसी तरह से शुगर कैन को लीजिए, उसमें भी सन् 1 967– 68 में 121 हजार हैक्टेयर रकबा शुगर कैन के लिए काश्त किया गया था जब कि सन् 1971– 72 में 114 हजार हैक्टेयर रकबा काश्त हुआ यानी सात हजार हैक्टेयर कम हु आ । जहां तक कपास का सम्बन्ध है वह 24 1– 241 हैक्टेग्ग्र रकबा दोनों सालों में काश्त हुआ है यानी बराबर– बराबर काश्त हुआ है । अब कौन सी बात ठीक हो सकती है । यह किस तरह से फख से कहते हैं कि बढौत्तरी हुई है । मैं तो यही समझता हूं कि या तो इनकी टेबल्ज में गलती है या इनकी अपरोच में गलती है या इनकी फिंगर्ज में कोई घोटाला है । कोई बात जरूर है । इसमें कोई शक और सन्देह वाली बात नहीं है । मेरी समझ में नही आता कि इतना करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी सरकार हरियाणा में अनाज की पैदावार को नहीं बढ़ा सकी तो इसका

मतलब यह हुआ कि इसमें बड़ी भारी खामियां हैं, इनकी अन–प्लैंड स्कीमें हैं ।

स्पीकर साहब एक बात और देखिए जिसके बारे में मैं अर्जकरना चाहता हूं । इन्होंने अनाज के सरकारीकरण के लिए कुछ बाते यहां कहीं पहली बात यह कही कि इस सरकारीकरण से पैदावार करने वाले को और कन्ज्यूमर, उपभोक्ता को ठीक कीमत पर अनाज मिलेगा हमने कहा कि बड़ी अच्छी बात है ऐसा होना चाहिए । दूसरी बात कही कि अनाज के सरकारीकरण से अनाज का भंडार किया जायेगा ताकि वक्त जरूरत पर काम आ सके तीसरी बात उन्होंने कयोंकि यह साहूकारों को बेचने की बजाए कन्ज्यूमर और प्रोड्यूसर को ही बेचा जाए गा । तो स्पीकर साहब बड़ी हैरानी की बात है कि जहां सरकार किसानों से 76 रुपए क्विंटल के भाव से गेहूं खरीद कर वही सरकार 1 ह ० रुपए क्रिंटल के भाव से उसी किसान को और उसी गेहूं को बीज कह कर बेच रही है. इससे ज्यादा ज्यादती और जुल्म, मैं तो यह समझता हूं किसान के साथ हो नहीं सकता । हरिजनों के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं कि हम यह कर रहे हैं वह कर रहे है । ज्यादा बातें तो मैं आगे चलकर बताऊंगा लेकिन फिर यह बता दूं कि जो यह कहते हैं कि हम गरीबों को, हरिजनों को सस्ते दामों पर फेयर प्राइसीज शोप्स पर गेहूं देगे, वहां यह 76 रुपए के भाव से किसानो से खरीद कर उन्हीं दुकानों पर 102 रुपए ओर 104 रुपए क्विंटल के भाव से बेच रहे हैं यह तो सस्ते दामों पर कनक

देने की इन दुकानों की हालत है ? एक गरीब मजदूर को 104 रुपए के भाव से देना चाहते है जिसका कोई चारा नहीं है । यहां पर डीग मारते हैं, शेखियां मारते हैं कि हम गरीबी हटाएगे इस तरह से गरीबी तो नहीं हटेगी लेकिन बेचारा गरीब जरूर हट जाएगा । मैं ऐसा समझता हूं । हमारे पर यहां इल्जाम लगाए जाते हैं कि हम सरकारीकरण के विरोधी हैं । राष्ट्रीयकरण या सरकारी करण को बात हम गलत नहीं मानते, होनी चाहिए लेकिन जिस तरह से सरकार की नीति हूँ वह गलत है । हम तो राष्ट्रीयकरण के हिमायती पहले भी रहे हैं और अब भी रहेंगे लेकिन जिस ढंग से सरकार चलना. चाहती है, जिस गलत काम को सरकार हाथ में लेकर फायदा उठाना चाहती हैं उसको हम बरदास्त करने वाले नहीं हैं । हम अपनी बात यहा हाउस में जरूर कहेंगे । कोई पटेल व्हीट कवि प्राइवेट लिमिटिड जलगांव में है, यह महाराष्ट्र में एक आदमी की कम्पनी है । उसको सरकार ने दो हजार टन गेहूं का परमिट दिया है यानि उसको नौ–आब्जैफशन सार्टिफिकेट दिया है हरियाणा से उस गेहूं को बाहर ले जाने के लिए । इन से पूछा जाता है कि किस बात के लिए दिया गया है तो कहा जाता है कि बीज के लिए ले जाएगा । इसी प्रकार से शादी पूरा डी ० एल ० एफ ० सीड फार्म जो कि जीद के पास है उसको भी को हजार टन का परमिट दिया गया है । यह जो गेहूं हरियाणा से बाहर जाता है यह किस नाम से जाता है, यह बीज के नाम से जाता है । यह क्या मतलब है? क्या कोई भी आदमी यह मान सकता है कि अब कनक की बीजाई का टाईम है । अब फसल पकने को जा रही

है और सरकार उनको बीज के लिए गेहूं बेच रही है । मैं सरकार से यह पूछ ना चाहता हूं कि प्लांनिग का फाल्ट नहीं है तो और क्या है? मैं आपकी मार्फत सरकार से और मिनिस्टर महोदय से गुजारिश करना चाहता हूं कि वह वाजेह तौर पर यहां हाउस में बताएं कि इस किस्म की किसान के साथ ज्यादती क्यों की जा रही है । यहां से गेहूं 100 रुपए क्विंटल के भाव से लेते हैं और वहां पर 400 रुपए क्विंटल के भाव से बेचा जाता है । क्या यह किसानो के हकों पर छापा नही है, क्या किसानों को अपने हकों से महरूम नही किया जा रहा है? इस वात क सस्कार को यहां जवाब देना चाहिए ताकि लोगों के सामने सही बात आ सके ।

इसी तरह से चावल का परमिट है । कई हजार बोरे का परमिट दिया गया है, वह भी बाहर महाराष्ट्र को जाए गा । यह सरकार कितनी ज्यादती किसानों के साथ कर रही है । मैं कोई सरकार की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं मैं तो आपके जरिए अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार सफाई दे इस बारे में कि क्या कुछ बात है? यह सरकार जो यह कहती थी कि हम साहूकार से बचाएंगे फिर यह दो हजार टन लेने वाला कौन है? दो हजार टन तो वही आदमी खरीद सकता है जिसकी जेब में बीस लाख रुपया हो ।

15.00 बजे

Mr. Speaker : Order please. The arguments which had been advanced during the discussion on Governor's

Address should not be repeated by the same hon. Member now as it will amount to repetition.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गेहूं खरीदने के लिए हरियाणा में कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए । आज कोयले की हरियाणा में कमी है । जब इसका कारण पूछा जाता है तो जवाब दिया जाता है कि वैगन्ज की कमी है लेकिन इस कनक के लिए बैगन कहां से आ जाती है । यह गेहूं वहां बीज के नाम से जा रहा है । मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार वाजेह तौर पर बताये कि यह बीज के नाम से किस तरह से जा रहा है और किस भाव पर महाराष्ट्र में बेचा जा रहा है । स्पीकर साहब, मैंने अच्छी तरह से पिछले तीन सालों का बजट देखा है । अगर आप पिछले तीन सालों का बजट देखे तो आप यह बात अवश्य महसूस करेगे कि इरीगेशन की मद के बन्दर सरकार ने जो रुपया मन्जूर किया, उसमे से 90% रुपया सिर्फ एक खास इलाके पर खर्च किया जाता रहा है । नहरों के नाम से जो रुपया रखा गया है आप देखू लें उसमें से 90% रुपया केवल एक ही इलाके के लिए खर्च किया गया है और उन 90% में से भी 80 % रुपया एक खिले के लिए ही खर्च किया जाता रहा है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को इन्साफ के साथ काम करना चाहिए और सबके साथ हमदर्दी का सलूक करना चाहिए । मिसाल के तौर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि जुई कैनाल बनाते वक्त यह कहा गया था कि इसके अन्दर जो ज्ढ़मनगरबी कैनाल का फालतू पानी होगा, वह दिया जायेगा । आज यह कैनाल

बारह–मासी केनाल हो चुकी है और इसके ऊपर बडा भारी खर्च हूआ है । इस. कैनाल का पानी किस इलाके में जायेगा, वह बात सरकार भी जानती है और हम भी जानते है । यह किस–किस रकबे को सैराब करेगी? यह 11,000 एकड़ एक ही जिले का रकबा सैराब करेगी ।

इसके अलावा एक इन्दिरा गांधी कैनाल बनी है । यह कैनाल भी भिवानी जिले के 3 लाख 29 हजार 600 एकड़ रक्बे को सैराब करेगी । इसके बनाते वक्त भी यही कहा गया था कि दरिया का जो फालतू पानी होगा, वह इसमें इस्तेमाल होया इसके अलावा एक बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती फीडर है, यह भिवानी डिस्ट्रिक्ट के 1 लाख 93 हजार 800 एकड़ एरिये को सैराब करेगी । फिर पीडत जवाहर लाल नेहरु लिपट इरीगेशन स्कीम की ओर देखिये यह नहर फालतू पानी और फ्लड वाटर ले जायेगी । मैं सरकार से यह पूछना चाहाता हूं कि यह फालतू पानी कहां से आना है? क्या आपको अभी तक कोई फालतू पानी मिल चुका है? आपने जमनगरबी नहर को ऊंचा नहीं किया आपने इसके तमाम किनारों को चौड़ा नहीं किया आज तक इस नहर के अन्दर कभी फालतू पानी नहीं चला । इसी नहर में जो आगमैटेशन कैनाल का 500 क्यूसिक पानी चलता है वह भी उसी नहर में से गुजारते हैं क्योंकि हरियाणा प्रान्त के अन्दर दो ही तो सिस्टम है । एक भाखड़ा कैनाल सिस्टम है और दूसरा वैस्टने जमुना कैनाल सिस्टम । भाखड़ा कैनाल सिस्टम को तो यह टच ही नही करते हैं ।

वैस्टर्न जमूना कैनाल सिस्टम से ही सरकार सारे काम करना चाहती है । क्या सरकार जवाब देगी कि यह कौम सा फालतू पानी है? इस नहर को न चौड़ा किया गया और न ही इसके किनारों को ऊंचा किया गया । हमें समझ नहीं आता कि वहां पर कोन सा फालतू पानी आयेगा? इसका साफ मतलब यह है कि हरियाणा प्रान्त के एक इलाके का पानी काट कर दूसरे इलाके में भेजा जा रहा है । मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि भिवानी जिले के लोगों को पानी मिले, मैं चाहता हूं कि उनको पानी जरूर मिले मैं इस बात के भी खिलाफ नहीं हूं कि महेन्द्रगढ के लोगों को पानी मिले, मैं चाहता हू कि उनको भी जरूर मिले लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूं कि किसी एक किसान के हक को काट कर दूसरे किसान को पानी दिदा जाये । मैं बडी सख्ती से इस वात की मुखालिफत करता हूं और मेरे विचार में यही एक कारण है कि हरियाणा प्रान्त के अन्दर अनाज की पैदावार नही बढ़ पायी है इस पानी को दूसरे जिलों के अन्दर देने से अनाज क7ई पैदावार बढ़ सकती है । क्वैश्चन–आवर के अन्दर आपने भी सूना है और हममे भी सुना है कि हमारे यहां तो 12 घंटे बिजली मिलती है लेकिन जिला भिवानी और महेन्द्रगढ के इलाको में 24 घटे बिजली मिलती है । आप देखें कितनी बेइन्साफी है, कितना बड़ा पक्षपात है । आखिर इसके लिए कोई वजह होनी चाहिये । तमाम नहरें वहां के लिए. तमाम बिजली वहां के लिए, क्या हरियाणा के बाकी गांबों के लोग यूं ही मरते रहेंगे? मैं सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार इस बात की ओर ध्यान दे और हरियाणा के हर

निवासी के साथ इन्साफ किया जाये । एक वात यहा पर बडा जोर देकर देकर गयी है कि ये नही उस वक्त बारह–मासी यानी पैरेनीयल हो जायेगी जब हमारे यहां रावी–व्यास का पानी आ जायेगा । स्पीकर साहब, देखिये यह इनकी कितनी हैरानी की बात है? पिछले दो बजट सैशनों के अभिभाषण निकाल कर देख लें । उसमैं इस पानी के आने के टाईम के बारे में कहा गया है । यह सरकार इस चीज को दोहरा तो रही है कि जब रावी–ब्यास का पानी आयेगा तव हम हरियाणा मे ज्यादा पानी देंगे । रावी–ब्यास का पानी आयेगा तो ये नहरें बारह मासी बनेगी । पहले इन्होंने कहा कि 1972 में आयेगा, दोबारा कहा कि सन् 1973 में आयेगा और अब की दफा हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो अभिभाषण पढ़ा, उसमें इसका कोई ज़िक्र नहीं– किया कि यह पानी कब आयेगा क्योंकि अब सरकार इसके बारे में अन–सर्टन है । यह सरकार और पानी लाने के लिए बन्दोबस्त नहीं कर सकी है । स्पीकर साहब, जैसाकि आप जानते है, इस पानी को लाने के लिए ताजमी तौर पर एक रोपड़ से करनाल तक के लिंक की कैनाल की जरूरत है । लिंक को बनाने के लिये पंजाब के अन्दर हमारी सरकार के लोग दाखिल नहीं हो सकते । मुझे पता है कि हरियाणा के इंजीनियर वहां पर गये और वहां पर अपनी टोकरी और फावड़ा खुसवा कर वापस आ गये । आज जबकि पजांब के अन्दर भी कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा के अन्दर भी काग्रेंस की सरकार है और सैंटर में भी काग्रेस की सरकार है, तब भी यह सरकार उस पानी को लाने का बन्दोबस्त नहीं कर सकी । मैं यह

कहना चाहता हूं कि अगर कल को हमें पानी मिल जाता है तो इस सरकार के पास ऐसी कोई नहर नही है कि जिससे हरियाणा के किसानों को यह पानी दे सके । हरियाणा मे जो इस वक्त सिस्टम है, उसके बनाने के अन्दर भी हरियाणा सरकार ने लापरवाही को है । इन्होने किसी किस्म की परवाह नही की कि ऐसा कोई लिंक बन जाये ताकि वक्त पडने पर हमारा पानी हमारे यहां आ जाये । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन से ऐसे वजूहात हैं कि आप हरियाणा के अन्दर ऐसा कोई चौनल नहीं बना सके? मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी पहले इसके लिये कोई चौनल बनाई जानी चाहिये । सरकार तो यह बात करती है कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ । हाथी के दात खाने के और, और दिखाने के और वाली बात इस सरकार पर हूबहू सही बैठती है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार इ स तरफ फौरी ध्यान दे और पूरी जद्दोजहद के साथ पंजाब से इस बात का फैसला करे और हरियाणा के किसान को पानी देने की पूरी कोशिश करे ।

स्पीकर साहब, एक बात मैं वाटर अलाउन्स के बारे में भी कहना चाहता हूं । वाटर अलाउन्स का मतलब यह है कि एक हजार एकड रकवे के पीछे कितना पानी चाहिये या कितना पानी सरकार मुकरर्र करती है । जब से हरियाणा बना है, उससे भी पहले से वैस्टर्न जमुना कैनाल चली आ रही है । इस नहर का वाटर अलाउन्स 19 क्यूसिक है । भाखड़ा का वाटर अलाउन्स 24 क्यूसिक है और जुई कैनाल का वाटर अलाउन्स 3. 5 क्यूसिक है '

मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हू कि ये ईमानदारी का दावा करते है कि जिस सिस्टम से यानी वैस्टर्न जमुना कैनाल से जुई कैनाल के अन्दर पानी जाता है, उसका वाटर अलाउन्स 35 किस लिये है जबकि बाकी का 19 क्यूसिक है क्या सरकार इम चीज का जवाब देने की हिम्मत रखती है? मैं कहता इ कि सरकार के प1स इसका कोई वाजिब जबाब नहीं है सिवाये इसके कि वह तोड़–मरोड़ कर अपनी सफाई में कुछ बात कह दे । इस ज्यादती क। हरियाणा के लोग समझते है । यह बात अलग है कि कोई आपके डर से या किसी दूसरी वजह से न कहे वरना फैक्टस तो छुपाये नहीं जा सकते । जो भी आप खेती के बारे में करना चाहते हैं, अगर आप हरियाणा के किसान के हित को ध्यान में रखते हुए करेंगे तब लाजमी तौर पर हरियाणा तरक्की करेगा अगर आपका काम इसी तरह से चलता रहा जिस तरह से अब है तो याद रखिये जो भविष्यवाणी वित्त मन्त्री जी ने को वै कि हम 50 लाख टन अनाज पैदा कर लेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह पूरी नहीं होगी और 50 लाख टन अनाज पैदा नहीं हो सकेगा । आप अगले साल इस चीज को देख लेंगे हमारी सरकार फिर यह फिकरा पढेगी कि हम अपना टार्गेट– पूरा नही कर सके इन्होने पिछले साल कहा कि हम 13 लाख टन अनाज वसूलेंगे लेकिन यह सरकार 50 भी प्रोक्योरमैंट नही कर सकी किन वज्हात में वसूल नही कर सकी, इसके बारे में काफी कहा जा चुका बै अगर मैं इस बारे मे कुछ कहता हूं तो ये नाराज होते है, इसलिये मेरे कहने की जरूरत नही है

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्राप्त में ऐसे और भी बहुत जिले है जहां पर उतनी ही पानी को जरूरत है जितनी की पानी की जरूरत आज भिवानी और महेन्द्रगढ में है हमें समझ नहीं आता कि सरकार क्या वजह है एक तरफ तो ध्यान देनी है लेकिन दूसरी तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है । मैं जिला जीन्द की बाबत खास तौर पर कहना चाहता हूं । मैने पहले भी चीफ मिनिस्टर साहब को सेवा में कई दफा प्रार्थना को है कि वहां पर मीठे पाती की बड़ी दिक्कत है । हर बार उन्होने यह वायदा किया कि हां भई, काम करेगे । ऐसा एक गांव है बडौदी, दूसरे हैं रूपगत, झाल कलां, झांझ खुर्द और दरिया वाला, जाजवान खेड़ी और जाजवान मैंने ऐसे गावों के नाम बताये हैं जिन गांवो के अन्दर लोग पिछले 5–6 सालों से पानी के लिये मांग करते आये फंस । जहां तक नहरी पानी का सवाल है, वहन के बराबर हूं । इन गावों के अन्दर ट्यूबवैल कामयाब नही हो सके हैं । मैंने यह अर्ज की थी कि जपे आप आगमैटेशन कैनाल्ज बना सकते हैं और जुई या दूस नहरों को भिवानी में ले जा सकते हैं .तो क्या वजह हैकि इन 5– 7 गांवो को जो जीन्द के पास पड़ते हैं .और जहां पर यह हालत है कि वे अनाज खाने के लिये भी पैदा नहीं कर सकते, पानी नही देते । आज अगर आप इन गांवों में जा कर दैखे' तो यह पायेंगे कि आधी से ज्यादा भूमि नजर पड़ी हुई वे क्योंकि वहां पर पानी अवेलेबल नहीं है । मैंने चीफ मिनिस्टर साहब मे जो प्रार्थना की थी, उस पर उन्होंने चीफ इजीनियर को लिखा होगा । मेरे पास उन्होंने यह जवाब दे दिया कि वहां पर तो खारा पानी है । अरे

भाई! यही तो मैं कहता हू कि वहा पर खारा पानी है । मीठा पानी वहां पर नहीं 'है । आप 30– 40 मील तक के फासले पर तो ट्यूबवैल लगाने के लिये तैयार हैं लेकिन वहां पर हालांकि नहरी टयूबबैल लगभग दो मील के फासले पर होंगे, तीन–चार टयूबवैल उन लोगो के गुजरे के लिये लगाने को तैयार नहीं हो । मैं अर्ज करना चाहेगा कि इस सरकार को हर किसान से और हर दूसरे आदमी से हमदर्दी होनी चाहिए जो कि गांवों में रहते हैं । अगर मेरी बात ठीक है तो कोई वजह नहीं कि उन लोगो की तरफ ध्यान न दिया जाए जो पानी के लिए तरसते है । जुलाना के आसपास के गांवों में ट्यूबवैल कामयाब नहीं हो सकते हैं । वहा पानी की कमी है । वर्षा के ऊपर सारा दारोमदार है वहां पर गांव मालवी है, देवरड है, झमोला है, खरेटी है, बुवाना है । ऐसे कितने ही गांव है जो पानी के लिए तड़पते हैं लेकिन सारा पानी उठाकर भिवानी और महेन्द्रगढ को दिया जा रहा है । किसी भी अफसर से बोलो वह बोलेगा हां जी भिवानी, किसी मन्त्री से बोलो वहू कहे गा हो जी भिवानी । कितनी हैरानी की बात है कि आज भिवानी के लिए दौड़ पड़ी है । मैं कहना चाहता हूं, अपनी सरकार है और हमें अपनी सरकार पर फख्र है लेकिन इसके साथ–साथ मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इतनी बेइन्साफी नहीं करनी चाहिए । जो गरीब लोग है उनके साथ इस सरकार को हमदर्दी रखनी चाहिए । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन गांवों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ।

स्पीकर साहब, पर–कैपिटा इन्कम की बड़ी एर्चा की गई है कि हरियाणा के अन्दर बड़ी भारी पैदावार हुई है, इतनी पर–कैपिटा इन्कम हो गई है । जो फिर्ग्ज सरकार ने दी हैं मैं उनके बारे में ही अर्ज करना चाहता हूं । वे इस प्रकार है । 1967–68 में 497 रुपए पर–कैपिटा इन्कम थी, सन् 1968–69 में 352 रुपए यानी दो साल में 45 रुपए कम ते गई हरियाणा प्रान्त में । इसका मतलब है कि 113 परसैन्ट माइनस हो गई । 1969–70 में सरकार ने 427 रुपए पर–कैपिटा इन्कम दिखाई है यानी अगर 1967–68 को लें तो उसमें पर–कैपिटा ईन्कम 397 रुपए थी और 1969–70 में 427 रुपए हो गर्ड । इस प्रकार से दो स। न में 30 रुपए की वृद्धि हुई यानी 75 प्रतिशत फी वृद्वि हुई । 1970–71 में पर–कंपिटा इन्कम 437 रुपए दिखाई है और 1971– 72 मे 435 रुपए पर–कपिटा दिखाई है यानी अगर हम 1960–70 की फिगर्ज का मुकाबला 1971– 72 को फिग्जं के साथ करें तो दो साल के अन्दर 8 रुपए फालतू हुए यानी 0.9 परसैन्ट की बढौतरी हुई जबकि आल इण्डिया लैवल पर–कंपिटा इन्कम 1 परसैन्ट बढी है और हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब की पर–कैपिटा इन्कम 2. 4 प्रतिशत बढ़ी है । इन्होंने पर–कैपिटा 'की किगर्ज गलत दिखाकर एक और काम किया है कि जौ सैट्रल गवर्नेमेट से मदद मिलनी थी वह भी बन्द होगा । उनका कहना है कि जब तुम्हारी इतनी पर–केंपिटा इन्कम है तो सैन्ट्रल अस्सिटैंस की कोई जरूरत ही नही है । मैं स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के लफ्जो को सदन को याद दिलाना चाहता हूं उन्होंने कहा था कि इन

स्टेटिसटिक्स की किताबों को समुन्द्र मैं फंक दो ताकि कोई वजीर झूठे आंकड़े देश के सामने न रखे, कोई गल्त आंकड़े न दे ।

स्पीकर साहब, अब मैं को–ओपरेटिव सोसायटीज की बाबत जिक्र करना चाहता हुं । यह ठीक है कि को–ओपरेटिव सोसायटीज की तादाद ज्यादा हुई है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज को–आपरेटिव सोसायटीज की हालत जितनी खराब है उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । मैंने इस बारे में एक सवाल भी किया था कि हरिजनों को कितना कर्जा दिया गया और मन्त्री महोदय ने कहा था कि हरिजनों को इतना कर्जा दिया । मैं कहना चाहता हूं कि इस साल से पहले जितनी हरिजन सोसायटीज थीं उनको 40 परसैन्ट और 60 परसैन्ट कर्जे के बदले में खाद दी गई दस हजार का कर्जा देना था तो उसको चार हजार रुपए की खाद दी गई । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक हरिजन जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास काश्त के लिए कोई जगह नहीं तो वह खाद का क्या करेगा । उन बेचारे हरिजनों ने दो रुपए कम पर खाद का कट्टा बेचकर कर्जा लिया । कोओपरेटिव के अन्दर एक असूली बात है कि कर्जा भाईचारे और शराफत से वसूल किया जाए लेकिन इन्होंने आर्डर पास कर दिया, असिस्टैंट रजिस्ट्रार को हुकम दे दिया, अख्तियारात दे दिए गए कि जो कर्जा न दे उसको गिरफतार कर लिया जगर । नतीजा यह हुआ कि अकेले जीन्द में 461 आदमियों को गिरफतार किया गया और इनके अन्दर ज्यादातर हरिजन थे । मैं कहना चाहता हूं कि

को–ओपरेटिव सोसायटीज के अदर कुछ आदमियों की ठेकेदारी है जो कि सरकार के एजेन्ट हैं, वे ही सारा रुपया बोगस नाम भरकर, झूठे आदमियों के अंगूठे लगाकर ले लेते है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो बोगस कोओपरेटिव सोसायटीज हैं उनको जल्दी खत्म किया जाए । जितनी जल्दी ऐसी सोसायटीज को खत्म किया जाएगा उतना ही सरकार के हित मे होगा और हरियाणा के हित में होगा ।

स्पीकर साहब, अब मैं हरिजन कल्याण निगम की बाबत अर्ज करना चाहता हूं यह सरकार बार–बार कहती है कि इसको हमने दो करोड़ रुपए से शुरू किया और आज इतनी तरक्की कर ली है । मैं चीफ मिनिस्टर और वित्त मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि इन्होने हरिजनो के लिए कितना रुपया सैक्शन किया और कितना रुपया तकसीम किया गया । मैं कहता हूं कि जो भी रुपया इन्होने तकसीम किया वह उन हरिजनों को दिया गया जो सरकार के एजेन्ट समझे जाते थे । मिसाल के तौर पर एक एक्स एम. एल. ए. को हरिजन कल्याण निगम से आठ हजार रुपए का कर्जा मिला और उसी आदमी को वैलफेयर डिपार्टमैंट से तीन हजार रुपए का कर्जा मिला और उसकी औरत को इट्रैस्ट की लोन दिया गया और फिर उसी आदमी को पब्लिसिटी डिपार्टमैंट के अन्दर सुपरवाईजर बना दिया गया हालांकि वह अनपढ़ है । यह जहनियत हैं सरकार की ये हरिजनों के साथ गद्दारी करते हैं, जुल्म करते हैं, हरिजनों के साथ और दम भरते है कि हम हरिजनों के हमदर्द है मैं कहता

हूं कि आप हरिजनों के हमदर्द नहीं है मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अब भी सरकार समझे । मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर वाकई सरकार हरिजनों की हमदर्द बनना चाहती है तो वह बिला लिहाज हरिजनों में रुपया तकसीम करे और फिर देखे कि आपकी बात बनती है या नहीं । डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर की रिकवरी के आर्डर करता है लेकिन आज तक वह रुपया रिकवर नहीं हो सका क्योंकि .....

Mr. Speaker : No personal charge please. The words will be expunged now.

Chaudhri Dal Singh : I am sorry if you say that स्पीकर साहब, एक और मसले की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं दो–तीन साल चुप रहा और सोचता रहा कि क्या किया जाए लेकिन लाचार था । .....

Mr. Speaker : Order please. This concerns internal working of an autonomous body. How is it connected with the Budget ?

Chaudhri Dal Singh : What are the circumstances, I am referring to them. मै बता रहा हूं कि आज हरियाणा के अन्दर क्या हालात है...

श्री अध्यक्ष : यह पब्लिक सर्विस कमिशन और सर्विस स्लिक्शन बोर्ड के अंन्दरूनी मामलात है ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, यहां पर एस. एस. एस. बोर्ड को डिस्कस करना कोई मुनासिब बात नहीं है ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं.... .....

श्री ओम प्रकाश गर्ग : आन ए प्यांएट आफ आर्डर, आनरेबल मैम्बर सर्विस सिलैक्शन बोर्ड के मुताल्लिक कुछ कह रहे हैं जिसका कि बजट के साथ कुछ ताल्लुक नहीं है । उनका यह कहना कि मैं चेयरमैन के पास गया, मैम्बरों के पास गया उससे ऐसा लगता है कि मैम्बर साहब, इस तरह की इन्टरफीयरैस कर रहे है ।

Mr. Speaker : I have already ruled it. The matter regarding the talk should be expunged.

चौधरी दल सिह :..... (विघ्न)

Mr. Speaker : No reference please.

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर वै कि यह सरकार के बारे में कहें लेकिन एस. एस.एस. बोर्ड के बारे में इनका कुछ कहना मुनासिब नहीं हैं ।

Mr. Speaker : Order please. The hon. member can discuss any matter referred to inthe budget.

चौधरी दल सिंह : .....

Mr. Speaker ; Order please. You cannot refer it when I have ruled it.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, तो फिर क्या कहें ।

Mr. Speaker ; now, this will also be expunged.

चौधरी दल सिंह : ..... (विघन्)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । एस. एस. एस. बोर्ड के बारे में यह कहना कि वहां पर ..... यह उचित नहीं है । यह पोर्शन ऐक्सपज करवाया जाना चाहिए ।

Mr. Speaker ; This will also be expunged.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता है कि हरियाणा प्रान्त के अन्दर बड़ी बेरहमी के साथ रुपया खर्च कया जा रहा है । आप रोड़ज की बा त को ही ले लीजिये, जिस का जिक्र मैं पहले कर चूका हू । दोबारा जि कर करने की जरूरत न हों । क्रै श प्रोग्राम है, दो सालों के अन्दर 17 करोड़ रुपया खर्च करना था परन्तु 40 करोड़ खर्च कर दिया गया । कही पर रेस्टोरैट बन रहे हैं, कहीं पर झीलें बना रहे है, क्य इन झीलों में ये डूबकर मरना चाहते हैं, इसलिए बन रहे हैं । स्पीकर, स हब यहां हरियाणा प्रान्त के अन्दर तो आज यह हालत है कि एक गरीब हरिजन के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पांव में डालने के लिये जूती तक नहीं है और ये लोग रैस्टोरैन्ट बनाने लग रहे हैं,

झीलें बनाने लग गये हैं, कहीं पर इ न के लिये कबाबघर बन रहे हैं । इस प्रकार गरीब जनता का खून चूस–चूस कर ये अपने एशो–आराम के लिये हर तरह की सहूलियते इकटठी किये बैठे हैं । स्पीकर साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी गरीब हरिजन को, गरीब जनता को बेनके इन प्रोग्रामों से एक फीसदी का भी फायदा नही हुआ होगा । इनके लिये तो जगह–जगह पर बंगले बने हुए है । जाते हैं, आराम करते हैं । इन्होंने तो इन बातों के कारण स्पीकर साहब, हरियाणा प्रान्त का सत्यानाश करके रख दिया है । (घटी) स्पीकर साहब, आप अभी घण्टी बजाने लग गये । यह तो कोई बात नही मुझे थोड़ा सा टाईम और दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ।

Mr. Speaker : You have taken 35 minutes.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दें–

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, सव मैम्बरों के साथ यकसा ही सलूक होगा।

चौधरी दल सिंह : तो स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि आज हरियाणा के अन्दर रिश्वत का दौर दौरा है । हमने पिछले सैशन में यह इल्जाम लगाया था कि इतनी चीनी की बोरियां ही गुम हो गई । जितनी तकसीम करनी होती हैं उतनी आगे नही आती । इस बारे में सरकार ने इन्कवारी भी करवाई

इन्कवायरी अफसर ने सरकार को रिपोर्ट दी कि वाकई सैकड़ों बोरिया बेईमानी से तकसीम की गई हैं सरकार ने उनका चालान नही किया क्योंकि मैं यह कहूं कि किसी सरकारी भाई का यह हक था तो नाराज होते हैं । आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि एक भाई बेईमान है, उसने सैकड़ों बोरियां खाई और वह आदमी जिसकी पहले एक लाख की जमानत हो चुकी है, उसी आदमी को नौ गांव का कोटा देना और फिर सैकड़ों बोरियों का गबन करवाना, फिर कहना कि हमारे पास कोई कानून नहीं । मैंने कहा कि आप कम से कम बोरियां तो वसूल कर लो, तो कहने लगे कि हम बोरिया वसूल नहीं कर सकते स्पीकर साहब, कितना तमाशा आज हरियाणा प्रान्त के अन्दर है, कोई चीज नहीं मिलती है । खाद नहीं मिलता है । हमारी सरकार कहती है कि हमने तो टागेंट मुकरर्र कर दिया । टार्गेट आपका 7,500 नहीं हम 20 हजार टन इस हरियाणा के अन्दर तकसीम कर सकते है । खाद है नहीं और तमाशा यह है स्पीकर साहब, कि बलैक में आप खाद ले सकते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार डिस्ट्रिकट हैडक्वार्टर पर कोई चीज दे नहीं सकती और बलैक में चाहे जितने कटटे लेना चाहो, ले सकते हो, ऐसी–ऐसी बातें हो रही हों और फिर यह स रकार अच्छी सरकार होने का दावा करती है । स्पीकर साहब, यही हालत आज सीमेन्ट की है । कहते है कि एक हजार रुपया स्माल सेविंग स्कीम में जमा करवाओ तो पाच कटटे लो । दो हजार रुपया जमा करवाओ तो दस कटटे लो । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार बताये कि कौन ऐसा गरीब आदमी है जिसके

पास एक हजार, दो हजार रुपया होगा । इस प्रकार तो कोई गरीब हरिजन भाई एक भी कटटा ले नहीं सकता । स्पीकर साहब, इस सरकार की झोली फटी हुई है, यह तो कलैक्शन पर लगी हुई है । फिर ये कहते है कि हमारा टार्गैट बड़ा बढिया है जी, हम हिन्दुस्तान पर दूसरे नम्बर पर है तूम अंगूठा देते रहो गरीबों के गले में, मारते रहो गरीबों को और फस्ट नम्बर पर आ जाओ, हमें क्या एतराज है? स्पीकर साहब। न चीनी इनके पास है, न कोयला इनके पास है, न मिट्टी का तेल इनके पास है कोई सामान इनके पास नही है यहां तो यह हिसाब है कि अन्धेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा । स्पीकर साहब, इस हरियाणा प्रान्त के अन्दर अजीब कहानी है, मैं कहां तक याद दिलाऊं । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट की जो अन्डरटेकिगज है आज हिन्दोस्तान के अन्दर 5 करोड़ रुपया सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने कारखानों पर लगाया है । हमारे हरियाणा के अन्दर एक फैक्टरी पिन्जौर के अन्दर है और सैन्ट्रल गवर्नमैंट को अन्डर टेर्किगज एलोकेशन कमेटी ने सन् 71 के अन्दर यह सिफारिश की थी कि हरियाणा के अन्दर पैट्रोलियम रिफाइनरी और स्कूटर बनाने के कारखाने लगाए जाएं । जो यह हरियाणा की सरकार है जो सैन्ट्रल गर्वमैंन्ट कहती है, उसको भी नही करती और अगर वह फैक्ट्री हमारे यहां हरियाणा में लग जाती तो यहां हजारों आदमियों को रोजगार मिल जाता और हरियाणा की आमदनी बढ़ती पर इस सरकार को तो अपनी ही पड़ी है कि सड़के बना लो उस भैसे खा लो मिल्क प्लांट में से कितने खा

गये. बिजली के पोलो में से कितने खा गये, इस तरह का नमूना पेश किया है भलाई का । इनके पास लेई साधन नहीं तो मैं यह अर्ज करूंगा कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने जो सिफारिश की थी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट को फिर दरखास्त करनी चाहिये । स्पीकर साहब, एक और अजीब बात आज हरियाणा के अन्दर है कि हम प्रजातन्त्र का नाम लेते हैं लेकिन हरियाणा के अन्दर प्रजातन्त्र की कोई बात नहीं है । जहां भी मार्किट कमेटियों का चुनाव होता था, वहां अपने नुमाइन्दे ठोस दिये, म्युनिसिपल कमेटियां यहां तोड़ दी । लैंड मार्डगेज बैन्क का जीद में चुनाव था, चण्डीगढ से घण्टी बजी पोस्टपोड । स्पीकर साहब, जब भी चुनाव हुए चण्डीगढ से घण्टी बजती है कि पोस्टपोड । अभी मार्किटिंग यूनियन का चूनाव था, नामिनेशन पेपर दाखिल हो चुके थे घण्टी चली गई कि पोस्टपोड । स्पीकर साहब, यह अजीब तमाशा आज हरियाणा के अन्दर है । इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह ऐसी घातक चीजें है कि अगर यह बीमारी बढ़ती चली गई ती शासक दल को अभी से खतरा हो सकता है इसलिए मैं यह कहूंगा कि जो डैमोक्रेटिक इंस्टीचुएशनज हैं उनके ऊपर सरकार को इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिये । आज अगर आपकी ओर से कोई चुनाव में आता है तो आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती । आप बैठे है आपके हाथ में ताकत है, आप यहां जब मिनिस्ट्री में हैं तो आपको यहां कोई पकड़ लेगा? इसलिये इस तरह की घातक बाते' सरकार को नहीं करनी चाहिये ।

Mr. Speaker : Please wind up.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मैं दो मिनट और बोलूंगा । अगर आप मुझे 15 मिनट और बोनने के लिए दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप समाप्त कीजिए ।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मैं आखिर में हरिजनों को तरफ ब्यान दिलाना चाहता हूं । आज हरियाणा के अन्दर हरिजनों की क्या हालत हूं । कोई भी पार्टी हो, वह खड़ी होनी ही प्लेटफार्म पर कहती है कि हरिजनों का भला चाहते हैं और सरकार ने बड़ी–बड़ी किनाबे' भी छापी हैं, हर जगह पर वजीर साहब के हरिजने के लिए ग्रीटिंग्ज कार्ड भी गए हैं उसमें भी पांच–छः बातें लिख दी । अव्वल तो यह हरिजन भी बाबला है जमीन के पीछे पड़ा हुआ हूं । जमीन कुएं में दिखा दो, जमीन के पीछे कूए में छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता है । स्पीकर साहव, मैंने जीन्द में देखा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एलान कर दिया कि 3 महीनों के अन्दर जमीन दे जाएंगे । आज से दो ढाई साल पहले की बात है । फिर अफसरों ने ढिंडोरा भी पिटवा दिया, आओ भाई हम आपको जमीन देगे । मैने जीन्द में स्पीकर साहब, यह देखा हं कि जो टिकट सवा रुपया का था वह ब्लैक में 5– 5 रुपये में बिका और हरिजनों की कतार खड़ी हो गई नम्बर नहीं आया क्योंकि यह टागे ट पूरा करना चाहते थे फैमिली प्लैनिग का । हरिजन अन्दर गया । कहने लगे कि देखो भाई, अगर तू

नसबन्दी करवा लेगा तो तेरे को एक किल्ला मिलेगा, अगर दो भाई करवाओगे तो दोनों को 2 किले मिलेंगे । हजारों आदमियों को इस सरकार ने ..... करवाया मीर यह सरकार हरिजनो को जमीन नही दे सकी । उन्होने हरिजनों के साथ इस तरह से मजाक बना रखा हूं । आज सरकार ने इस तरह मे हरिजनो को निहत्था करके खड़ा कर दिया हूं । कर्जे के लिये जब हरिजन जाता है तो महिनों फिरता रहता हं । फिर कर्जे में मिलता क्या है? सब से पहले उसको दलाल मिलते हैं, वे पन्डे उसको लूटते, हैं फिर वहां कर्मचारी लूटता है, फिर वहां ले जाने वाले कुछ शराब पीते हैं, फिर वह क्र्लक बाबू मेहरबानी करता है । तो आप ही देख लीजिये कि 25 परसैन्ट उसका रुपया रास्ते में ही गबन हो जात है । पिर उसको हथकड़ी लगती है । यह हालत तो आज हरिजनों की हैं । आज सब जगह पर नौकरियों मैं रिजर्वेशन्ज हैं । ये एलान करते हैं कि अगर इस क्वालीफिकेशन का कोई आदमी नहीं मिलेगा तो यह नौकरी उस वक्त तक पुर नही को जाएगी लेकिन आज हालात क्या है, सच्चाई क्या है कि झुन्ड के झुन्ड पढ़े लिखे हरिजनों के बेरोजगार फिरते हैं । मैं यह कह सकता हूं कि अगर दूसरी ऊंची बरादरी वाले लोग, जिसे ऊंचे लोग कहते हैं, वे इस तरह से फिरे' तो इन् हें पता चले । लेकिन आज जीन्द में हालत य ह है कि जितने पढ़े लिखे हरिजन लडके है वे बे रोजगार फिरतै है और उन्हैं पूछने वाला कोई नहीं हैं । आज हरिजनो की बड़ी दुर्दशा है । ये कहझे हैं कि हम वजीफे देंगे हम

फलानी चीजें देंगे, इन चीजों का क्या फायदा है स्पीकर साहब, जबकि वे पढ़े –लिखे लो ग बेरोजगार फिरते है।

स्पीकर साहब, मेरे ए क वात याद आ गई कि एक जमीदार था जोकि बड़ा गरीब था । काम काज करने के बाद जब वह शाम को घर आता था तो उसे उसके बच्चे कहते कि कहानी सुनाओ । उन के घर मे दूध का इतजाम न ही था तो व ह बच्चों को कहानी सुनाते वक्त कहता कि हम एक भैस लाएगे , व ह दूध देगी तो हम दुध गर्म करके पीएगे और मक्खन भी निकालेगे । ऐसी कह सुना कर वह बच्चो को सुलाता था । यह काम कई दिन तक चलता रहा तो एक दिन उसको घर वाली ने कहा कि तुम क्यो पागल हो गए हो । बैसे ही अपने बच्चों के बह काते हो । ले किन इसके बावजूद फिर बच्चों ने कहा कि कहानी सुनाओ तो वह कहने लगा कि मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि तुम्हारी माता जी नाराज होती हैं । तो बच्चे कहने लगे कि पिता जी यह तो हमें भी मालूम है कि न तो भैस आएगी । न दुध मिलेगा और न ही मक्खन क्रीम मिलेगा लेकिन कहानी सुनने के बाद हमें नींद आ जा ए गी । तो स्पीकर साहब, मैं यह कह ना चाहता हूं कि हरिजनों पर भी बल्कुल यही मिसाल आती है कि इस सरकार ने न तो उनको मुरब्बा देना है और न कोई नोकरी देनी है । स्पीकर साहब, मैं आखिर मै यह कहना चाहता हूं...

चौधरी राम प्रसाद : स्पीकर साहब, मेरा प्वायट आफ आर्डर है कि यह लैक्चर दे रहे है या कहानी सुना रहे है?

चौधरी दल सिंह : मैं आपकी भलाई को ही बात कह रहा हूं । इस किस्म की चमचागिरी ते अंग्रेजों के वक्त में हुआ करती थी । लेकिन आप अपनी भलाई की भी बात नही सुनना चाहते । स्पीकर साहब, देखें ये क्या बात कह रहे है?

Mr. Speaker : Order please, Is story telling relevant on the Budget?

Chaudhri Dal Singh : I am coming to that.

Mr. Speaker : This is not relevant.

Chaudhri Dal Singh : I am very sorry.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना): स्पीकर साहब, मेरा प्यांवट आफ आर्डर है कि आनरेबल मैंबर ने हरिजनों के बारे में बहुत सी बातें कही और यह भी कहा कि उनको ..... कर दिया गया है । तो मैं चाहता हूं कि यह .... शब्द एक्संपज करवा देना चाहिए । दूसरी बात इन्होंने कही कि इस सरकार ने यह काम नही किया वह काम नहीं किया तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब ये पोजीशन में थे तो इन्होंने क्या किया था? (विघ्न)

Mr. Speaker : Order please. Please wind up. You have taken sufficiently long time.

चौधरी दल सिंह : मैं अभी खत्म करता हूं । तो स्पीकर साहब, मे अर्ज कर रहा था कि हरिजनों की आज दयनीय हालत है इसलिये मैं सरकार से पुरजोर अपील करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दे । सरकार तो इनके लिए जो कर रही थी वह कर ही रही

थी इसके अलावा और भी इनके नमायदे बन गए जैसे हरिजन सघर्ष समिति । तो मैं अर्ज करूंगा इनके मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए (घंटी) स्पीकर साहब, मैं सिर्फ एक दोबाने और कहना चाहता हूं कि गावों के अन्दर हरिजनों के पास शामलात जगह नही है । मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि गांवों के अन्दर हरिजनों के लिये एक ऐसी जगह बना दी जाए जहां कि वे अपनी बारात वगैरह को ठहरा सकें । दूसरी बात स्पीकर साहब, इनके 1797 करोड़ के घाटे को देख कर मुझे बाटा कम्पनी की बात याद आ गई कि उनके हर जूते पर कीमत लिखी होती है 395, 495 या 5. 95 यही हालत इस सरकार की है इसने भी 17. 97 का घाटा दिखाया हूं बिल्कुल बाटा शूर कम्पनी की तरह लिखा है । मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सीधे लफ्जों में 18 करोड़ लिख देते तो क्या तीन लाख और लिखने से शर्म आती थी । अब ये इस घाटे को पूरा करने के लिये जनता पर टैक्स लगाएंगे । हरियाणा मैं तो पहले ही बहुत टैक्स लगे हुए है तो स्पीकर साहब, अंत में मैं यह बात कहता हुआ कि हरियाणा में और टैक्स न लगाए जाए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ) : स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया । अभी मेरे दोस्त चौधरी दल सिंह बजट पर बोल रहे थे बोलते–बोलते उन्होने बजट मे घाटे के बारे में एक बात कही

। अगर वे पिछले साल के बजट डैफीसिट संबंधी कुछ पढ़ लेते तो शायद ऐसा न कहते । पिछले साल के बजट में हमारा 1417 करोड़ का डैफिसिट था जो कि बाद में रैवैन्यू आने से सिर्फ 5.19 करोड़ का रह जाएगा इसी प्रकार इस बार हमारा डैकिसिट 17.97 करोड़ का है जिसमें कि 5.19 करोड़ पिछले साल का भी शामिल हूं । इसका मतलब यह नहीं है कि सारा साल ही हमारा डंफिसिट इतना ही रहेगा । इस साल घाटा तो हमारे पास साढ़े बारह करोड़ का ही था उसके बावजूद भी हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया । मैं चौधरी साहब को बताना चाहता हूं कि जैसे पिछले साल 1 4.17 करोड़ से 5.19 करोड़ रह गय है उसी तरह इस साल का घाटा भी पूरा हो जाएगा ।

इसके साथ अगर हमें टैक्स लगाने भी पड़े तो कोई ऐसी बात नहीं है क्योकि हमने फिफ्थ प्लान में काफी काम करने हैं और उसके लिए पैसा भी चाहिये । लेकिन 17.97 करोड़ के घाटे को देख कर यह शंका कर लेना कि बहुत टैक्स लगेंगे यह गल्त शंका है । सरकार जो काम कर रही है वह जनता और प्रदेश की भ लाई के लिए कर रही है । स्पीकर साहब, आपके द्वारा मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने क्या–क्या काम किये हैं । जिस दि न हरियाणा बना उस वक्त भारत सरकार के जरिये हम दुसरे प्रदेशों से एक लाख टन अनाज मंगवाया करते थे । ठीक पैं पिछले साल कुछ बारिश कम हुई जिसकी वजह से हमारा अनाज कम हु ऑ क्योंकि बहुत सारे हमारे इ लाके बरानी

हैं जो कि नहर न होने की वजह से सिर्फ बारिश पर ही डिपैड करते है । लोकिन इसके बावजूद भी हमने 13 लाख टन अनाज बाहर भेजा । विरोधी भाई यह भूल जाते हैं कि पिछले साल अगर हम गेहूं का टार्गैट पूरा नही कर सके तो राइस का टार्गैट जितना हमने भारत सरकार को दिया था उससे ज्यादा हमने भेजा । एक बात मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन अब कहे वगैर रहा नहीं जाता कि हमारे सी. एम. साहब ने भी क्रप्शन के मुताल्लिक यहां बताया था । हमारे आनरेबल मैंबर उस भठ्टे में शामिल थे जिसका लाइसंस कैंसिल हो गया था। लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं उसमें शामिल नहीं था । मैं कहता हूं उस सोसाइटी जिसके नाम वह भटटा था उसके ये भी मेम्बर थे और हाई कोर्ट द्वारा चार्ज लगाए जाने के बाद उसका लाइसंस कैसिल हुआ था । हां यह मैं कहता हूं कि इनका पर्सनल चाहे न हो लेकिन सोसाइटी के नाम था और उस सोसाइटी के ये मैंबर थे । मैं सदन को बता दूं कि मैं चौधरी दल सिंह जी की बात कर रहा हूं । इन्होंने को–आप्रेटिव सोसाइटीज के बारे में कहा कि ये वहुत ज्यादा खराबी करती हैं । अगर ऐसे–ऐसे नेता जो ' अपने आप को महान नेता कहलाते हैं सोसाइटियों में शामिल होंगे और वहा क्रप्शन करवाएंगे तो फिर सोसाइटीज तो बदनाम होगी ही । ले किन दूसरी ओर अगर ऐसे आदमी उनको सुधारने में साथ दें तो वह ज्यादा फायदे मंद साबित होंगी । बहुत से भाईयों ने कहा कि को–आप्रेटिव सोसाइटियों में घपला होता है लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि को–आप्रेटिव सोसाइटी एक ऐसी चीज है जिसके

जरिये सब लोगो को फायदा पहुच सकता है । एक मिसाल मैं आपको इसकी बाबत बता दु कि हरियाणा में 13,517 को–आप्रेटिव सोसाइटीज हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सारी सोसाइटीज ही खराब हैं तो इनकी तरफ लोग जाएं ही क्यों? आप इनकी मैम्बरशिप देख लीजिये 1968 में यह 9.57 लाख थी आज 12.87 ताख है इसके अलावा को–आप्रेटिव सोसाइटीज जो काम करती हैं वह 1967– 68 में 5 लाख रुपये का था और आज वे 26 करोड़ रुपये का काम कर रही है कितनी तरक्की की है? यह जो 26 करोड़ का वी कग हैं इममें 1 ते. ते 0 करोड़ जो हे वह सिर्फ फार्टिलाइजर का है जो कि काश्तकारी को उन्नत करने के लिये है । ठीक है फर्टिलाइजर की कमी है लेकिन वह कमी केवल हरियाणा के लिये ही नहीं है बल्कि' सबके लिये है अगर आप हाऊस की पिछली स्पीचों को निकाल कर देखें तो पिछले साल जब इन्ही दिनों में बिजली की कमी हो रही थी तो हमारे उस तरफ के मैंबर साहिबान चिल्ला कर कहते थे कि सारी फैक्ट्रियां बन्द कर दो । और उसी का असर ऐसा पहुंचा कि हमारी जो नंगल फर्टीलाईजर फैक्टरी थी उस का बिजली का कोटा सिर्फ 30 परसैंट रह गंया था । इ स लिए जब प्रोडक्शन कम होगी तो नैचुरली खाद भी उतनी ही कम मिलेगी । इस के इलावा हमारी जो सरकार है यह ऐसी स्कीमें खेती के बारे में वना रही हैं जिससे कि खाद की मांग दिन–ब–दिन ज्यादा बढ़ रही है ऑर लोगों के पास ज्यादा उपज आती है मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे पास खाद की कमी जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें

खाद मिलती ही नहीं है । जितनी हमें खाद की जरूरत हो उम को पूरा करने के लिए हमारी सरकार बाहिर से भी खाद मगंवाती है लेकिन बाहिर भी खाद को कमी है । स्पीकर साहब यहां पर बताया गया था कि हमारी हरियाणा सरकार हरियाणा में भी खाद की फैक्टरी लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन इस क। मतलब यह नहीं है कि अगर यहां पा खाद फैक्टरी लगेगी तो वह सारी खाद हरियाणा में ही दी जाएगी, उस का फायदा दूसरी स्टेटों को भी पहुंचेगा क्योंकि इस वक्त अगर नंगल में खाद बनती है तो उसका फायदा सारे देश को सप्लाई कर के होता है, लेकिन फिर भी अगर यहां पर फैक्टरी लगेगी तो उससे पोजीशन ईज जरूर होगी । अगर हम बजट को देखें उस में हमारी जो फ्लैड स्कीमें हैं उन के ऊपर टोटल एक्सपैडीचर 70 करोड़ 79 लाख और 25 हजार का है. इस में छोटी–छोटी स्कीमो को छोड़ कर जो बड़ी–बड़ी स्कीमें हैं उनकी डिटेल्ज इस तरह से है । इस में मलटीपरपज प्रोजैक्ट 13. 63 करोड़ के हैं, पावर प्रोजॅक्ट पर 13 करोड़ का खर्चा है, इस के इलावा मेजर और मीडियम इरीगेशन स्कीमों पर 9 करोड़ खर्च किया जाएगा, हैल्थ पर 7 करोड़ होगा और एग्रीकल्चर के लिए पाच करोड़ 55 लाख का प्रोविजन है । रोड्ज पर भी आप का 50 करोड़ चार लाख से ऊपर खर्चा होना है, इन्डस्टरी पर दो करोड 50 लाख रुपया खर्च होना है । तो यह जितनी भी स्कीमें हैं इन से लोगों की उन्नति होनी है । इन के ऊपर सरकार ज्यादा खर्च करेगी इस के इलावा जनरल एडमिनिस्टेरशन का जहां तक सम्बन्ध है उसके लिए सिर्फ एक

करोड़ 30 लाख रुपया फ्लैड स्कीम का खर्चा है । इस के इलावा ड्रैनेज और फ्लड्ज कौ कंट्रोल करने पर एक करोड़ का खर्चा है जो फि मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है क्पोकि हमें तजुर्बा है, अभी पिछली बरसात में मेरे हलके में एक नदी .है, वह अपना रास्ता बदल कर गांवों में चली गई और जो सरसब्ज जमीनें थी वहां पर सब रेता हो गया । इस लिए अगर इस को कंट्रोल करने के लिए फ्लैन में रुपया न रखा जाए तो वह कैसे ठीक हो सकती है? जब कोई अनफोर्सीन चीज आ जाती है और खर्च उसका बढ़ जाता है तौ वह लाजमी तौर पर करना ही पड़ता है । मैं समझता हूं कि इस साल जब उस नदी ने अपना रास्ता बदला तो nobody could control it. It was imposible अब सरकार की तरफ से बताया गया है कि उस को कंट्रोल करने के लिए गौर किया जा रहा है और आने वाली बरसात से पहले सरकार उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है । हमारे बजट में जो स्कीमें हैं उनके बहुत से आंकड़े पहले बताए जा चुके हैं इस लिए उनको ज्यादा तफसील में दोहराने की जरूरत नही है । अब यह अपोजीशन वाले भाई कहते है कि ट्यूबवैल्ज नहीं है और अगर कहीं हैं भी तो उन से पैदावार नहीं बढ़ी । मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले सन् 1968 में हमारे हरियाणा में 29 हजार ट्युबवैल थे और इस वक्त एक लाख 23 हजार ट्यूबवैल हैं । इस लिए यह कैसे कहा जा सकता है कि ट्यूबवैल्ज की तादाद नहीं बढ़ी और उन से कोई पैदावार भी नहीं बढ़ी? मेरा इलाका नारायणगढ सब–डिविजन का जो है वहां पर जहां–जहां पर हमारी

सरकार ने इरीगेशन के लिए टयूबवैल लगाए हैं वहां पर दिन रात का पैदावार में फर्क पड़ गया है हम देख रहे है कि वहां पर ट्यूबवैल्ज के जरिए कितनी तरक्की हो रही है, यह और बात है कि हमारे एरिया भे अभी और भी कमी है, वहां पर और भी ट्यूबवैल्ज लगने चाहिए और हमारी सरकार लगाने की कोशिश कर रही है । अगर इनकी बात को मान लिया जाए जैसे ये कहते हैं कि बिजली की कमी है इस लिए और ट्यूबवैलों को कनैक्शन न दिए जाएं तो उस का मतलब यह होगा कि हमारा जो एरिया नैव जहां पहले ही पानी की बहुत कमी है वहा पर कनैक्शन न मित्रने की वजह से लोगों की तरक्की रुक जाएगी और पैदावार में इजाफा नहीं होगा । इस लिए इनकी बात को हमारी सरकार नहीं मान सकती । मैं गुजारिश करूंगा कि वहां पर और इस के इलावा जो दूसरे एरियाज है जहां पर आबपाशी का और साधन नहीं है वहां ज्यादा से ज्यादा बिजली के कनैक्शन दिए जाने चाहिए ताकि जो वैकर्वड इलाके हैं वे ऊपर उठ सकें । दो चार बातें स्पीकर साहब मैं और कहूंगा । रोड्ज के बारे में मैंने कई साहिबान को कहते हुए भी सुना हूँ और अखबारों में भी यह लिखा हुआ पढ़ा है कि सरकार ने हरियाणा में रोड्ज पर फालतू खर्च किया है । यह बात यहां हाऊस में भी कुछ मैम्बरों ने अपनी स्पीच मे कही है लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होने सिर्फ प्रोपेगंडा करने के लिए ऐसी बातें कहीं है स्पीकर साहब, मैं आप को जिला अम्बाला के बारे में अर्ज करता हूं, यहां पर तीन सड़कें बनी हैं जिन्होंने अम्बाला जिला की किस्मत बदल दी है । एक अम्बाले से हिसार

रोड़ है, दूसरी नैशनल हाईवे रोड़ बनी है, जो पचकूले से अम्बाला को जाती है और ण्क सड़क अम्बाला से जगाधरी को जाती है जिस पर टांगरी और घग्गर का पुल बना है । यहां पर कई मैंम्बर यह कहते हैं कि यह सड़क फिजूल बनी है और इस पर जो पुल इतना मंहगा बनाया है वह भी फिजूल खर्ची की गई है । उनकी यह बात बिल्कुल नामुनासिब है और मैं समझता हूं कि वे हमारी तरक्की को देख कर खुश नहीं होते । मैं स्पीकर साहव कहता हूं कि हमारी तो इन सड़कों और पुलों ने किस्मत बदल भी दी है मैं 1962 से 1967 तक भी एम. एल. ए. रहा था । और मुझे याद है कि उस वक्त एक–एक, दो–दो बसे चलवाने के लिए और छोटी–छोटी सड़के बनवाने के लिए इतनी मिनते करनी पडती थी जिसका कि ब्यान नही किया जा सकता लेकिन अब हमारी हरियाणा सरकार ने बगैर कहे अपने आप सड़कें और पुल बनवा दिए हैं और जहां पर पहले दो बसें भी नही चलती थीं वहां पर अब 25– 25, 30–30 बसें चलती है । इस का अन्दाजा हम ही लगा सकते हैं कि हमें कितनी सहूलियतें मिली हैं, जो दूसरे इलाकों के लोग हैं वह नही लगा सकते हमारे जो जिला अम्बाला के लोग हैं वह ही उन सड़कों से जो फायद हुआ सै उस का अन्दाजा ज्यादा लगा सकते हैं । आज मोरनी हिल्ज में एम्बैसेडर कार भी जा सकती है जबकि पहले वहां पर किसी अफसर की ड्यूटी होती थी तो वह भी नहीं जाते थे । आज वहा पर डेली बस सर्विस है और आने जाने के लिए लोगो को बहुत आराम हो गया है । इस लिंए हमारी हरियाणा सरकार ने बहुत काम किया है

। घग्गर के पुल के बारे में मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार ने इतना बडा पुल इतने थोड़े अर्से में बना कर सारे देश में रिकार्ड कायम किया है लेकिन यह भाई कहते हैं कि उस को बनाया क्यों गया, और कहते हैं कि उस पर कोई खास ट्रैफिक नहीं? ट्रेफिक का जहां तक ताल्लुक है वह तो आहिस्ता–आहिस्ता बढेगा आप को मालूम होगा शि पहले अम्बाला कालेका रोड़ पर भी ट्रेफिक कम था लेकिन आज देखिए कितना है । स्पीकर साहब जब पंजाब रोडवेज की स्ट्राईक हुई तो तमाम हिमाचल की बसें और हरियाणा की बसें इस सड़क से गई, इस लिए हमें इस पुत्र का और सड़क का बहुत फायदा हुआ है सड़क के साथ–साथ लोगों ने ट्यूबवैल लगा लिए हैं और जो लोग चण्डीगढ के पास रहते हैं चूंकि उनको पता है कि इस जगह ने तरक्की करनी है इसलिए वे भागते फिरते हैं कि हमें कहीं थोड़ी बहुत जमीन बय मिल जाए । जमीन चूंकि कम है इस लिए पहले तो कोई बेचता नहीं और अगर कोई बेचना चाहे भी तो पहले जहां दो हजार एक किल्ले की कीमत थी अव 10 हजार कीमत पड़ती है । इसलिए हमारे भाईयों को नुक्ताचीनी करने से पहले इन सब बातों को सामने रख लेना चाहिए ।

16.00 बजे

कई भाइयो ने यह कहा कि पावर अबेलेबल नही है । पावर के बारे मैं अर्ज करता हूं कि पहले हमारे पास 232 मैगावाट पावर होती थी लेकिन अब यह 450 मेगावाट है । तो आप देखें कि पावर भी हमारे पास कितनी वढी है । लेकिन जितनी यह तेजी

से बड़ी हूँ उतनी ही तेजी से हमारे पांत में पावर की डिमांड भी ज्यादा बढ़ी है । इसी लिये इतनी पावर बढ़ने के बाबजूद भी हमें पावर कम नजर आती है इस पावर को बढ़ाने के लिये भी बहुत कोशिशे की जा रही है । यहां हाऊस में चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया था और मैं उसे दॉहरा देना फर्ज समझता हूं ताकि इन भाइयों को मैमोरी शार्प हो जाये कि पावर को बढ़ाने के लिये फरीदाबाद में साठ– साठ मैगावाट के दो थर्मल यूनिट्स और पानीपत में एक सौ दस–पेस मैगावाट के दो यूनिट लगाने की कोशिशें की जा रही हैं और उनसे जल्दी ही पावर मिलने लग जायेगी । इसके अलावा दूसरे सोर्मिज से और दूसरे सूबों से भी पावर लेने की कोशिश की जा रही है जैसे कि राणा प्रताप सागर से जब हमें अनर्जी मिलेगी तो उससे काफी फायदा होगा । मेरा ख्याल है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो पांबटा में हाइडल प्रोजैक्ट बना रही है उसमें भी हमारा हिस्सा रखा जायेगा क्योंकि वह पानी हमारी स्टेट से होकर गुजरता है । बदरपुर से भी हमें पावर मिलेगी और हमारा अपना जो हाइडल प्राजैक्ट वैस्टने जमना कैनाल पर बनाने की योजना चल रही है उससे भी हमें कम से कम 45 मैगावाट बिजली मिलने की सम्भावना है । इस लिये यह कहना कि सरकार पावर के बारे में कुछ नहीं कर रही है गलत है और यह वह भाई कहते हैं जिनको यह पता नहीं कि सरकार कौनसी योजनायें चला रही है । कई भाईयों ने कहा कि हरियाणा के गांवों में पीने के पानी की भी कमी है मैं मानता हूं कि बहुत से गांव हैं जहां पर पीने के पानी की कमी है लेकिन जब से यह

सरकार आई है इस बारे में बहुत काम हुआ है और बहुत गाँवों को जल योजनाओं से कवर किया गया है और आगे कवर करने को योजनायें बनाई जा रही हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1954 से लेकर 1968 तक 14 सालो में 203 गांव को पीने का पानी दिया गया था ले किन मई 1968 के बाद जब से यह मौजूदा सरकार आई है अगस्त 1973 तक पाँच सालों में 436 गांव में पानी पीने के लिये दिया गया है और इस वक्त टोटल गांव जिन को पीने का पानी दिया गया है 639 हो गये हैं और 1973–74 मे 154 और गांव में य ह पानी देगे । यह ठीक है कि यह मसला काफी बड़ा है और इस तरफ ज्यादा ध्यान देने और पैसा खर्च करने को जरूरत है क्योकि 25 सात्र की आजादी के बाद भी हम अगर लोगों को पीने का पानी नही दे सकते तो यह अच्छी बात नहीं लगती लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सरक। र ने इस बारे में कुछ नही किया है । किया तो बहु. त कुछ है लेकिन आज भी मेरी नारायणगढ़ तहसील मे कई गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की बहुत दिक्कत है । मैं सरकार से कहूंगा कि उस इलाके में प्रायरिटी दे कर पानी दें क्योंकि वहा पर लोग गांव मे तालाब और जोहड़ों का पानी पीते हैं वहां पर न कोई कुंआ है और न वॉटर सप्लाई स्कीम चलाई गई है । मुझे आशा है कि स रकार उस तरफ ध्यान देगी और मैं तो समझता हूं कि सरकार ध्यान दे भी रही है । हमारे जो काववाला स्कीम है उससे 15/20 गांव को पानी मिल जायेगा । सरकार कर तो बहुत कुछ रही है लेकिन हमारे हरियाणा के यह जो इलाके थे वे इतने पिछड़े रहे कि वहां

पर पहले कुछ हुआ ही नहीं इस लिये जितना काम किया जाता है वह थोड़ा लगता है । ऐसी भी बात नहीं है कि हमारे यहां पानी दे ने की तरफ ध्यान नही है पानी देने की कोशिश की जा रही है टयू बवैल्ज से मिल भी रहा है और ज्यादा देने की कोशिशें भी की जा रही हैं लेकिन मांग इतनी ज्यादा है कि जो काम होता है वह थोडे लगता है । मुझे आशा है कि सरकार इस तरफ और ध्यान देगी । सड्कों के बारे में भी यहां पर जिकर आ या है । इस के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि एक नवम्बर 1966 को जब हरियाणा बना तो हमारे हरियाणा में 5,100 किलो मीटर सड़कें थीं जो कि 1,386 गांव को पक्की सडझों से कनंक्ट करती थीं । मई 1968 में ह मा रे पास 5650 कि नो मी टर सड़कें थीं जित का मत लब है कि तीन साल में कुल 550 कि लोमीटर सड़ के ही रयाणा में बनी थीं । आप दे खें कि सितम्बर 1973 में हमारी सड़कें 13, 672 किलोमीटर हो गई । अब आप अं दाजा कर लें कि जब से यह मौजूदा सरकार आई हूँ इस ने पिछ ले पांच साल में आठ हजार किलो– मीटर रोडज बनाई हैं और उन से 4070 गावों को कवर कर दिया गया है । अगर इन रोड्ज को पग्सैंटेज के हिसाब से देखा जाने तो आप देखेंगे कि 60 फीसदी गांव? पक्की सड़कों से कनैक्ट कर दिये गये हैं । मिनिस्टर साहब ने जो जवाब यहा हाऊस में दिया है उसके मुताबिक तो 61 फीसदी गांव कनैक्ट हो गये हैं और अब तो यह 61 फीसदी की फिगर और आगे चली गई होगी । यह नहीं है कि सडके बनाने का काम बंद हो गया हैं यह चल रहा है और इस बारे में सरकार

ने प्रायरिटी फिक्स कर दी है कि कैसे और कहां–कहां रोड्ज पहले बनानी है । जो रोड़ज बाकी रह गई हैं, जहां पुल नहीं बने है और छोटी–छोटी पुलिया नहीं बनी है उनको बनाने का और पूरा करने का सरकार ने विश्वास दिलाया है औंर हमें सरकार पर पूरा ऐतबार करना चाहिये कि वह बनायेगी । अब आप टू औंसपोर्ट को ले लें और देखें कि इस क में कितनी तरक्की हुई है । जिस दिन यह हरियाणा बना उस दिन हमारे पास कुल 567 बसें थी और इन 567 में 300 तो डौज बसें थी जो कि यूजुलैस थीं और यह डीज बसें सारे पंजाब से ला– ला कर हमारे हरियाणा के डिपुओं में रख दी गई थीं । आप देखेगे क हमारे पास काबले इस्तेमाल बसें 267 ही थी इ स सारे हरियाणा में । हमारी सरकार ने नई बसें ली और आज जु ला ई 1973 तक हमारे पास इन से बढ़ कर 1, 431 बसें हो गई । आप देखें कितनी तरक्की हुई है और सरकार की भी इन बसों से पूरी तसल्ली नही है और वह ज्यादा से ज्यादा बसें लेना चाहती है लेकिन डिमांड के मुताबिक बसें मिल नहीं रही हैं । स रकार तो चाहती है कि उसे सौ बसें एक महीना में मिले लेकिन मिलती नहीं है । फिर आप इन्कम को देख ले कतनी इस मद में बढ़ी है जब हरियाणा बना था उस वक्त हमारी आमदनी एक करोड़ 82 ताख 25 हजार थी लेकिन अब हमें इस ट्रांसपोर्ट से चार क रोड़ 16 लाख 54 हजार रुपये की आमदनी होती है । जहां हमारी बिजली के मामले में नम्बर एक है वहां ट्रांसपोर्ट के मामले में भी हम नम्बर दो पर सारे भारत में आते हैं । मेरे एक भाई ने बिजली के बारे में कहा कि यू ० पी ०

में इतने ज्यादा गांव में बिजली चली गई और हरियाणा में उसके मुकाबले में इतने गांव में गई । यह बात शायद चौधरी दल सिह जी ने कही थी । लेकिन मेरे उन भाई को यह तो देख ना चाहिये था कि यू ० पी ० में टोटल गांव की तादाद कितनी है औ र उसके मुकाबले में हमा रे कितने गांव हैं और फिर परसैटेज निकाल कर देखते कि हमारे कितने परसैट गांव में बिजली ग ई है और यू ० पी ० में कितने परसैंट गांव में गई है लेकि न उहोंने यह बात न देख कर तोडू मरोड़ क र अपनी बात को कहा और फैक्ट स को देखने की कोशिश नहीं की । आप अन् दाजा लगायें कि यू ० पी ० में 54 जिले हैं और हमारे अब दस हो गये हैं लेकिन ऐ रिया तो वही है बड़ा नही है । हमारे हरियाणा में सौ परसैंट गांव में बिजली चली गई है और यू ० पी ० की परसैंटेज वह भाई निकाल कर बता दें । जै सा कि हमारे चीफ मिनिस्टर सा हब ने कहा है अगर कमीशन बन गया तो बेससे हरियाणा को और गांव मिलेगे और 120 के करीब गाव तो हमें प्राईम मिनिस्टर अवार्ड में से भी मिलने हैं और अगर हमें और ज्यादा गांव मिलते हैं तो उन में भी यह सरकार बिजली दे देगी लेकिन इस वक्त जितने गांव हरियाणा में हैं उन सब में इस सरकार ने बिजली दे दी है और सारे भारत में यह पहली मिसाल है कि सौ परसैट गांवों में किसी स्टेट के अन्दर बिजली गई है । लेकिन यह भाई कहते हैं कि यू ० पी ० में इतने गांवों को मिल गई और हरिया णा में इतने को मिली । तो बितने गांव हरियाणा मैं थे उन सब को मिल गई तो बाकी और गांव कहां से लाये? क्या किसी दूसरी

स्टेट मे जाकर बिजली दे दें? मैं अर्ज करता हूं कि इस सरकार ने हर शोहबा मैं नुमाया तरक्की की है । अब मैं कोआप्रेटिव के बारे में अर्ज करता हूं । हमारे पास हरियाणा में 6,670 गांव है और तकरीबन सारे के सारे गावों को को–आप्रेटिव सोसायटीज से कवर कर लिया गया है । कोआप्रेटिव सोसायटियो के जरिए से लोन डिस्ट्रिव्यूट होता है । 1967– 68 में 9 करोड़ रुपए का लोन डिस्ट्रिब्यूट हु आ था और 19 7 2– 7 उ मे 39 28 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिब्यूट किया गया हे । इससे आप अन्दाजा लगाएं कि पहले से कितना फर्क पड़ गया है । 1967– 68 में वर्किग कैपिटल 58. 90 करोड़ था और अव 210 करोड़ हे । अब मैं डिपौजिट्स के बारे मे वता देता हूं । 1967– 68 में को–आप्रेटिव सोसायटियों के पास डिपोजिट्स 8 करोड़ था और आज 28. 67 करोड़ है इससे आप अन्दाजा लगाएं कि इन पर लोग कितना एतबार करते है? लोग खुद डिपौजिट करवाते हैं, यह बात नहीं कि सरकार डिपोजिट करवाती है सरकार तो इनसे हिस्से खरीदती है जो बड़ी– बड़ी को– आप्रैटिव सौसायटियो हैं, लेकिन डिपोजिट नहीं करवाती जो लोग दूसरी जगहों से आते हैं वे इन में डिपोजिट करवाते हुं । जब आपके पास इतना डिपोजिट है तो आप प्रोफिट का भी अन्दाजा लगा लें कि कितना हो सकता है स्टेट कोआप्रेटिव बैक में 1967– 68 में 9.87 ला का प्रोफिट था और अब 1 9 7 1– 72 में ए 1 7 ह लाख हो गया । स्टेट लैंड मार्गेज बैंक ने कितनी तरक्की की है? स्टेट लैंड मार्गेज बैंक में 1 967– 68 में 0. 86 लाख का प्रोफिट था और आज 1971 – 72 मे 28. 63 लाख का

प्रोफिट हुआ है । यह प्रोफिट तब हुआ जा लोगों ने पैसे डिपोजिंट करवाये और इंसके बदले में बैंक ने लोगों को कुएं लगवाने के लिए, ट्यूबवैल लगवाने के लिए, लिए प्रिजरवेशन के लिए और लैंड खरीदने के लिए कर्जे दिए और इससे इसको यह प्रोफिट .हुआ है ।

सैन्ट्रल को–आप्रेटिव बैंकस में 1967– 68 में 18. 93 लाख का प्रोफिट था और 1971 – 72 में यह मुनाफा 64. 42 रुपये तक जा पहुंचा अगर ये बैक काम न करते, लोगों को कर्जे न देते तो लोग उन मे पैसा जमा करवाने के लिए न जाते और यह मुनाफा न होता । लेकिन लोगों को इन पर विश्वास है और पूरा फायदा उठाते है पी 0 एल 0 एम 0 वीज0 में 1967– 68 में 31 हजार रुपये था और आज 1 971 – 72 में बढ़कर 2 1. 43 लाख हो गया । इससे इ स संस्था की कामयाबी का पता चलता है एक चीज मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इन पर सरकार को एक चौक करना चाहिए चाहे सरकार चौक रखे, चाहे संस्था वाले रखें चौक यह करना है कि बैंक से जिस चीज के लिए को आप्रेटिव बैंक को कर्जा दिया जाए वह उसी चीज पर इस्तेमाल हो जाए और ऐश्योर कराया जाए कि वह रुपया उसी चीज पर खर्च होगा जिसके लिए कर्जा दिया जा रहा है । डसके लिए कोई स्कीम बनायें क्योंकि कोआप्रेटिव सोसायटी की मारफत अगर कोई चीज की जाएगी तो वह इंडिविजुवल तौर पर करने से बेहतर होगी । अब आप इडिविजवलज के बारे में देख लें । आप

इन्क्वायरी करवा करके देख लें उसके लिए चाहे आप सारे अपोजीशन के मैंम्बर ले ले, मुझे कोई एतराज नहीं है । पहले कोआप्रेटिव सिस्टम के थ्रु सारे के सारे डिपो चलते थे मैं कहता हूं कि ये कितने करप्शन के ऐलीगेशन लगाते थे और कितने प्रूव होते थे । ऐलीगेशन तो चाहे कितने ही ल गा लो । जब इडविजुएल बीच में आएं तो करप्शन के चांसिज बढ़ जाते हैं क्योकि कोई चौक करने वाला नहीं होता । कोआप्रेटिव सोसायटी में कई मैम्बर होते हैं । उसकी बर्किंग कमेटी होत है और वर्किंग कमेटी के मैम्बर किसी में 10 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, किसी में 16 होते हैं, वे चौक रखते हैं कि करप्शन न हो और अगर कोई भद्र–पुरुष उन सोसायटीज में रहकर करप्शन या बलैक मार्किट करवाना शुरू कर दे तो इसका कोई इलाज नहीं है । इसका इलाज होना बड़ा मुश्किल है । फिर ये यहां आकर कहते हैं, कि करप्शन है, लेकिन असलीयत यह है कि वे खुद करप्शन करवाते है । आप किसी भी शोबे में ले ले, जहां ऐसे आदमियो का दखल है वहां करप्शन है । स्पीकर साहब, एक बात मैं और अज कर देना चाहता हूं । वे आफिसर जिन को को– आप्रेटिव सोसायटियो का पता नहीं है कि कोआप्रेटिव क्या चीज है, को–आप्रेटिव किस को कहते हैं उनका जरूर यही ख्याल हो जाता है कि पता नही को–आप्रेटिव वा ले क्या–क्या करते हैं, खाने–पीने का मामला है । कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट के अफसर या दूसरे कैडर के आफिसर आई ० ए० एस. या पी. सी. एस. हैं जिनको कोआप्रेटिव' के अर्थ का पता है वह ऐसा नहीं कहते, उनको तजर्बा

हो जाता है । लेकिन जो जानता ही नहीं वह कहता है कि यह खाने–पीने का साधन है । आप किसी को लगा दो, छः महीने तो उसकी समझ में नहीं आयेगा कि यह मामला क्या है । जिन आफिसर्ज ने यह स्टेज त्रास कर ली है, इस स्टेज से पार हो गये हैं, जिन्होंने एक बार देख लिया कि किस तरह से सोसायटिया चलती हैं, वे को–आप्रेटिव को बुरी चीज नही समझते । मिसाल के तौर पर को–आप्रेटिव में एक डिस्ट्रिक्ट होल से ल को– आप्रेटि व सोसायटी है यानी कि डी 0 डबल्यू 0 सी 0 एस0 । एक लहर चली कि इस संस्था को अबौलिश कर दिया जाए । अबौलिप्रश कैसे होगी, यह तो कानूनी बात है लेकिन इस लहर ने उनको नाकारा जरूर बना दिया । मैंनै उस वक्त यह कहा था कि कि डी. डबल्यू. सी. एस. की संस्था डिस्ट्रिक्ट लैवल पर जरूर होनी चाहिए लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई इन्होंने इसके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट आफिस बना दिया है । आज आप अगर उसका कम्पैरिजन करके देख लें तो मालूम होगा कि इसपर खर्चा भी ज्यादा, उस खर्चे के मुकाबले में जितना पहले होता था । लेकिन एक अलग आफिस खोल दिया, और जहां तक मैं समझ ता हूं, उसका फायदा कोई नहीं । तो स्पीकर साहब, ऐसी–ऐसी बातें भी हो जाया करती हैं । कई आफिसर ऐसा इशू बना लेते है कि फलां संस्था को तो हम ने खराब ही करना है । अगर खराब करने पर आ जाते हैं तो दूसरी बात है ।

स्पीकर साहब, को–आप्रैंटिव सोसायटीज और पंचायतों का आपस में गहरा सम्बन्ध है । को–आप्रेटिव जनता की भलाई करने की संस्था है और इसी से जनता की ज्यादा से ज्यादा भलाई हो सकती है क्योंकि इसमें जनता आपस में मिल कर काम करती हैं । स्पीकर साहब, डेरी के महकमें ने काफी तरक्की की है । सरकार ने तीन प्लांटस–जींद, अम्बाला और भिवानी में लगा दिए हैं । कई लोग हाऊस में कहते है कि फलां जगह नहीं लगाया गया, यह बात ठीक नही है । जहाँ लगना चाहिए वहां सरकार खुद लग। रही है । आप तो मांग कर सकते हैं लेकिन यह नहीं कहना चाहिए कि फलां लगा है इसलिए यहा भी लगन। चाहिए । हमें ठीक मांग करनी चाहिए । जहां लगना चाहिए सरकार खुद लगा रही है, इसको फलौरिश कर रही है । अम्बाला में तहसील न।रायणगढ में एक चिलिग सैंटर लगाया है यह पिछले ड़ेढ़ महीने से चालू है । इस सेटर के जरिए से नारायणगढ से 5 हजग्र लिटर दूध रोज जाता है । आप मल्टीपलाई करके देख लें, ड़ेढ़ रुपये किलो के हिसाब से साढ़े सात हजार रुपये का दूध उस चिलिग प्लाट में जाता है और लोगों को दूध की कीमत मिलती है । अब आप अंदाजा लगा लें कि सालाना कितने रुपये का दूध सरकार द्वारा खरीदा जाता है । जो मिस्क वंडर थे वे पानी मिलाकर दुध देते थे और अब वह दु ध इन्होंने ले लिया । तो सरकार जो हे वह लोगो को अच्छा दु ध देगी और जिन्होंने अपने जानवरों का दूध दिया उनको भी कीमत अच्छी मिल गई लेकिन

फिर भी मेरे भाई कहते हैं कि सरकार ने यह फायदे वाली बात नहीं की ।

स्पीकर साहब, फॉरेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहता हूं । फौरेस्टस का नार्म प्लेन्ज में 20 परसैट है और हिल्ज में 60 परसैंट है लेकिन फौरेस्ट के नीचे हमारा टोटल एरिया केवल 3.4 परसैंट है । जिस तरह से भी हो सके सरकार को इसको भी बढ़ाना चाहिए । हमारे पास फॉरेस्ट्स का एरिया पंजाब से ज्यादा अच्छा है । पंजाब के पास तो फौरेस्टस रहे ही नही हैं उनके पास तो केवल सड़कों, नहरों और रेलवे लाईन्ज के आस–पास की जगह रह गई है जहां कि वै फौरेस्टस लगा सकते हैं लेकिन हमारे पास मोरनी हिल्ज है जिनको काफी डिवैल्प किया जा सकता है, कलेसर है, और इसी तरह से गुड़गांव में अरावली रेजिज है जिनमें फौरेस्ट्री हो सकती है लेकि न जहां मैं फौरेस्ट्री को डिवैल्प करने के लिए कहूंगा वहां मैं तुक बात यह भी जरूर कहूंगा कि लोगो के हक्कों का भी खास ख्याल रखा जाए जैसा कि हमारे पड़ौसी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में होता है– (घण्टी) स्पीकर साहब दूसरे भाई बजट पर भी बोले हैं और गवर्नर ऐडैरस पर भी बोले हैं मैं तो पहली दफा बोरर रहा हूं इस लिये मुझे समय थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिये. । तो स्पीकर साहब मैं फौरेस्ट के बारे में अर्ज कर रहा था फॉरेस्ट का बजट सिर्फ 45 लाख का है यह बहुत कम है । इनके लिये मे रा निवेदन है कि बजट थोड़ा ज्यादा होना चाहिये ।

इसके बाद, स्पीकर साहब मैं इरीगेशन एंड ड्रेनेज महकमें के बारे मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा । इस महकमे में टयूबवैल्ज ल गाने का काम हमारी एम० आई ० टो ० सी ० कर रही है । इसने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है और टयूबवैल्ज लगाकर के बड़ा नाम कमाया है । हमारे यहां तो इ सने टयूबवैल्ज लगाए ही लेकिन बिहार में भी लगा दिए । पिछले साल मैं इतफाक से आसाम और बिहार की तरफ गया था और थोड़ा सा टाईम मुझे बिहार मे ठहरने के लिए मिला था । तब वहां के लोगों ने मुझे बताया कि हमारे यहां तो हरियाणा के लोग टयूबवैल्ज लगा रहे हैं । वैसे तो, स्पीकर साहब वहां के लोग खुद भी टयूबवैल्ज लगा सकते थे लेकिन इनके अच्छे काम को देख कर ही उन्होंने इन्हें बहां बुलाया था । यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है लेकिन स्पीकर साहव इस सम्बन्ध में आपके द्वारा सरकार के नोटिस में मैं एक बात लाना चाहता हूं । हमारे जो ये टयूबवैल्ज लगते ऐ, उनसे जब इरीगेशन करते हैं तो कई जगह पाईप लाईन डिफैक्टिव रह जाती हैं, वह पूरा पानी नहीं खींचती, उसमें लीकेज होती है । एम 0आई0टी0सी0 इस बारे में कोई सर्वे करवा ले और यह देखे कि पूरा पानी मिलता है या नहीं मिलता है । अगर नही मिलता है तो कहां नुक्स है उसे यह देखना चाहिए और फिर उस नुक्स को दूर करना चाहिए ।

स्पीकर साहब, फ्लडज से कही–कही जो जमीन गिरनी शुरू हो गई है उसको रोकने के लिए यह डिपार्टमैंट स्कीम्ज

बनाता है । नारायणगढ तहसील में इस सरह का काफी इलाका है जहां इन स्कीम्ज की काफी जरूरत है । रुण और मारकंडा नदियों ने तो अपने रास्ते बदल लिए हैं । इसलिए मैं आपके कार स्पीकर साहव, गवर्नमैंट से यह अर्ज करूंगा कि वे वहां के लिए स्कीम्ज बनाकर इस बरसात से पहले–पहले चौक कर ले वरना बरसात में हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी।

स्पीकर साहब, पानी की सीपेज को रोकने के लिए सरकार कैनाल्ज की लाईनिंग कर रही है और उनको ईटों से पक्का कर रही है । ब्रूससे भी लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा । इस बारे में भी मैं निवेदन करूंगा कि रावी और व्यास का पानी आए तो उसमे से कुछ पानी लिफ्ट स्कीम के द्वारा अम्बाला को जरूर दिया जाए । मिनिस्टर साहब ने वैसे कहा तो है कि कोई स्कीम बनाई जा रही है लेकिन फिर भी मै निवेदन कर दूं कि लिफ्ट स्कीम ही वहां फायदा पहुचा सकती है क्योंकि कैनाल से ज्यादा फायदा हम नहीं उठा सकते । तो इस तरफ भी सरकार अवश्य ध्यान दे ।

शड्यूल्ड कास्टस के मुताबिक, स्पीकर साहब, मेरे बहुंत से विरोधी भाई कहते हैं कि कुछ नही हुआ । यह बात ठीक नहीं है । मेरे से पहले बोलने वाले भाई ने इस बात का जवाब तो दिया है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इस बारे मं अर्ज कर देता हूं । स्पीकर साहब, इवैक्यू लैण्ड ज्यादातर इन भाईयों को ही अलौट हुई है और इसे खरीदने का जहां तक ताल्लुक है उसे सिवाए

हरिजनों के कोई सैर खरीद ही नहीं सकता । यह दूसरी बात है कि वहू एक भाई के पास जाए या दूसरे भाई के पास जाए । सर्विसिज का जहां तक ताल्लुक है उसमें भी रिजर्वेशन है चौधरी दल सिह जी ने पता नही कैसे कह दिया कि रिजर्वेशन नही है । मैं उन्हे बताना चाहता हूं कि सरकार जो भी पोस्टस भरती है उनमें 20 परसैंट हरिजनो के लिए रिजर्व होती हैं । पहले तो यह रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में ही होती थी लेकिन. अब तो सरकार ने नया हुक्म दिया है उसके मुताबिक जितनी कार्पोरशन्ज हैं, जितनी को–आप्रेटिव सोसाईटीज हैं फैडरेशन्ज हैं और बैक्स हैं उन में भी यह रिजर्वेशन लागू कर दी गई है । तो अब 20 परसेट पोस्टस इन अदायरो में भी हरिजन भाइयों को मिला करेंगी । ' जहां तक हरिजन चौपालों का सम् बन्ध है वे भी जहा–जहां मांग हो ती है हर साल दी जाती हैं । यही नहीं स्पीकर साहब, हमारे यहां स्टेट लैवल पर हरिजनो के लिए जो कमेटी है उसके हैड सी 0 एम म0 साहब हैं । जब सी 0 ए म 0 साहब उस कमे टी में स्वयं हो तो मैं नहीं समझ ता क उनकी भलाई की क्या बात वाकी रह जाएगी जस में वे मदद नहीं करेंगे । फिर स्पीकर साहब, अब तो रिजर्वशेन प्रोमोशन में भी कर दी गई है । लेकिन फिर भी स्पीकर साहब, एक बात अ पनी सरकार के जरिए अपने बिजली बोड ए को मैं जरूर कहूंगा । (इस समय सभपतियों को सूची में से एक सदस्य चोधरी ईश्वर सिंह पदासिन हुए) चेयरमैन साहब, आज मैं देखता हूं कि इलैक्ट्रिक कनैक्शन लेने में हरिजन लोगो और पिछड़े हुए लोगों के जिनमें दो ए कड़ से कम जमीन वाले

भाई भी शामिल हैं, बडी दिक्कत आती है क्योंकि बे इलैक्ट्रिक कनैक्शन लेने की समर्थ नहीं रखते । इसके लिए मैं चाहूंगा कि जिस तरह से जमींदार को तकाबी मिलती है उसी तरह से इलक्ट्रिफिकेशन के लिए इन लोगों को सरकार तकावी दे दे । इलैक्ट्रिफिकेशन जो है वह बोर्ड कर दे और इन से एक या दो रुपया महीना चार्ज कर ले । एक घर की इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए मान लो सौ रुपया लगाते है तो मेरे ख्याल में चार साल में वे वसुल हो जाएंगे । अगर, चौयरमैन साहब, इस तरह से हो जाए तो इससे हरिजन भाइयो और गरीब लोगो को बड़ा फायदा होगा । इसमें आप भले ही उस घर को बेशक छोड़ दें जस घर का एक बच्चा मुलाजिम हो क्योकि उसके पास रसोर्सिज हैं, वह स्वयं इलैक्ट्रीफिकेशन कर सकता है लेकिन बाकियो के लिए आप इस बात को जरूर कर दें ।

टूरिजम में, चेयरमैन साहब, हमने बड़ा नाम कमाया है । कालका से दिल्ली तक सउरक जाती है । इस सड़क के किनारे पिंजौर गार्डन, पिपली, चक्रवर्ती झील, सम्भालखा, घरौंडा आदि जगहो पर टूरिस्टस के लिए वड़ा इस्तजाम किया गया हूं । वहां वैठकर लोग चाय पानी पी सकते हैं और ठहरना चाहे तो ठहर भी सकते हैं क्योंकि यही मोटल्व भी बने हुए हैं । पहले लोग थ्रू करनाल जाया करते थे मगर अब दाई पास से होकर टूरिस्ट चकवर्ती झील का आनन्द लेना चाहता है । यह बड़ा ही सुन्दर नजारा हमारे पास हो गया है । उसको देखकर दिल बहुत बहलता

है । इन्सान का दिल करता है कि काफी देर वहां ठहरा जाए लेकिन मजबूरी से आगे जाना पड़ता हूं । इसी तरह से दूसरे हाई–वेज के ऊपर भी डिवैल्पमैंट हुई है । कुछेक जगहों के नाम जो कि डिवैल्प हुए हैं, बड़खल क्षील, सूरजकुण्ड, सोहना और सुलतानपुर आदि हैं । अगले वर्ष के दौरान मी, चेयरमैन साहब सोनीपत, रोहतक, हिसार, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल तथा नारनौल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्यटन कम्पलैक्स बनाए जाने का प्रस्ताव है । इससे, चेयरमैन साहब, हरियाणा टूरिज्म के नक्शे पर जो कि पइले नही था आ गया है ।

अब चेयरमैन साहब मैं एजुकेशन की तरफ आता हूं । हमारे पास प्री–प्राइमरी स्कूल हरियाणा में दो थे लेकिन अब ह वै, प्राईमरी स्कूल्ज 4, 348 थे ले किन वे 31–8–73 को 4, 800 हो गए हैं । मैं अब गवर्न मैट मिडल स्कूलों की बात करना चाहता हू । पहले ये 447 थे ले किन अब उनकी तादाद 781 हो गई है । पहले हाई स्कू ल और हायर सैकेन्डरौ स्कूल 713 थे ले किन अब 1, 092 हो गये हैं । यह गैं मानता हूं कि जे 0 दी 0 टी 0 स्कूल वाकई दो कम हो गये हैं ले किन जब हमारी स्टेट में जे 0 बी 0 टी 0 इतने सरप्लस हो गये हैं, जिन्होंने पहले जे 0 बी0 टी 0 की हुई थी उनको ही नौकरी नहीं मिल पायी है । जब हरियाणा बना तो कुल 47 कालेज थे । अब हमारे यहां 100 कालेज हो गये है और भी प्राईवेट कालेज बनते जाते है । हमारा जो फोर्थ प्लान का टारगेट था उसमें हमारे प्राइमरी स्कूल 250 खोले जाने थे ले

कि न 800 खोले गये । प्राइमरी से मिडल स्कूल बनाने का 150 का टारगैट था लेकिन हमारे यहां 279 स्कूलों को अपग्रेड किया गया । मिडल स्कूल से हाई स्कूल बनाने का टारगैट 60 का था पर 279 स्कूलों को अपग्रे ड किया गया । काले ज दो बनाने का टारगैट था परन्तु 6 कालेज बनाये गये । पहले हमारे टीचर्ज 8 हजार 415 एम्पलाएड थे लेकिन 31. 8. 71 को ये 11 हजार 472 की तादाद में एम्पलाएड हुए । कालका से दिल्ली तक इस जी 0 टी 0 रोड़ पर कोई भी गवन मैंट कालेज नहीं था, यह ठीक है कि अब भी कम हैं लेकिन अब हमारे कालका मे काले ज हो गया है, राई के अन्दर स्पोर्ट स कालेज हो गया, कुरूक्षेत्र में यूनिवर्सिटी हो गयी है । हरियाणा बनने से पहले कालका से देहली तक यानी 150 या 175 मील तक कोई भी गवर्नमैट की इन्स्टीच्यूशन नहीं थी लेकिन अब यहां हो गयी हैं । हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार और स्कूलों को अपग्रेड करेगी । वै से तो सरकार ने मेरे सवाल के जवाब में कहा है कि अपग्रेड इस साल नहीं कर रही है लेकिन हमारे एरिया मे अपग्रेड करने के लिए अभी बहुत मांग है क्योंकि मेरे एरिया में स्कूलों की अपग्रेडिग कम हुई है इसलिए वह होनी चाहिए । (इस समय उपाध्यक्षा पदासीनन हुई) डिप्टी स्पीकर सिंह मैं आपके द्वारा एक अर्ज करना चाहता हूं कि एक मुफाल की स्कीम है । वह केवल हमारे अम्बाला, भिवानी और गुडगाव जिले में चल रही है । इस स्कीम से काफी लोगों को फायदा पहुंचा है । इस स्कीम के तहत लोगो को पशु पालने के लिए, डेरी स्कीम चलाने के लिए कर्जा देते है ताकि वह अपनी आमदनी बढ़ा सकें ।

उस पं से से वे जानवर ला सकें और उन से दूध बेच कर ज्यादा आमदनी बढ़ा सकें । इसलिए डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए अर्ज करूंगा कि कम से कम अम्बाला जिले में जो मुफाल की स्कीम छोटे किसानों के लिए लिमिटिड ब्लाक्स में है यह लिमिटिड ब्लाक में नहीं होनी चाहिए, वह सारे के सारे जिले अम्बाला में होनी चाहिए । इस स्कीम के तहत जो बगैर जमीन वाले लैन्डलैस लोग हैं, उनको कर्जा दिया जाता है, वह उनके लिए ग्रान्ट नहीं बल्कि कर्जा हैं । हमारे इलाके के लोग पिछड़े हुए हैं उनको ग्रान्ट्स भी मिलनी चाहिए, वह तभी मिलेगी जब टोटल एरिया को इम्फाल की स्कीम में शामिल कर दिया जाये गा । मै सरकार से फिर अर्ज करूंगा कि सारे जि ले को इम्फाल स्कीम में शामिल कर लिया जाये ताकि हमारे सारे जिले को फायदा हो सके ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं हेल्थ के विष य में अर्ज करना चाहत हूं । हैल्थ डिपार्टमैंट हमारे प्रदेश मे काफी तरक्की हुई है । सन् 1968 में हमारा परकैपिटा एक्सपैडिचर मैडीशन का जहां 21 पैसे था आज 1 – 4– 72 तक वह 80 पैसे पर–कैपिटा हो गया है । हैल्थ की मैडिकल फैसिलिटीज के लिए सन् 1968–69 में चार रुपये साठ पैसा पर–कैपिटा था परन्तु अब वह 10 रुपये परकैपिटा हो गया है । पहले 1968– 69 में नम्बर आफ बैडज 5 हजार 188 थे लेकिन अब 1972– 73 में छः हजार 817 हो गये है । आशा है कि भविष्य में और भी हमारी नयी

डिस्पैन्जरीज खुल जायेंगी । यह बात दूसरी है कि इ स बजट मे हमारे स्कूलो में अपग्रेडिग नही हो सकी लेकिन डिस्पैन्सरीज तो खुल जाये' गी । कुछ डिस्पैन्सरीज खुल चुकी है आयुर्वेदिक 38 डिस्पैसरीज खोली गयी है । हमारी स्टेट में 20 हस्पताल और 11 प्राइमरी हैल्थ सैन्टज अन्डर कन्सट्रक्शन है । मैं सरकार का बडा भारी मश्कूर हूं कि सरकार ने हमारे नारायणगढ जैसे बैकवर्ड ए रिया में हस्पताल दिया है, वहां पर कन्सट्रक्शन जारी है और जल्दी उसका काम पूरा हो जाये गा । उस से हमारे बैकवर्ड एरिया के लोगो को बहुत फायदा होगा ।

अब मैं इडस्ट्री के विषय में भी अर्ज करूं । इन्डस्ट्री में सारे हरियाणा में काफी तरक्की हुई है । हमारी बहुत छोटी स्टेट है । इन्डस्ट्री के लिहाज से डिवैल्पमेट के चासिन्स कम हैं क्योंकि इतना ज्यादा बडा एरिया नहीं, इतनी ज्यादा बड़ी स्टेट नही है । जितनी ज्यादा बड़ी स्टेट होगी उतने फन्डज भी ज्यादा होंगे । यहां के लोग ज्यादा गरीब हैं । मुझे तो अपनी तहसील नारायणगढ का पता है वहां पर बहुत कोशिश की जाती है । तब जा कर इन्डस्ट्री लोग लगाते हैं । सरकार ने वहां पर लोगों को इन्डस्ट्री लगाने के लिए काफी सहूलियतें दे रखी हैं । सरकार ने कहा कि यदि कोई इन्डस्ट्री लगाना चाहे और अगर वह 20 परसैन्ट पैसा अपनी तरफ से लगा दे तो 80 परसंन्ट पैसा सरकार देगी । उसमें वह जमीन भी शामिल होगी जिसमें वह इन्डस्ट्री लगायेगा । हमारे लोगों के पास इतना पैसा नही कि वे क्हा पर

इन्डस्ट्री लगा सकें । मैं अब सरकार का मश्कूर हूं कि सरकार के को– आप्रे शन से वहां मुगफली के तेल का सहदपुर में कारखाना लग रहा है । इसलिए मैं सरकार से फिर अर्ज करूंगा कि वहां पर कोई और भी सरकारी कारखाना लगाया जाये ताकि उससे इ स इलाके के लोग फायदा उठ सकें । अगर कोई कारखाना ल ग जाये गा तो यहां के लोगों को एम्पलाएमैंट मिल सकेगी ।

जहां तक तालीम का सम्बन्ध है उसका इस समय तो जिक्र नही करना चाहता कि वह किस किस्म की होनी चाहिए । चौधरी मेहर चन्द जी जो रेज्योलूशन लाये हैं उस बारे में तो उसी दिन कहूंगा । जिस तरह की तालीम आज पढाई जाती है उससे तो लोग बेकार ही रहते हैं । ऐ सी तालीम पढ़ाई जाये जिससे लोग बे कार न रहें, अगर उनको नौकरी नही मिलती है तो वे कोई अपना काम कर सकें ।

इडस्ट्री के मुताल्लिक मैंने अर्ज किया हुं कि काफी तरक्की हु ई है । हरियाणा फाइनेन्शल कार्पोरेशन ने 1968– 69 में 13.73 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया था और उसके मुकाबले में सन् 1972– 73 में चार करोड़ 56 लाख 12 हजार रुपया सैंक्शन किया है । इसमें से जो डिस्कस किया गया है वह 2 करोड़ 60 लाख 74 हजार है । इसमें वह रकम शामिल न हीं है जो इडस्ट्री एक्ट के तहत दी गयी है । यह रकम 19.25 लाख रुपए है । सरकार हमें इम्पोर्टिड मैटीरियल भी मंगा कर देती है ।

उपाध्यक्ष : आपको बोलते हुए काफी टाईम हो गया है । ट्रेजरी बैचीज से और भी काफी बोलने वाले हैं । इसलिए आप वाइड– अप करें ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : मैं जल्दी ही वाइंड–अप करता हूं । आप पांच मिनट और दे दें ।

उपाध्यक्षा : हां आप पांच मिनट में वाइड–अप करें ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : मैं अभी बपने ऐरिया के बार में थोड़ा सा अर्ज कर दु । जो ज्यादा स्ट्रेस करने वाली बाते' हैं उनके बारे में जरूर करूंगा । जेब आपने कुछ टाईम की भी पाबन्दी लगा दी है । हमारे एरिया में टयूबवैलज ज्यादा होने चाहिए ताकि नारायणगढ तहसील के अन्दर ज्यादा आबपाशी ही सके। सिढौरा के अन्दर 25 वैड्ज का हस्पताल है । यह काफी बड़ा टाऊन है वहां पर सब–तहसील भी होनी चाहिए । लोगों को काफी दिक्कत रहती है । दूर से आने वाले लोगों को काफी परेशानी है । इसलिए मेरी अर्ज है कि वह सब–तहसील होनी चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं । आप भी उस तरफ आयी हैं आपने भी देखा होगा । नारायणगढ़ से अम्बाला तक की सड़क पर अभी तीन पुत्र बनने बाकी हैं । इस बारे गे मैं आपको बताऊं, एक बार ये बजट में भी आ चूके थे और सैक्शन भी आ चुकी थी । एक पुल है धमाना

चोआ पर, एक आमला नदी पर और एक टांग री नदी पर । धमाना चोआ पर और आमला नदी पर पुल जल्दी बनाये जाने चाहिये । टांगरी नदी पर जो पुल बनना है, उसके बारे में एक दिक्कत आती है । उसमें आधा एरिया पंजाब का आता है और आधा हरियाणा का । अगर पंजाब सरकार के साथ किसी समझौते के साथ यह पुल बन जाये तब तो यह ठीक है वरना जिस तरह सरकार ने हरियाणा में सड़कें बनायीं हैं उसी तरह वहां पर यह पुल एक ऐसी जगह बन सकता है जो हरियाणा में पड़ता है और उसमें पंजाब नहीं आता । इसलिये मेरी यह दरख्वास्त है कि अगर यह पुल किसी समझौते के साथ न बन सके तो इसे थोड़ा सा डाइवर्ट करके बना दें । इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो रोड्ज बननी बाकी पड़ी हैं, उनकी जिस हिसाब से सरकार ने प्रायरिटी रखी है उसी हिसाब से कम्पलीट करा दें । इसके अलावा एक बात मैं बहुत जरूरी समझता हूं । मैं यह कहूंगा कि नारायणगढ में बसिज का सब–डिपो होना बहुत जरूरी है । यह काभ आप जरूर करे । सीमेंट की भी हमारे यहां बड़ी तकलीफ है । इतफाकन हमारे इस महकमे के वजीर भी हाऊस में बैठे हुए हैं । ये वहां पर भी होकर आये हैं और इन्होंने हमारी दिक्कत देखी है, हमारी दिकक्त यह है कि वहां पर कोई मेन–डिपो–होल्डर्ज नहीं है जिसकी वजह से न तो वहां का कोई इन्डैन्ट देता है और न ही सीमेंट आता है । वहां का मेन–डिपो–होल्डर न होने और न इन्डैन्ट देने की वजह से हम लोग बिना सीमेंट के रह जाते हैं । पिछली दफा क्वार्टर की हमारे

लिए कोई ऐलोकेशन ही नहीं हुई थी जिसकी वजह से काफी परेशानी हुई । इसलिये मेरी अर्ज यह है कि हमारे इलाके का कोई न कोई डिपो–होल्डर जरूर होना चाहिए । आपकी तरफ से यह हुक्म हुआ है कि अब मैं बैठूं । वैसे तो कुछ और समय तक बोलना चाहता था लेकिन इतना ही कहकर समाप्त करता हूं । मैं स्पीकर साहब का बडा मश्कूर हूं कि उन्होंने मुझे टाईम दिया और आपका भी बहुत मश्कूर हूं कि आपने भी मुझे 5 मिनट का टाईम और दिया ।

चौधरी मेहर चन्द (बडोपल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज बजट पर जनरल डिस्कशन जारी है । सबसे पहले मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि फाइनैंस मिनिस्टर ने जो बजट प्रैजेन्ट किया है, वह काबिलेतारीफ है, उम्मीदों से लबरेज हूं, संतोषजनक है । मैं यह समझता था, जब मंत्रीगण को तरफ से हाउस में सवालों के जवाब दिये जा रहे थे कि शायद बजट में कुछ मायूसी हो, या बजट मायूसकुन हो, या शायद बजट कुछ फीका हो लेकिन मैं फाइनैंस मिनिस्टर को इस बात के लिये दाद देता हूं कि बजट वड़ा पुर–उम्मीद है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह भी कहूंगा कि हम तरक्की के रास्ते पर चलते रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद हं कि इस बजट में जो कुछ प्रोवीजन किया गया है उससे तरक्की कायम ही नहीं रहेगी बल्कि हम आगे बढ़ेंगे ।

अब डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं बजट के चन्द अदायरो का जिक्र करूंगा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, सबसे पहले जो अब की

बार बजट का प्रैजेटेशन इस हाउस में हुआ है, उस के लिये मैं फाइनैंस सेक्रेट्री हरियाणा, और फाइनैंस मिनिस्टर साहब को दाद देता हूं कि बजट बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया गया है । इसके अलावा बजट की प्रैजेटेशन के मुताल्लिक मेरा एक सुझाव है । अगर यह सुझाव सरकार ठीक समझे तो मैं सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि उसकी इसे मान भी लेना चाहिए । बजट में जो तबदीली आयी है, उसके लिये मैं पहले ही फाइनेंस सेक्रटरी और फाइनैंस मिनिस्टर महोदय की तारीफ कर चुका हूं लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि इस बजट को और भी आम फहम बनाया जा सकता है । वह किसे तरीके से बनाये जा सकते हैं, इस बारे में डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा बजट ऐट–ए–ग्लान्स का ए क छोटा सा पंम्फलैट आया है । यह पैम्पलैट भी फाइनेशियल आस्पैक्ट्स को डील करता है । जनता ने आपके इस फाइनैंशियल आस्पैक्ट्स को नहीं देखना । जनता यह देखती है कि आपके फिजीकल टार्गट्स क्या हैं? हरियाणा के अन्दर क्या काम हो गया है और क्या होना है? मैं आपकी मार्फत अपनी सरकार को यह सुझाव देता हूं कि बजट के साथ एक ऐसी पैम्पलैट अटैच होना चाहिए जिसके अन्दर तमाम इम्पौटैंन्ट फिजीकल । टार्गेट्स का जिक्र वे या उसमें वर्क्स–चुन–प्रौग्रेस बतायें जायें कि क्या–क्या काम चल रहे है और क्या वे 1974– 75 में जारी रहेंगे । इसके अलावा उसमें यह भी होना चाहिए कि

बजट के अन्दर किन–किन आईटम्ज के लिये प्रोवीजन किया गया है । मिसाल के तौर पर डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं यह कहूंगा कि इस पंम्पलैट के अन्दर यह बात आनी चाहिए कि कितनी सडके बनी और बनेंगी, मेरा मतलब सड़को की लम्बाई इन किलोमीटर्ज से है । दूमरी आईटम उस पैम्पलैट में यह आनी चाहिए कि कितने वाटर वर्क्स बने और कितने बनाने को तजवीज है । मसाल के तौर पर बजट के अन्दर यह मैन्शन किया गया है कि सौ गांवों को और कवर किया जाये गा । बेहतर हो यदि ऐसी सभी चीजें जनता की नौलेज के लिये एक पैम्पलैट की शक्ल में आ जायें । कोई ए क आध आईटम नहीं है, कई आईटम्ज हैं, जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं । इसी तरीके से नहरों का भी इस पैम्पलेट में जिक्र आना चाहिए कि किस हद तक आवपाशी हो रही है और मोजूदा साल में कितने ओर एरिया में आबपाशी होने का इमकान है । फिफथु फाईव ईयर प्लान को जो बात है, यह एक अलग चीज है । 1974– 75 का जो बजट जनता के और इस हाउस के सामने है, उसमें यह बातें आना निहायत जरूरी हैं । नहरों के अलावा पानी के और भी कई साधन हैं जिनसे जमीन इरीगेट होती हैं । उनके बारे में भी इस पैम्पलैट में जिक्र होना चाहिए. कि उन साधनों से इस वक्त कितनी जमीन की इंरीगेशन होती है और आगे कितनी की इरीगेशन होने की सम्भावना है । इसके अलावा इस में यह भी जिक्र होना चाहिए कि 1974– 75 में कितने हास्पिटल्ज और डिस्पैंसरीयां और बनेंगी । मैंने एक जगह एक मैमौरेन्डम पढ़ा था उसमें इस बारे में कुछ जिक्र किया गया

था कि अस्पताल या डिस्पैंसरिया कुछ बढ़ेगी । जनता को इससे अगाह करने के लिये अगर एक पंम्फलैट में यह भी आ जाये तो हमारे हाथ थोड़े से और मजबूत होते हैं । हम जनता को यह बताने वाले बनते हैं और जनता खुद भी यह देख सकती है कि वाकई हरियाणा गवर्नमैंट का जो ऐटीच्यूड है वह एक प्रौग्रेसिव ऐटीच्यूड है । इलैक्ट्रिसिटी के मुताल्लिक भी उस पैम्फलैट में आना चाहिए कि इलैक्ट्रिसिटी की मौजूदा जनरेशन कितनी है और आगे जनरेशन कहां तक बढ़ने को सम्भावना है, चाहे हम वह जनरेशन किसी दूसरी स्टेट से पड़ोसी से ले या अपने साधन जुटा कर बढायें । इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें ऐम्पलायमैंट के बारे में भी जिक्र होना जरूरी है। उसमें यह बताया जाना चाहिए कि कितने लोगो के ऐम्पलायमैंट दी जा चुकी है और कितने लोगों को एम्पलायमैंट देने को तजवीज हूँ । इसमें मामूली सा बेरियस साधनों का भी जिक्र हो जाना चाहिए

इसके अलावा हरिजन चौपालों के लिये, हरिजनों के लिये मकान और वैल्ज इत्यादि के लिये सोशल–वैलफेयर की जो मद है, उसमें प्रोवीजन है । उसमें इस बारे में सबसिडी का जिक्र है और रुपया रखा गया है । जनता को इस बारे में भी वताया जाना चाहिए । जनता के पास यह वजट जाना चाहिए क्योकि यह बजट जनता को बताने वाली एक चीज है । उनको यह बताना चाहिए कि इतना अया चौपालो के लिये 1974– 75 के बजट में रखा जा रहा है.

यह सारी चीजें कि इतना रुपया ड्रिकिंग वाटर के लिए है इतना रुपया हाउसिज के लिए दिया जा रहा है, यह एक बड़ी इम्पारटंट चीज है जो. कि जनता के सामने आनी चाहिए ताकि हमारे जो क्रिटिक्स हैं उनको जनता भी फेस कर सके, उनको जनता बता सके कि हरियाणा सरकार ने जनता को इतने साधन दिए हैं । सरकार ने जनता के लिए इ तने काम किए हैं । एक और चीज है जिसकी बाबत क्वैश्चन आवर में क्वैश्चन के जवाब में कहा गया 'नो' और वह सवाल था स्कूलों की अपग्रेडिंग के बारे में । दो–तीन साल से स्कूलों की अपग्रेडिग नहीं हो रही है यह बताया जा रहा है कि जो टारगैट फोर्थ फाइव ईयर प्लान का था उससे भी ज्यादा पूरा किया जा चुका है अब फिफथ प्लान शुरू होने वाला है । मैं कहूंगा कि हर साल कुछ न कुछ होना चाहिए ताकि हम जनता की तसल्ली कर सकें और जनता को कुछ न कु छ महसूस हो कि ह रियाणा सरकार का ध्यान हायर एजूकेशन की ओर भी है इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक और बात का जिक्र होना चाहिए । हरिजनों के अलावा इस दुनिया में और भी गरीब लोग है और उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिए और यह बताना चाहिए कि बजट के अन्दर उनके लिए कितना रुपया प्रोवाइड किया जाएगा पर्टीकुलरली उन गरीबों के लिए जो देहातों में रहते है मैं इस बात को मानता हूं कि जहां तक शहरो का ताल्लुक है हरियाणा सरकार का काम सराहनीय है । लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि सिर्फ शहर ही नहीं ज्यादा आबादी देहातों में रहती है उस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है ।

यह मेरा सुझाव है बाकी तो हरियाणा सरकार की मर्जी है कि उसकी क्यों पालिसी रहेगी । मेरा सुझाव है कि जहां तक देहातो मे गरीबों को मकान देने का ताल्लुक है उसका जिक्र इसमे जरूर होना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं दूसरी आइटम टूरिजम को लेता है' । हमारे क्रिटिक्स कई दफा कहते हैं कि हरियाणा को खूबसूरत क्यों बनाया जा रहा है? मैं कहता हूं कि इस वतन को जिसके साथ हमारा इतना प्यार है, उसको खूबसूरत बनाना कोई गुनाह नहीं हैं । हां, मैं यह जरूर कहूंगा कि अपना–अपना नजरिया है । कहा भी गया है कि जिन्दगी के हमीन तकाजों को लोग अक्सर गुनाह कहते है । अगर उनका यह नजरिया है तो मैं कहूंगा कि यह ठीक नहीं है । मैं टूरिजम के महकमे को दाद देता हूं और टूरिजम के मिनिस्टर की सराहना करता हूं कि इस महकमे ने हरियाणा का नाम ऊचा किया । हरियाणा को टूरिजम के भै प पर ला दिया है, यह कोई बुरी बात नहीं है...

उपाध्यक्षा : चौधरी मेहर चन्द जी आप कितना टाईम लेंगे? मे रे पास बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट है । आपको 15 मिनट बोलते हु ए हो गए है ।

चौधरी मेहर चन्द : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर मैं रेल गाड़ी की तरह चलू तब ही पूरा कर सकूगा ।

उपाध्यक्षा : तेज चलना तो अच्छा ही होता है ।

चौधरी मेहर चन्द : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कह रहा था कि टूरिर म डिपार्टमैंट ने बडा सराहनीय काम किया और मैं इसकी दाद देता हूं । एक और बात के लिए भी मैं मन्त्री महोदय की दाद देता हूं कि इस डिपार्टमैंट को सैल्फ सफीशेन्ट बनाया जा रहा है । 1974– 75 के बजट में जो खर्चे का प्रोवीजन है वह है एक करोड़, चालीस लाख, अडसठ हज एंड सम थिंग और उसके अगेन्सट आमदनी जो दिखाई गई है वह 1 करोड़, 41 लाख 44 हजार । अगर हरियाणा को खूबसूरत बनाया जा रहा है तो मेरे ख्याल में किसी को दुख नही होना चाहिए । शायद मेरे भाई यह भूल जाते हैं –

न हो जिस चमन में बहार कभी आई

है उससे खुशतर किसी सहरा की तिन्हाई ।

अगर अपने वतन में हम बहार नहीं ला सकते तो सहरा ही रखें, मेरे ख्याल में वह अकलमन्दी की बात नहीं कही जा सकती । ए क बात का मैं और जिक्र करूंगा और वह है मेरे हल्के में फतेहबाद लेक उसको ब्यूटीफाई करना चाहिए । अगर टूरिजम डिपार्टमैंट फतेहबाद लेक को ब्यूटीफाई कर दे तो मैं यह गारन्टी देता हूं कि उससे आमदनी भी हो सकती है क्योकि वहां के लोग कुछ इस तरफ अपनी रगबत भी रखते हैं ।

ड्रिकिंग वाटर की तरफ भी हमारी सरकार का खास ध्यान है और मैं समझता हूं कि जहां फोर्थ फाईव ईयर प्लान में 750 गांवों को पीने के पानी की सुविधा दी गई वहां अगले साल यानी 1974–7 5 में सौ गावों को पीने के पानी की सुविधा देने का प्रोवीजन है । मैं उम्मीद करता हूं कि फिफ्थ प्लान में 1400 गांव कवर होंगे इस तरह से अगर पांच से तकसीम किया जाए तो यह फिगर सौ नहीं रहती यह वहुत ज्यादा बैठती है । लेकिन यह सारा काम अवेलेबिलीटी आफ फंडज पर निर्भर करज है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि डिपार्टमैंट इस तरफ खास ध्यान देगा । एक बात और है मेरे हल्के में 55 विलेजिज हैं । कोई गांव ऐसा नहीं है जिसका मीठा पानी हो, सब गावों का खारा पानी है । मैं दरखास्त करूंगा कि मेरी कास्टीच्यूएंसी की तरफ और ध्यान दिया जाना चाहिए ।

अब मे इरीगेशन की तरफ आता हूं । इस शोबे में बहुत ज्यादा तरक्की की हुं । तरक्की ही नहीं बहुत ज्यादा तरक्की की है । सरकार ने इस तरफ खास ध्यान रखा है । अगर कोई अपनी नजर से उस तरक्की को न देखे तो वह देखने वाले का कसूर है । मैं अपने साथियों से अर्ज करूंगा कि चाहे वह हरियाणा की तरक्की के वारे में कुछ न कहें लेकिन जो बाहर के आदमी हैं वह हरियाणा की तरक्की के बारे में क्या लिखते हैं, वह मैं बताना चाहता हूं । आप इलस्ट्रेटिड वीकली के 1973 के एनुअल नम्बर को देखें । उसमे मंगत राय, आई ० सी ० एस ० ने लिखा हं ।

मंगत राय ने 1938 का हरियाणा देखा, मंगत राय ने 1948 का हरियाणा देखा और उन्होंने आज का हरियाणा भी देखा है । उन्होंने लिखा है :–

"Haryana has today re-earned its name as the green land. Haryana's progress, since it broke away from the Punjab on 1st November, 1966, particularly from May, 1968, has been phenomenael."

जबकि यह मौजूदा मिनिस्टरी कायम हुई थी अगर हम खुद इस तरक्की को नहीं देख सकते, अगर हम उस प्रोग्रैस का अन्दाजा नहीं लगा सकते तो हमारे क्रिटिक्स बाहर वालों की ओपिनियन तो देखें कि हरियाणा ने कितनी तरक्की की है और वे हरियाणा की बावत क्या कहते हैं । मि0 मुन्नी लाल ने एक किताब लिखी है जिसका नाम बै 'हरियाणा आन हाई रोडस टू प्रासपैरेटी ।' उसमें उन्होंने लिखा है कि–

"Haryana is speeding forward at a pace that dazzles the eye."

हमारे यहां के ये लोग कहते हैं कि हरियाणा में तरक्की नहीं हुई है और जो लोग हरियाणा को देखने आते है उनके व्यू क्या हैं. उन्होंने एक और बात लिखी है कि–

"Already the simple and unsophisticated people of Southern districts have begun to praise Mr. Bansi Lal, the Chief Minister of Haryana."

17.00 बजे ।

और वह क्या कहते हैं? चौधरी बंसी लाल के लिए मैं एक ही मिसरा– कहता हैं कि बड़ी मुश्किल से होग है चमन में दीदवर पैदा' यह उनका जज्बा है डिवैल्पमैंट पर बेसड है । बंसी लाल जी ने हर तरफ हिवैल्पमैंट ही की है । जैसे चौधरी दल सिह ने यहां यह कह दिया कि नहरें बना दीं और इसके लिये बहुत सारी जमीने ले लीं मेरे दोस्त को यह नहीं पता कि ऐसा करने से उनके जींद के इलाके को तो बचा लिया, बहां पर अगर ऐसा न करते तो सेम के कारण चौधरी साहब के मकान को वहां पर नूनी लग जाती । इन्हें तो चौधरी बंसी लाल को इन कामों के लिये दाद देनी चाहिये और जो वह जमीन भी भी, वह भी रिक्लेम कर दी, उसको बचा दिया । इस के अलावा डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह भी कहूंगा (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी तो मैंने बोलना था और आप घण्टी बजा रही हैं ।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब, जो मैम्बर गवर्नर एड्रैस पर नही बोले हैं उनको भी टाइम देना है ।

चौधरी मेहर चन्द : डिपटी स्पीकर साहिबा, मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि मुझे थोड़े से टाइम के लिए और बोलने की इजाजत दें ।

उपाध्यक्षा : अच्छा आप दो मिनट और बोल ले ।

चौधरी मेहर चन्द : इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कहना चाहता हू कि मेरा हल्का इरीगेशन के लिहाज से बारानी है, मैं वहां पर वाटर अलाउंस की तरफ इतना स्ट्रैस नही करता, वह तो जब रावी का पानी इस तरफ आ जाएगा तब बढ़ेगी यमुना डैम बनेगा वाटर अलाउंस तो तब इंक्रीज हो सकता है लेकिन जो बारानी एरिया है, उस तरफ हरियाणा सरकार को ध्यान देना चाहिए । इस बारे में हरियाणा सरकार के वजीर, मीटिंगों में भी एलान करते हैं तो मैं आपकी मारफत सरकार से, सम्बन्धित वजीर से कहूंगा कि मेरे इलाके में, मेरी कांस्टीचुएन्सी में जो बारानी इलाका है, वहां बारानी न रहने दी जाए । डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं एक और बात फतेहबाद ब्राच के बारे में कहूंगा जो कि मेरे हल्के के हार्ट से जाती है और वह सारे रेतीले एरिया से जाती है कि उस ब्रांच की लइनिंग की जाए । सरकार हांसी ब्रांच की लाइनिग कर रही है, मुझे इससे कोई चिड़ नहीं है, मुझे तो हरियाणा के कोने– कोने से प्यार है और ऐसा काम तो प्रिआरिटी बेसिज पर होना चाहिए, मुझे इसकी खुशी है, लेकिन हमारी फतेहबाद ब्रांच का काम भी होना चाहिए।

इसके साथ–साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एजूकेशन के बारे में कुछ कहूंगा और यह बात मैं अपने वजीर तालीम से कहूंगा कि हमें फीमेल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । बातों की रंपीटशन नहीं करूंगा जो कि रेज्योलूश न के अन्दर हैं । हमारी सरकार का इस तरफ ध्यान होना चाहिए कि मेल

एजुकेशन के साथ–साथ फीमेल एजुकेशन की तरफ भी ख ध्यान दें । यही वजह है कि हरियाणा में फीमेल एजुकेशन की कमी के कारण बाहर के लोग हमें शामिल कहते हैं । तो मैं सरकार मे कहूं गा क अगर आप हरियाणा की और ज्यादा तरक्की चाहते है क हरियाणा और आगे बड़े, तो फीमेल एजुकेशन की तरफ खास तवज्जो दी जाए । इसके साथ–साथ जो एजुकेशन के ऊपर रुपय खर्च किया जा रह है, उस रुपए को इस तरीके से खर्च किय जाए कि जिससे एजुकेशन जाब ओरिएन्टिड बन जाए मेरा यह सुझाव है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एग्रीकल्चर के वारे में अभी चौधरी दल सिंह ने एक बात कही कि प्रोडक्श न में कमी हुई है । वह एक बात भूलते हैं कि एग्रीकल्चर के अन्दर कुदरत ए क बहुत इम्पौर्टेन्ट पार्ट अदा करती है । नहरें तो इसलिए बनाई गई है कि ऐसे इला कों को बचाया जाए जहां कि कहत पड़त थ । जिस साल का उन्होने बताया, उस साल की उन हजरत ने रेनफाल की फिगर्ज नहीं देखीं, य ह मानसून की कमी के कण उस साल की प्रोडक्शन डिपरैसड हुई है । इसके साथ साथ मै एक सुझाव एग्रीकल्चर के बारे में देना चाहता हूं, इस ओर जो तरक्की हुई है, उसक सारा क्रैडिट नहर और बिजली विभाग को जात है । मे यह तो कहूंगा कि एग्रीकल्चर विभाग ने काम तो किए हैं लेकिन जहां तक उनको करना चाहिए था वह नहीं किया । जब सरकार बनी थी, टैक्नीकल स्टाफ का जिकर करता हूं, नान–टैक्नीकल स्टाफ

का जिकर नही करता, उस समय जो टैक्नीकल स्टाफ को फिगुर्ज थीं, वह थी 499 और आजकल वह फिगर्ज 15 सौ के करीब और अब जो यह प्रोडक्शन है, यह भी आममान तक जानी चाहिए ले जा नही रही । इतने स्टाफ के बावजूद यह क्रापस को इनसैक्ट पैस्ट से नहीं रोक सके । अगर यह सहूलियात एडीक्वेट हों तो यह प्रोडक्शन बढ़ सकती है । मैं अपने मिनिस्टर महोदय से और फाइनैन्स मिनिस्टर साहब से यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा में जितनी कल्टीवेबल भूमि है, अगर उसको इस नफरी पर तकसीम कर दिया जाए तो एक कर्मचारी को कोई 6 हजार एकड रकबा आता है, अगर वह 6 हजार को लुक– आफटर नहीं कर सकता है तो मैं इस बारे और कुछ नहीं कहूंगा।

इस तरह से मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ होना कि डिस्ट्रीबूशन आफ वर्क कैसे हो, सुपरवीजन हो । अगर किसी वजह से पानी को किल्लत होती है, अफसरो को चाहिए कि वे अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को इस बारे में कहे और फर एग्रीकलचर मिनिस्टर इ स हारे में आई.पी.एम. से बात करे तो सब काम ठीक ढंग से चल सकत है । जब पानी की जरूरत हो तो पानी दे, जब न जरूरत हो तो बन्द कर दें । डिप्टी स्पीकर साहिबा, ए क बात कह कर मैं बन्द क रू गा, वह है हाउसिंग के बारे में । यह बड़ी दर्द नाक बात है । मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार का सा रा ध्यान शहरौ की तरफ है देहातों की तरफ नहीं है । आखिर हम भी देहातों में बसते हैं,

इस तरफ सरकार का ध्यान ही नही है । भट्ठू मण्डी में जब मैं जाता हूं और गरीबों की दिक्कतों को देखता हूं तो उन्हें देग्द कर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा दिल भरता है । आखिर वे भी इन्सान हैं अगर सरकार की देहातों की तरफ नजर हो तो इनायत होगी और इसके लिए मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जब तक उनका ध्यान इस तरफ नहीं होगा, यह काम वैसे का वैसा ही रहेगा । (घंटी)..... डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप घंटी बजाए जा रही हैं, आप मुझे बोलने नहीं देती.. (विघ्न). मैं एक बात जो इस बजट के मुताल्लिक है, आखिर में कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं और फिर मैं अपने फाइनैन्स मिनिस्टर साहब को यह दाद देता हूं कि बजट से यह भावना टपकती है :–

हर चाके के गरेबा से मुसीबत है हमें,

हर हाले परेशां से मुसीबत है हमें ।

पत्तझड से बचाया है चमन को

फूलों से सजाया है वतन को ।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, 1974– 75 का बजट सदन के सामने पेश हुआ हूँ । मोटे लफ्जों में अगर इस बजट के बारे कहना हो तो हम यह कह सकते हैं कि यह उत्साह जनक नहीं है, अगर और भी इसे स्पष्ट शब्दों में कहना हो तो हम यह कह सकेंगे कि यह एक धुंधली तस्वीर पेश करता है और अगर और भी स्पष्ट कहना हो तो हम

कह सकेंगे कि निराशाजनक आशा लिए हे । फाईनैसं मिनिस्टर साहज ने इस बजट पर जो स्पीच पढ़ी उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि–

न छेड़ ऐ नकहते वादे बहारी, राह लग अपनी,

तुझे अठखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा फाईनैस मिनिस्टर साहब ने बजट स्पीच परुते हुए शुरू में स्वंय इस बात को स्वीकार किया है कि हमें पूर्ण रूप में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि हम आशा करते थे । उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि चीजों के मूल्यों के अन्दर वृद्धि हुई परन्तु उसके मुत्तालिक केवल इतना ही कह दिया कि यह तो सारी दुनिया के अन्दर हुई है । उसके साथ ही उन्होंनै परिस्थितियों के ऊपर दोष डाल दिया । कहते हैं कि अगर हम अनाज का निशाना पूरा नहीं कर पाए तो एडवर्स वैदर केडीशन की वजह से ऐसा हु आ । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भगवान की कृपा से वर्षा हो जाए और फसल अच्छी हो जाए तब तो सरकार. कहती हैं कि हमने अच्छा काम किया इसी वजह से फसल अच्छी हुई और अगर वैदर खराब हो जाए तो दोष भगवान को दिया जाता है और कहते हैं कि सरकार कोशिश. कर रही है । जो सरकार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्र गति के साधन जुटा सके वह सरकार है । सरकार ने जो साधन जुटाने हैं उनके नाते सरकार है । नेचर चाहे कुछ भी करे

लेकिन सरकार को प्रगति की ओर कदम बढाने चाहिए । इसीलिए मैंने कहा कि यह बजट उत्साहजनक नहीं है और इसे स्वंय फाइनै 'स मिनिस्टर साहब ने स्वीकार किया है इसकी सब से बड़ी तरक्की की मिसाल मैं देता हू । यह जो बजट–एट ए –गलांस' किताब है इ सके सफा 18 पर –स्टेट इंकम, पर–कैपिटा इंकम हरियाणा की दी हुई है । इसमें दिया हुआ है कि 1970 – 71 के अन्दर पर–कैपिटा इंकम 437 रुपये थी, 1971 – 72 के अन्दर वह 437 से घट कर 434 रुपाए रह गई और 1971 – 72 के बाद 1972– 73 में वह 434 से घट कर 426 पर आ गई है अब 1974– 75 के अन्दर वह कहां पहुंचेगी इस का अनुमान स्वंय फाईनैस मिनिस्टर साहब लगा लें । यह मोटे तौर पर बजट की तरक्की की सव से बड़ी मिसाल मैंने उनके द्वारा बजट के. साथ दी गई किताब से दी है । उसके अन्दर इ स बात को स्वीकार किया गया हैं कि तरक्की नहीं हो रही है बल्कि हरियाणा के अन्दर पर–कैपिटा इंकम आहिस्ता– आहिस्ता नीचे गिरती चली जा रही है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार की नीति या गल्त हैं । उसकी प्लानिंग गल्त है । प्लानिंग किस तरह गल्त है? आज पापुलेशन जिस ढंग से बढ़ती जा रही है उस ढंग से तरक्की को निशानी दिखाई नहीं देती है । आज क्या जरूरत है उसके अनुसार तो हमने प्लानिंग कर ली सैं किन दो साल बाद या चार साल बाद आबादी और बढ़ने वाली है तो उसके अनुसार हमारी प्लानिंग ठीक नहीं होगी। और क्या होता है कि टैक्सैशन बढ़ते जा रहे है और पर–कैपिटा इंकम घटती जा रही है और कीमतें

आसमान को छू रही हैं जब तक कीमतें नहीं घटेंगी तो तरक् को को गति धीमी रहे गी । हम जहां से चले थे वहीं खडे रह जाएंगे । इस लिए डिप्टी स्पीकर साहिबा, बजट के अन्दर यह जो 18 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है यह दूसरे मार्के की बात है । पिछले 4– 5 सालों में हमने इतनी तरक्की की, उसका बड़ा गुणगान किया गया है, इतनी पुस्तकें छापी गई हैं जिनमें से एक हरियाणा 1968 से 1973 है पता नहीं यह पब्लिक रिलेशनज वाले कैसे छाप कर भेज देते है । लेकिन हमारे सामने उसका नजरिया यह है कि पर–कैपिटा इंकम घटी है और उसके साथ आज अगर हम फाईनैंस करने के लिए खड़े होते हैं तो हमें बजट भी घाटे का करना पड़ेगा । यह बजट 18 करोड़ रुपए के घाटे का है और अगले साल पता नहीं कितने का होगा? ये जितनी प्लानिंग करते जाएंगे उसके साथ–साथ आबादी भी बढ़ती जाएगी । और फिर जो कारोबार के साधन है उनके लिए सरकार ने कोई नीति इस प्रकार को निर्धारित नहीं की कि जो लोग बे कार हैं उन को तो रोज गार मिल न । चाहिए लेकिन आगे जो और बेकार होने वाले हैं उनके लिए कुछ भी नही किया गया । तो इस तरीके डैफिसिट का बजट किया होगा!

और भी होंगे मसायब का शिकार उसके अवाम,

हुक्मरानों से बढ़ेगी उनकी नफरत और भी ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा स्टेट के पास रिसोर्सिज बहुत कम हैं यह एक मानी हुई बात है । डैफिसिट बजट देना इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है कि आने बाले 2– 4 महीनों के अन्दर हम कम से कम 24– 2 5 करोड़ रुपये के टैक्स जनता के ऊपर लादने वाले हैं और कोई तरीका नहीं है । मै इसका वर्णन आगे करूंगा कि सोर्सिज क्या हैं और इसमें किसी प्रकार की बढोत्तरी होने की संभावना नहीं है । पर–कैपिटा इंकम घट रही है और हम टैक्स लगा रहे हैं, मुल्यों के अन्दर वृद्धि होती जा रही है, इन सब का नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि हरियाणा सरकार की तरक्की की इन स्कीमों के नीचे जनता टैक्स दे–दे कर मर जाएगी । टैक्सों के बारे में अब मैं बताता हूं कि 'हरियाणा बजट एट ए गलास के पेज 4 पर लैंड रैवेन्यू से तीन करोड़ 70 लाख रुपये की आमदनी दिखाई गई है जब कि पिछले साल यह एक करोड़ 60 लाख रुपये थी । इसका मतलब यह है कि नये लैंड टैक्स हमने लगाए हैं और उनके द्वारा हमारी यह आमदनी बढी है । शायद अब ये और भी बढ़ाने की सोचते हों लेकिन इसको बड़ाने के बाद इसके अन्दर बढ़ाने की कोई और गुंजाइश नहीं है । मुझे एक बात समझ नहीं आई कि फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने 2 6 सफे की एक बड़ी आशा दिलाने वाली बजट की तकरीर पढ़ी है लेकिन इस तकरीर को सुनने के बाद मुझे कहीं भी दो लफ्ज ऐसे नहीं मिले जो कि यह बताएं कि इस 18 करोड़ के घाटे को सरकार पूरा किस तरह से करेगी और अगर सरकार इस घाटे को पूरा नहीं. करेगी और न

ही इसके बारे में सरकार कुछ जानती है तो मुझे समझ नहीं आती कि ये प्लानिंग किस तरीके से पूरी कर पाएंगे। मैं आशा रखता हूं कि फाइनैसं मिनिस्टर साहब जिस समय सदन के अन्दर बताने के लिए खड़े होंगे तो उस समय वे इस ओर जरूर बताएं कि इस घाटे को सरकार किस तरीके से पूरा करेगी मै सदन को इस बारे में अन्धेरे में नहीं रखा जाना चाहिये । डिप्टी स्पीकर साहिबा, बड़ी भारी–भारी इस बजट की पुस्तकें है जो हमें दी गई हैं । मैंने दो दिन बैठ कर इनके एक सफे से लेकर दूसरे सफे तक पूरा अध्ययन किया है और उसके अन्दर से मुझे मिला क्या है?

On page 18 of the Memorandum Explanatory on the Budget for 1974-75, it has been stated—

"The main increase has occurred under the following heads and to the extent noted against each—

	Rs.
Interest payments	17.39 crores"

तो 17.39 करोड़ रुपया यह सरकार इंटैरस्ट पेमैंटसु के लिये रख रही है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, 'वह हरियाणा बजट एट ए गलांस' के सफा 2 पर टोटल वर्किंग कैपिटल बताते हैं तीन सौ करोड़ रुपया का और उममे से डिप्टी स्गईकर साहिबा, 120 करोड़ रुपये पब्लिक डैटस है । अगर इस को बीच में से निकाल दिया जाए तो बाकी 180 करोड़ का बजट रह जाता है और उस के ऊपर 18

करोड़ रुपए के करीब सरकार इन्ट्रैस्ट पे कर रही है । इतनी बड़ी रक्म इन्ट्रेस्ट की देने के बाद हरियाणा सरकार की प्लैंनिग की शक्ल चन्द सालों के बाद क्या रह जाएगी देस का अनुमाम हाउस खुद लगा सकता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले साल के बजट को मैंने देखा तो उस में 14.47 करोड़ रुपऐ सूद के लिए था और इस साल के लिए 19 उ 9 करोड रुपए की सूद की प्रोविजन की गई है । इस बात से साफ जाहिर है कि जिस रक्रूतार' से हमारी तरक्की हो रही है उस से ज्यादा रफ्तार से लोन लिए जा रहे हें । डिपट्री स्पीकर साहिबा, जब 17. 39 लाख रुपया हमारी सरकार सूद देती है और 17 करोड़ 97 लाख के घाटे का बजट पेस करती है तो इस को देखते हुए मोटा हिसाब–किताब लगाने वाला आदमी भी यह कह सकता है कि यह सरकार दिवालिया हो चुकी है, इस के पास अपनी प्लैनिंग चलाने के लिए सूद देने के लिए भी पैसे नहीं हैं । तो यह है नक्शा जो हमारी सरकार तरक्की की स्कीमों का पेश कर रही है । इस का मतलब यह है कि अगर सरकार सूद देगी तो उस के साथ ही टैक्सिज जनता के ऊपर और लगेंगे । डिप्टी स्पीकर साहिबा, बजट के अन्दर जो मूल कर्जा हमारी सरकार ने ले रखा है उस को देने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है । पिछले साल के बजट 'एट– ए–गलांस' के अन्दर भी पबलिक डैट्स 120.77 करोड के थे और इस साल भी 120.32 करोड़ की फिगर है जो कि तकरीबन उस के बराबर की है । इस का मतलब यह है कि सरकार ने जो प्रिंसीपल लोन लिया था उस को लौटाने के लिए इन के पास

किसी प्रकार का रुपया नहीं है और केवल सूद पे करने के लिए इनको घाटे का बजट बनाना पड़ा । इस लिए मैं इस बात को नहीं समझ सका कि हरियाणा सरकार कहां से रिसोर्सिज निकाल कर इस तरक्की की स्कीमों पर लगा रही है । किस तरीके से जो इन्होंने कर्जा ले रखाहै उस को अदा करेगी और किस तरीके से सूद की अदायगी करेगी जो कि हर साल बढ़ता चला जा रहा है । मैं आशा करूंगा कि जवाब देते वक्त हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहब जरूर इन बातों पर रोशनी डालेंगे ।

अब डिप्टी स्पीकर साहिबा, गें बताऊंगा कि टैक्सिज की क्या पोजीशन है । इसी के पेज 161 पर यह जो ऐक्सप्लेनेटरी मैमोरैन्डम आन दी बजट फार 1974– 75 है । (विघन)

उपाध्यक्षा : आप जरा शाट रखना क्योंकि अभी बहुत से मेम्बरों ने बोलना है ।

चौधरी राम लाल वधवा : डिप्टी स्पीकर साहिबा एक घण्टा दस मिनट तो टिक्का जगजीत सिंह जी बोल कर गए है, मैं एक घन्टे के अन्दर– अन्दर ही खत्म करने की कोशिश करूंगा । मैं काम की चीजें बताऊंगा और फिर अपनी सरकार को सुझाव भी दूंगा । डिप्टी स्गईकर साहिबा, मेरे एक आनरेबल दोस्त फाईनैंस सैक्रेटरी और फाईनैंस मिनिस्टर की बड़ी दाद दे रहे थे । दाद देने को तो मेरा भी दिल चाहता हे लेकिन इनकी काबलियत का नमूना मैं आप के सामने पेश करना चाहता हूं । यह लाखों रुपया

एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करते हैं लेकिन उनकी काबलियत का नमूना आप देखिए । इस पर इन्होंने लिखा नै रैवैन्यू डिपार्टमैंट और ब्रैक्टि में लिखा हैं 8.16 करोड़ । इस में लिखा है

"23...Tax Revenue (+8.16 crores) —This increase has occurred due to larger income from ;

(a) State's share in Income Tax; and

(b) Various State Taxes as under ;-

Income Tax

Land Revenue

State Excise

Sales Tax

Tax on Vehicles

Taxes on Passengers and Goods

Other Taxes and duties on Commodities and Services."

इसके नीचे इन्होंने हैडवाईज दिया है– इन्कम टैक्स का शैयर, डलैं रैवन्यू का शैयर, स्टेट ऐक्साईज का शैयर, फिर सैल्ज टैक्स है, फिर टैक्स आन व्हीकल्ज है, टैक्सिज आन पैसै जर्ज एंड गुड्ज और अदर टैक्सिज वगैरा । इन के, डिप्टी स्पीकर साहिब, इन्होंने जो फिगर्ज दिए हैं वह अलइदा– अलहदा दिए हैं । उनका टोटल नीचे नहीं दिया । मैंने खुद बैठ कर उनका टोटल कर के देखा है

वह ऊ पर वाले हैंड के साथ नहीं मिल पाया । ऊपर इन्होंने 8.16 करोड़ दिया है ओर नीचे जो मैंने टोटल कर के देखा हैं वह 8.6 करोड बनता है । तो 10 लाख का घपला तो इस में ओर से ही है । बाकी और पता नही कितना होगा क्योकि मेरे पास सारा बजट चौक करने के लिए इ तना टाईम नहीं है । खैर मैं इनकी इस काबलियत की दाद देता हू । इन्होने ए मेन सोर्स पहले बताया है लैड रैवैन्यू इ सके अन्दर 1 करोड 39 लाख रुपया इस साल बढा है जिसका मतलब यह हे कि इसके अन्दर और बढौत्तरी की गुजायश नहीं हो सकती । इस के बाद स्टेट ड्यूटी सै, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर शराब की आमदन के ऊपर ही यह सरकार चलनी है फिर तो खुदा ही हाफिज है । मैं गांधी जी के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहता उनकी रूह तो आसमान पर स्वर्ग में बैठे हुए इन के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही होगी क्यों कि इन के पास उनके असूलो पर चलने के लिए कोई प्रोगाम नहीं है । जब और कोई जबाब इनको नहीं मिलता तो यह कहते हैं कि अगर दूसरी स्टेट वाले शराब बंद करेंगे तो हरियाणा में भी हम बंद करेंगे । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज हरियाणा के लोगे ?? को शराब पिला–पिता कर इन्होंने 15.50 करोड़ रुपए की इन्कम शो की है यानी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को शराब पिला कर वसूल किया जा रहा हूँ । 15.50 करोड़ को आमदन जो ऐक्सादृ ज की गवर्नमैंट को होत है इसका मतलब यह है कि जो कारखाने वाला शराब को बेचता है या जो लोग ठेका लेते हैं तकरीबन इतना रुपया उनकी जेब में जाता यानी 30– 35 करोड

रुपया सालाना लोगों से शराब का वसूल किया जाता है । इस लिए जो पर कैपिटा इन्कम दिखाई है, उस में से यह रकम निकाल देनी चाहिए क्योंकि इस से किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा, किसी नौजवान का चरित्र निर्माण नहीं हो रहा । इस से लोगों का क्या भला हो रहा है? डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस प्रकार की लानत –अमेज आमदनी को अगर कोई सरकार अपना जरिया बनाए तो मैं समझता हूं कि इस से बड़ी और कोई शर्म नाक बात नहीं हो सकती । इसका मतलब यह है कि अगर इनको रैवेन्यू चाहिए तो यह शराब की नहरें चलाएंगे और वह रुपया लो गों की तरक्की पर लगाएं गे, फिर जब तरक्की हो गी तो लोग शराब और पीएगे और इ स तरीके से यह शराब का चक्कर चलता रहे गा । जब 15. 50 करोड़ रुपया शराब से ऐक्साइज डियूटी का आ जाता है तब इस के अन्दर और कितना रैवैन्यू बढ़ सकेगा यह भी सरकार देख लेगी । अब मैं सेल्ज टैक्स की तरफ आता हूं । इसमें इन्होने 32 करोड़ रुपए की इन्कम शौ की है । मैं बजट के सोर्सिज बताता हूं लेकिन इस सेल्ज टैक्स के बारे में ऐक्सप्लेनेट री मैमौरैडंम के अन्दर यह बात बताई गई है–

"State Excise Duties (+ Rs. 1.50 crores)—The increase of Rs. 1.50 crores is due to larger bid money anticipated from auctions and larger lifting of liquor by the vendors.

Sales Tax (+Rs. 3.00 crores)—The increase of Rs. 3.00 crones represents the normal annual growth of about 8 per cent due to development of economy."

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कम है, दाद देने को जी चाह ता हैं । खुद मान रहे हैं कि कीमतें बढ़ी हैं । पिछले साल जिस चीज की की मत दो रुपए थी इस साल उस की कीमत तीन रुपया हो गई है और उन्ही चींजों के रेट बढने से सैल्ज टैक्स की इन्कम ज्यादा हु ई है । हरियाणा में कोई डिवैल्पमैंट या इकौनोमी की ब ओथ नहीं हुई । पर–कैपिटा इन्कम बताती है कि डिवैल्पमैंट का काम नहीं हु आ है । साफ जाहिर है कि बजट में गलत वजाहत की गई है और इस के इलावा सरकार ने पिछले साल से सेल्ज टैक्स के रेट भी बढ़ाए हैं और कई षीजें जो इ स में शामिल भी नही थीं उनको भी शामिल किया था और इस तरीके से तीन करोड़ रुपया और बढ़ । इस लिए सैल्ज टैक्स के फिगर्ज को बीच में शामिल करके अगर लो गों को गुमराह किया जाए तो गलत बात है । मेन हिस्सा इस की इन् फ्रीज .का रि स के ब ढ जाने से हु आ है और किसी वजह से नहीं हुआ हैं । तो यह कहते हैं कि आमदन बढ दी है इ ससे भी जनता के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ा है । इसके बाद एक और टैक्स है जो इनका मे न सोर्स आफ इन्कम है । और वह है टैक्स आन व्हीकल्ज और टैक्सिज आन पैसेंजर्ज एंड गुडुज । डिप्टी सपीकर साहिबा, इ न दोनों मदों के अन्दर यह कहते हैं और मानते हैं कि इन टैक्सो से भी इन की आमदनी बढ़ी है । ट्रांसपोट से जो यह इतनी आमदनी बताते हैं यह दर असल कोई आमदनी नहीं है । यह इंकम तो इन्होंने मुलाजिमों के बोनस को खाकर इन्कम में शामिल कर दिया है । पिछ ले सैश न में जब इस बारे में एक .बि ल आय था तो मैंने पूरी डिटेल के

साथ बताया था कि किस तरह से इन्होंने ट्रांस्पोर्ट के मुलाजिमी के बोन स को खा कर, काट कर इन्कम में शामिल कर दिया थे । अगर बोनस को निकाल दिया जाए और व्हीकल पर जो टैक्स बढ़ाया है जो कि सरकारी वहीकल हैं, बुक ट्रांसफर की बात है उससे जो इन्होंने बोनस मुलाजिमों का मारा हूँ उसे निकाल दिया जाए तो पता लगता है इनकी आमदनी कितनी बढ़ी है । फि र इन्होंने वर्करों की अमैनिटीज को काट कर और मुसाफिरों की सहूलियतो को नजर अंदाज करके इन्कम को बढ़ाने की कोशिश की है । जब इन्हो ने ट्रांस्पोर्ट को नैशनेलाइज करने की बात की थी तो इन्होंने यह कह कर यह काम किया था कि लोगों को जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने के लिए जो कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले नहीं देते हैं ऐसा किया जाएगा । लेकिन जो सहूलियतें आज ट्रेवलिंग जनता को मिल रही हैं उसे कौन नहीं जानता । जब हम हाउस में पूछते हैं कि बसों में ओवर–लोडिंग क्यों है तो यहां खड़े हो कर जबाब देते है कि बसें नही मिलती है । आज ओक्र लोडिंग की हालत यह है कि बसों में लोगो को भेड़ बकरियों की तरह टटि किया जाता है । बोरियों की तरह बसों में भरा जाता है । और फिर बसों की क्या हालत है? बस सड़क पर खड़ी होती है और सवारियां भी अपने बिस्तर ट्रक या अटेची लिए सडक पर खड़ी होती हैं क्योंकि बस चलती ही नहीं । मैं पूछना चाहता हूं और जनता यह जानना चाहती है कि करोड़ों रुपया जनता से टैक्सों की सूरत में लेकर उनको क्या यही सुविधायें दी जा रही हैं कि वह सारा–सारा दिन सड़कों पर खडे

रहते हैं और बसों में भेड बकरियों की तरह भरे जाते हैं । एयर कंडीशंड और डीलक्स बसें चला कर और बड़े–बड़े रै स्टोरैंट खोल देने से तो जनता को राहत नहीं मिलती । एक आम आदमी को सहू लियत नहीं मिल जाती । आ म आदमी को तो यह अमैनिटी मिलती है कि और जगह तो चाय का कप 25 पैसे में मिलता है लेकिन आपके अड्डो पर 40 पैसे उनकी जेब से निकाले जाते हैं । फिर डिप्टी स्पीकर साहिबा, छोले जो अड्डों पर इनके रेस्टोरैट्स पर मिलते हैं वह ऐसे हैं कि सारी प्लेट को छान लो एक दाना नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा । फिर आप देखें आज एक रुपए के पी छे, उस गरीब जिसका यह रोना रोते नहीं थे कते, 40 पैसे पैसैंजर टैक्स के चार्ज किए जाते हैं । मैं कहता हूं कि यह टैक्स नहीं यह तो मुगलिया सल्तनत का जजिया है जो यह गरीब जनता से वसूल कर रहे हैं ।

उपाध्यक्षा : अब आप वाइंड–अप करें ।

चौधरी राम लाल वधवा : उपाध्यक्ष महोदया, अ भी तो मुझे 25 मिनट ही बोलते हुए हुए हैं ।

उपाध्यक्षा : पांच मिनट और ले लो आध घण्टा हो जाएगा ।

चौधरी राम लाल वधवा : मैं अब जल्दी–जल्दी फैक्टस ऐंड– फिगर्ज आपके सामने रखता हूं और 10– 15 मिनट में खत्म करता हूं । तो मैं अब यह अर्ज करना चाहता हूं कि खर्च किस

बहुतात से किया जा रहा है । वह आप भी देख लें और उसकी डिटेल्ज आपके सामने रखता हुं । इसके अन्दर आप देखें, वाल्यूम एक–डिटेल्ड ऐस्टीमेज आफ रैवैनयू ऐंड रिसीटस मेजर हैड 0– 29 लैड रैवेन्यू में रिसीटसु हैं तीन करोड़ 60 लाख रुपए की और इ सके मुकाबले में आप देखें वाल्यूम दो, डिमांडज फार ग्राटस विद डिटेल्ड– ऐस्टीमेट्स आफ ऐक्सपैडीचर पेज 19 मेजर हैड– 229 लैंड रैवैन्यू इसकी वसुली पर जो खर्च किया गया है वह है एक करोड़ 50 लाख 48 हजार 650 रुपए यानी आधे से ज्यादा रुपया सरकार वसूली पर खर्च कर रही है । यह बहुत ज्यादा खर्च है । सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस भारी खर्च को कम करना चाहिए । इसके साथ ही आप इसी वाल्यूम में पेज 19 मेजर हैंड 045 अदर टैक्सिज एंड डियूटीज आन कमोडिटीज एंड सर्विसिज को देखें । इस में जौ रिसीटज हैं, वह हैं रिसीट्स काम डियूटीज अदर दैन स्टैम्पस, 6 लाख 66 हजार रुपए, रिसीटसु अन्डर एन्टरटेनमैंट ऐक्ट 11 लाख रुपए और फाइन्ज वगैरा के हैं 15 हजार रुपए यानी ये टोटल बनते हैं 17 लाख 67 हजार 500 रुपए । इसके मुकाबले में आप ऐक्सपैडिचर को देखें वाल्यूम दो में ही पेज 33 मेजर हैंड 245 अदर टैक्सिज एंड डियूटिज के नीचे खर्च जो दिखाया है वह है 8 लाख 56 हजार 50 रुपए । तो आप देखें रिसीट्स के अगेंस्ट खर्च कितना भारी किया जा रहा है । यह कोई सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है । फिर आप समाल सेविंगज की मदद को देख लें । प्रोमोशन आफ समाल सेविंगज के लिए यह 21 लाख 59 हजार रुपया खर्च करते हें और

सूद जो देते हैं जो कि बहुत ज्यादा है इसके बल औवा है । यह अ । ईटम आप वाल्यूम दो पे ज 35 मेजर हैड 247 पर मुलाहिजा फर्मा स कते हैं । इस मदद में जो कलैकशन हुई है वह है दो क रोड़ 36 लाख, 9 हजार 451 रुपए । आप देखें कलैकशंज के अगेंस्ट खर्च कितना भारी है और जो सूद की रकम है वह इसके अलावा है । यह बड़ा भारी खर्च है इसमें कमी होनी चाहिए फिर थाप वाल्यूम दो पेज 45 मेजर हैड – 252 सैकेटेरिएट जनरल सर्विसिज पर इस हैड के अंडर कितना खर्च कया जा रहा है वह मैं' आपको बताना चाहता हूं । वह इस प्रकार है.

हैड/ऐक्सपैडीचर टेरविलिंग आफिस

का टाईप ऐक्सपैडीचर ऐक्सपैडीचर

चीफ सैक्रेटेरियट 1,10,000 रुपये 8,02,500 रुपये

फाइनैसं डिपार्टमैंट 70,000 ,, 1,42,000 ,,

होम डिपार्टमैंट 35,000 ,, 1,40,000,

,,

मेनटेनैंस आफ वी.आई.पी. 60,000 ,,

3,75,900 ,,

एयरक्राफ्ट

मैं कहता हूं कि इस सरकार को दाद देनी चाहिये जो इस ने इस छोटी सी स्टेट में वी 0 आई0 पीज 0 के लिए एयर क्राफ्ट रखा है और आठ लाख रुपया सालाना इसकी देख भाल के लिये सरकार खर्च करेगी । इससे सुन्दर बात और क्या हो सकती है? इस आठ लाख के खर्च की डिटेल भी आप देख लें । तनखाह का दो लाख 27 हजार एक सौ रु पया, डी. ए. का 37 हजार रुपया मशीनरी का तुक लाख रुपया, टी. ए. ऐक्सपैडीचर 60 हजार रुपया और दफ्तर का खर्च तीन लाख 7 5 हजार 900 रुपये और यह कुल मिला कर बनता है आठ लाख रुपया जो कि इस हवाई जहाज की देख भाल के लिये ख चे होगा । ऐसी अच्छी सरकार और कहां मिल सकती है जो कि हरियाणा जैसी छोटी स्टेट में, जहां लोगों को पी ने का पानी नहीं मलता, वहां इस तरह के खर्च कर रही है? यह बिल्कुल नाजायज खर्च है और यह हरियाणा के गरीब टैक्स–पेयर के साथ ज्यादती है । फिर आप पेज 45, मेजर हैड– 255, पुलिस, की मदद पर आयें । स्टेट मिलिशिया पर खर्च

हो रहा हूँ एक करोड़ 55 लाख, 48 हजार 130 रुपये और डस्ट्रिक्ट पुलिस पर जो खर्च हो रहा है वह है चार करोड 63 लाख 56 हजार 460 रुपये यानी यह टोटल खर्च पूलिस पर 6 करोड़ 19 लाख 4 हजार 590 रुपये बैठ ता है । आप ही अंदाजा लगायें, कितनी भारी रकम पुलिस पर खर्च की जा रही है । लेकिन इ सके बावजूद जो ला–एड–आडेर की हालत है वह ब्यान से बाहर है । इस पुलिस का सट्टेबाजों से मेलजोल है और अफीम बेचने वालों के साथ हिस्सेदारी है जिस पुलिस पर आप इतना खर्च कर रहे हैं । अगर थाने में कोई काम हो तो किसी सट्टेबाज की सिफारिश ले जाओ, फौरन काम हो जाएगा वरना नहीं होगा । यह हालत है इनकी पुलिस की, जिस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं । पुलिस पर 6 करोड़ से भी ऊपर रकम खर्च कर देना जायज नहीं है और फिर इतने बड़े खर्च करने की जरूरत भी क्या है जबकि यहां शान्तिप्रिय लोग रहते हैं और आप भी ला–एंड–आर्डर की इतनी तारीफ करते हैं । जब हमारी स्टेट का बजट इतने बड़े घाटे का दिखाया गया है तो इन हालात में इतनी भारी रकम पुलिस पर खर्च कर देना कहां तक न्याय की बात है, यह आप ही देख लें । (घंटी) बस जी, मैं अभी पांच मिनट में खत्म करता हूं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह मेरे पास इनकी छापी हुई किताब है 'हरियाणा 1968 टू 1973 । इस में सब से पहले इलैक्ट्रिसिटी का जिक्र आता है । इस में बताया गया है कि कैपिटल पर रिटर्न ईस प्र कार है रू

साल	रिटर्न परसैटेज
1967–68	73 परसैंट
1968– 69	8.4 परसैंट
1 969– 70	8.0 ,,
1970– 71	5. 8 ,,
1971 – 72	4.0 ,,
1972– 73	5.3 ,, (अनआडिटिड)

बिजली बोर्ड ने करोड़ों रुपया खर्च करके बिजली की तारें खिंचवाई हैं । बिजली का बहुत विस्तार किया लेकिन इससे जो रिटर्न है वह नीचे को जा रही है । मुझे समझ नहीं आती कि जो लोन लै रखा है, वह कैसे वापिस होगा? डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके पेज 17 पर ऐग्रीकल्चर का जिक्र किया गया है और इसमें सरकार ने बहुत सारी इन्वैस्टमैंट की है । अगर मैं यहां से सब कुछ पढू गा तो टाईम लगेगा । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी मार्फत एक ही बात कहना चाहूंगा कि इन हालात में ऐग्रीकल्चर कैसे प्रगति करेगा? खाद ये नहीं दे सकते, बिजली ये नहीं दे सकते, बीज ये नहीं दे सकते और सीमेट ये नहीं दे सकते । जमींदार के सामने बड़ी भारी प्रोब्लम है । वह सोचता है कि अगर

नहरें खुदवाकर देंगे तो बिजली कहां से आयेगी, ट्यूबवैल लगायेंगे तो बिजली कहां से आयेगी । अगर खाद पूरी होगी तो पानी नहीं मिलेगा और अगर पानी मिलेगा तो खाद नहीं मिलेगी खाद और पानी मिलेगा तो अच्छे बीज नहीं मिलेगें । इन चीजों को देखते हुये आप अन्दाजा लगाएं कि प्रगति कैसे होगी, किसान का काम कैसे चलेगा ।

चौधरी भजन लाल : आप सुझाव तो दें कि कैसे प्रगति हो सकती है? (विघ्न)

चौधरी राम लाल बधवा : समय दिलवाये, सुझाव भी दूंगा । मैं आपके सामने एक–दो मोटी मोटी बातें कहना चाहूंगा । सबसे पहला प्वायंट फाजिल्का और अबोहर के बारे में है, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया था । फाजिल्का और अबोहर के बारे में मैं एक बात साफ करना चाहता हूं । जब–जब चीफ मिनिस्टर साहब गये तो उन्होने एक ही सवाल किया कि फाजिल्का और अबोहर क बारे में अपोजीशन गड़बड़ करती नै । अपोजीशन अकाली दल से मिल कर गड़बड़ कर रही है । यह बिल्कुल गल्त है । गवर्नमैंट को इसके बारे में अपनी पोजीशन की वजाहत करनी चाहिये । मैं हैरान हूं कि भारत सरकार कांग्रेसी है, पंजाब सरकार कांग्रेसी सै और हरियाणा सरकार भी कांग्रेसी है, अगर हर तरफ कांग्रेस की सरकारें हैं तो गवर्नमैंट अपनी पोजीशन क्लीयर क्यों नहीं करती और अबोहर फाजिल्का हरियाणा में आने में देरी क्यों हे? मैंने 1967 में एक रेजोलूशन मूव किया था और उसको सदन

ने यूनानिमसली पास किया था जिसमें कांग्रेसी भी शामिल ऐ और दूसरी पार्टियों के सदस्य भी शामिल थे । इसके बाद भारत सरकार का अवार्ड आया । (घंटी)

उपाध्यक्षा : आप जल्दी खत्म करें ।

चौधरी राम लाल वधवा : थोड़ा सा टाईम और दे दें । मैं इस सवाल पर एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी चण्डीगढ पंजाब को देने से पहले फाजिल्का और अबोहर के इलाके को ले ले, अपोजीशन मुख्य मंत्री की स्पोर्ट पर खड़ी है, पूरी स्पोर्ट करेगी ।

उपाध्यक्षा : आप बजट पर बोलें ।

चौधरी राम लाल वधवा : जो रुपया कैपिटल बनाने पर खर्च करना है उस पर बोल रहा हूं । दूसरी बात कैपिटल के बारे में है । राजधानी बनाने के बारे में सरकार कुछ बता दे तो ठीक रहेगा । भिवानी के पास च्यांग और महम इत्यादि गांवों के लोग कहते हैं कि वहां कैपिटल बनेगा, उन्हे उजाड़ा जा रहा हे । यह आम कहा जा रहा है कि वहां राजधानी बनेगी । मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि राजधानी बनाने से पहले सदन को कन्फिडैंस में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि राजधानी कहां पर बनेगी ताकि जनता में जो पैनिक फैला हुआ है, वह खत्म हो ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात असैंशल कमोडिटिज के बारे में कहूंगा । असैशंल कमोडिटिज, जरूरियाते जिन्दगी की जो

चीजें है, इन पर मैं ज्यादा तफसील से नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि सरकार को इसका प्रबन्ध करना चाहिए । महंगाई होने के बावजूद अगर एक आदमी सारा दिन लाईनों में जा, कर खड़ा होगा एक मजदूर तेल और खांड के लिए तीन–तीन दिन तक लाईनों में खड़ा रहेगा और इतनी तपस्या करने के बावजूद भी तेल और चीनी नहीं मिलती, निराश होकर घर वापिस आ जाता है तो डिप्टी स्पीकर साहिबा देश की डिवैल्पमैंट क्या होगी? मजदूर के काम के घंटे कम होंगे । अगर गरीब आदमी, मजदूर आदमी को लाईनों में खड़ा होना है तो वह काम कब करेगा? इसका नतीजा यह होगा कि तरक्की पीछे हटेगी, आगे नहीं बढ़ेगी ।

एक और बात सरकार से कहना चाहता हूं कि उन्होंने गवर्नमैंट मुलाजमो को राहत देने का जिक्र बजट के अन्दर नहीं किया, सिर्फ इतना कह दिया कि देंगे । लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह अश्योरैस न बजट के अन्दर है और न बजट– स्पीच में है कि कब देंगे, इसकी कोई न कोई डेट फिक्स होनी चाहिए । जितनी महंगाई दुसरी स्टेटों में हे उतनी ही यहां है । (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं किसी और भाई को कह देता हूं कि वह पांच मिनट कम बोल ले लेकिन आप म्रुझे पांच मिनट और दे दें । हां, मैं कह रहा था कि हरियाणा के गवर्नमैंट इम्पलाईज को दिल्ली के पैटर्न पर डी. ए. मिलना चाहिए और सरकार को एक कंक्रीट प्रपोजल बनानी चाहिए कि कितने दिनों में, कब देंगे, इसका ऐलान शीध्र करना चाहिर । आज प्राईस–इंडैक्स बहुत बढ़

रहा है और गवर्नमैंट मुलाजम हकबजानब है । आप देख रहें है, बिजली कर्मचारियों में, टीचरों मैं रोज कोई न कोई गड़बड़ डी. ए. के बारे में होती रहती है । इसलिए एक कमीशन या बोर्ड बना दिया जाए जो हर छः महीने के बाद प्राईस–इंडैक्स को ध्यान में रखते हुए डी. ए. पर नजरसानी करे । वह कमीशन यह देखे कि कितना प्राईस–इंडैक्स बल है, उसके मुताबिक काम करे ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ न होने पाये ।

इसके साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात सरकार से आपकी मारफत और कहना चाहता हूं । शहरों में एक ही प्रौपर्टी के ऊपर दो प्रकार कैं टैक्स हैं–एक प्रापर्टी–टैक्स और दूसरा हाउस टैक्स । हाउस–टैक्स म्युनिसिपल कमेटी लेती सै और प्रापर्टी टैक्स सरकार लेती है । इन दोनों टैक्सों को मिला कर एक ही टैक्स करना चाहिए और जितना हिस्सा म्युनिसिपल कमेटी का बनता है वह उसे देना चाहिए । एक ही जायदाद पर दो प्रकार के टैक्स अनुचित हैं । इसके साथ–साथ प्रोफैशनल टैक्स है जो अर्बन एरियाज के लिए एक मुसीबत है । इस टैक्स में रुपया थोड़ा आता है, मेरे ख्याल में 30– 32 लाख रुपये के करीब आमदनी होती होगी । लेकिन इस टैक्स के लिए एक–एक आदमी को हिसाब– किताब रखना पड़ता है । यह टैक्स अर्बन एरियाज के लिए बड़ा दुःखदायी है इसलिए इसको खत्म करना चाहिए ।

एक बात और सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं । हरियाणा प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट करनाल टोप का डिस्ट्रिक्ट है,

खेतीबाड़ी का सैन्टर है, सबसे ज्यादा पैदावार होती है । आज कुरूक्षेत्र इससे अलहदा हो गया है । करनाल में सबसे ज्यादा पैदावार होती है, गवर्न मैट को सबसे ज्यादा रैवैन्यू आता है लेकिन इसकी प्रगति के साधन बहुत कम हैं, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि प्रगति के साधन हैं ही नहीं । सरकार दूसरे डिस्ट्रिक्टस की तरफ ध्यान देती है लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं है । करनाल में कोई गवर्नमैंट कालेज महीं है, कोई मैडीकल कालेज नहीं है । आजकल एम. बी. बी. एस. डाक्टर्ज की बहुत कमी है लेकिन हरियाणा में जो एग्जिस्टिंग ' कालेज हैं उन में सीटें कम हैं । इस लिये अगर सरकार करनाल में मैडीकल कालेज खोल दे तो डाक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी । इसके इलावा करनाल में कोई हैवी प्रोजैक्ट नहीं लगाया गया जो कि निहायत जरूरी है । मेरे इलाके में एक तरफ कोढी–कालोनी है और दूसरी तरफ उचाना लेक है । अगर किसी ने बीमार होना हो तो कोढी–कालोनी में चला जाए और अगर डूब मरना हो तो उचाना लेक में चला जाए, इनके सिवाए और कुछ नहीं है । मेरी प्रार्थना यह है कि वहां पर अधिक अनाज होता है । एग्रीक्लचर इम्पलीमैंटंस का सैन्टर है । इसलिए करनल को इंडस्ट्रियल टाउन करार दिया जाए । एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स का सैन्टर होने के नाते करनाल में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खोली जाएं । डिप्टी स्पीकर साहब वहां पर करनाल में एक और चक्र चला हुआ है । एडमिनिस्ट्रेशन ने डिवैल्पमैंट के नाम पर लोगों के बने हुए मकान गिरा दिए लोगों के साथ बड़ी धक्केशाही कर रही है । रामनगर

के अन्दर लोगों को बिना नोटिस दिए उनके मकान और दुकानें गिरादीं, 35 दुकानें जी. टी. रोड पर गिरा दीं, उनको सामान भी नहीं निकालने दिया गया । सरकार जो डिवैल्पमैंट का. काम कर रही है यह लोगों की बरबादी के ऊपर महल खड़ा करने की बातें कर रही है । दुकान मकान गिराने से पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए ताकि लोग अपना सामान वगैरा निकाल लें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, कोई सूचना तक नहीं दी गई ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं खत्म करने वाला हूं । एग्रीकलचर के अन्दर बढौत्तरी होनी चाहिए, यह मैं मानता हूं । मैं लास्ट बात कहना चाहता हूं जो कि एक सुझाव है । एग्रीकल्चर पर इतना भारी इन्वैस्टमैंट करने के बावजूद भी बढ़ोत्तरी नहीं हुई । एग्रीकल्चर में क्यों बढौत्तरी होनी चाहिए? क्योंकि हम चाहते है कि पैदावार बढे, भारत में जो अनाज की कमी है उसको पूरा कर पाएं, इसके लिए सरकार जितने भी काम करै ठीक हे, लेकिन इससे हमारे रिसोर्सिज नहीं बने गे, हमारा रैवैन्यू नहीं बढ़ेगा । आज हम महसूस कर रहे हैं कि पैदावार के लिए बिजली चाहिए, जितनी चाहिए उतनी देंगे चाहे इंडस्ट्री तबाह हो जाए लेकिन इंडस्ट्रीज पर कट लगेगी और एग्रीकल्चर को देंगे । लेकिन इससे रिसोसिंज नहीं बढेंगे । मैं आपकी मारफत सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार हरियाणा स्टेट में रिसोर्सिज बनाये अगर तरक्की करनी है । अगर आप हरियाणा के नौजवान के हित में काम करना चाहते है तो रिसोर्सिज बढ़ाओ । अगर नौजवान को

काम नहीं मिलेगा तो वे स्कूलों और कालिजों से निकलने के बाद, पढाई पूरी करने के बाद जब वह मैदान में खड़ा होगा तो वह तखरीब का काम करेगा, बिल्डिंग्ज को तोड़ेगा, स्कूलों को जलाएगा । यह इसलिए करेगा क्योंकि गर्नवमैंट काम नहीं दे पाती । इसलिए अगर स्टेट की तरक्की करनी है तो स्टेट को इडस्ट्रियलाइज करना चाहिए । एक यही तरीका है जिससे लोगों को काम मिलेगा, इससे पैदावार होगी, एक्सपोर्ट होगा और हरियाणा में पैसा ज्यादा आयेगा ।

आज आप किसान के अन्दर कितना इंसेन्टिव लगा सकेंगे, कितनी उसकी पैदावार बढ़ा सकेंगे? (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) उसका भी तो परिवार बढ़ रहा है, उसके भी तो इंडिपैन्डैंट बच्चे हैं, वे भी चाहते हैं कि वे खुशहाल हों । इसके लिए जरूरी है कि रूरल एरियाज के अन्दर इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, अपने तरीके तालीम को बदलना चाहिए, इंडस्ट्रियल इस्टिच्यूशंज के जो बड़े–बड़े प्रोजैक्ट्स फरीदाबाद, करनाल और सोनीपत के अन्दर लगे हुए हैं उनके अन्दर देहात के बेकार नौजवानों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, आज के तालीमी शान की जगह इंडस्ट्रीज का ज्ञान उन्हें दिलाया जाए, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात को न माने तो जिस वक्त उसे जमीन की जाती है या लोन दिया जाता है उस वक्त उसे मजबूर किया जा सकता है कि इस तरह की ट्रेनिंग उसे हमारे बेकार नौजवानों को देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग के लिए सरकार को ग्गट देनी चाहिए और

जिस समय ये नौजवान ट्रेनिंग लेकर निकलें उस समय सरकार इनको कर्जा देकर रूरल एरियाज के अन्दर छोटी–छोटी इंडस्ट्रीज लगवाए । मिसाल के तौर पर ऐसकोट फैक्टरी के अन्दर ट्रैक्टर बनेते हैं, मोटर साईकिल बनते हैं और टैलिविजन बनते हैं । इन सब के पार्टस इन नौजवानों के द्वारा देहात में बनवाए जाएं । जापान के पैटर्न के तौर पर आज सारे हरियाणा को इंडस्ट्रियलाइज किया जाना चाहिए । यही एक तरीका है जिससे सरकार के रिसोसिंज बढ सकते हैं सरकार का रैवैन्यू बढ़ सक्रूता हैं । मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर अवश्य घ्यान देगी ।

Mr. Speaker : You have taken sufficiently long time,

Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Only two minutes more, Sir.

Mr. Speaker : Order please. Chaudhri Abdur Razak Khan.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa : All right, sir. Thank you.

चौधरी अखुर रजाक खां (फिरोजपुर झिरका) : मोहतरिम स्पीकर साहब, आज यह हाउस साल 1974– 75 के बजट पर बहस कर रहा है । फाईनैस मिनिस्टर साहब ने जो बजट पेश किया इससे उम्मी द है कि हरियाणा के हर हिस्से में तरक्की होगी और कहीं–कहीं जो पिछले वक्त में इम्बैलैंस रहा उसको दूर किया जाए गा । मसलन फिरोजपुर झिरका और नूह इस स्टेट के

बैकवर्ड एरियाज हैं । उनकी तरफ पिछले दो साल में बहुत कम तवज्जुह दी गई । जो मुसीबत थी वहां फलड की उसको दूर करने के लिए वाकई ही काम किया गया है और वह काम काबिले–तारीफ है । कुछेक जगहें वहां पानी से भरी हुई रहती थीं और उस जमीन को काश्त करना मुश्किल था उस पानी को भी सरकार ने निकाला है । यह भी काबिले तारीफ है लेकिन इसके साथ मुस्तकिल मुसीबत को दूर करने के लिए रैगुलर ढंग की कोई खास प्लानिंग अभी तक नहीं हुई है । 1970 में अपने लीडर आफ दी हाउस ने एक वायदा भी दिया था लेकिन वह भी अभी तक पूरा नहीं हुआ । इस इ लाके में रावली पर्वत है जो कि काले पहाड़ के नाम से जाना जाता हैं । हमारे लीडर आफ दी हाउस ने उस समय कहा था कि नहर तो अभी इस इ लाके में आ नहीं सकती लेकिन रावली पहाड़ के दामन में सरकार टयूबवैल्ज लगाएगी, हर गांव के लिए दो तीन टयूऋबवैल्ज प्रोवाईड करेगी और इस तरह से टैम्पोरेरी इरीगेशन उस इलाके को दी जाएगी इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी और आमदनी बढ़ने से उनकी बैकवर्डनैस और पिछड़ापन जो है वह दूर हो जाएगा । आ ज इस वायदे को तीन साल होने को हैं लेकिन यह पूरा नही हुआ । लोग बड़ी आंखें लगाए हुए हैं इस तरफ और उनके मन में यह बात घ र कर रही है कि हरियाणा स्टेट के सरबरा, जिन्होने तमाम स्टेट की तरक्की के लिए हंगामी इरादे के साथ कदम उठाया है वे हमारी तरफ पता नहीं क्यों नजर नहीं करते । इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि यह स्कीम जो गालबन तैयार ही हो चुकी हे, जल्दी से जल्दी

इम्पलीमैंटेशन होनी चाहिए । उस इलाके में जमीन के अन्दर पानी का बहुत भारी जखीरा है, इसलिए मेरी अर्ज है कि वहां सरकारी टयूबबैल्ज लगाकर जल्दी से जल्दी लोगों को पानी मुहैया किया जाए ताकि पैदावार बड़े और खुशहाली आए ।

स्पीकर साहब, उस इलाके की गिरावट की वजह यह है कि वहां तालीम नहीं हूँ । लोगों में हिम्मत भी कही है कि वे अपना कंट्रिब्यूशन करके तालीमी अदायरे खोल लें । इस बारे में भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वायदा किया था कि वहां एक गवर्नमैंट कालेज दिया जाए गा । इसके लिए इलाके के लोगों ने 14– 15 एकड़ जमीन भी दे रखी है जो कि अभी तक खाली पडी है । न वहां काश्त होती है और न उस का पट्टा ही ट्रो ता है । लो गो ने डेढ हजार रुपये के क रीब कंट्रिव्यूशन भी कर रखा है । तो सरका र इ स तरफ तवज्जुह दे क्योंकि उस इलाके में तालीम को बढ़ाने के लिए गवर्नमैंट कालेज का होन बहुत जरूरी है ।

स्पीकर साहब, हमारी स्टेट में मुसलमान भाइयों की आबादी आठ लाख के करीब हे लेकिन हमारे त्योहारों की छुटिटुयो में इक जुहा की छुटट्री नहीं है । इ स बारे में भी मैं कई बार कह चुका हूं लेकिन सरकार ने अभी तक इसे छुटिटुयों की लिस्ट में शामिल नहीं किया । आल इंडिया दर्जे पर यह छु

टूटी होती है, मिसाल के तौर पर पंजाब में होती है, हिमाचल में हो ती है, दिल्ली में होती है और राजस्थान में भी होती है । इसके बारे में पिछले सैशन में भी मैंने याद दिलाई थी कि हमारे यहां भी यह छुट्टी होनी चाहिए ताकि हमारे मुलाजिम भाई अपने घरो में जाकर ईद का त्योहार मना सके ।

स्पीकर साहब, हमारे इलाके की बहुत सारी लैंड जो है उसमें टिब्बे ही टिब्बे पड़े हैं । अगर वहां चितौडा और पिगांव आदि चार पांच जगहों पर बांध बांध दिए जांए तो खेती के लिए काफी क मीन निकल आए गी, पैदावार में इजाफा होगा, लोगों की आमदनी में इ जाफा हो गा, लोग खुशहाल होंगे और स्टेट का रैवैन्यू भी बढ़ेगा । वाटर सप्लाई का, स्पीकर साहब, स्टेट में बहुत काम हुआ है लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इस बात का लिहाज नहीं रखा गया कि बैकवर्ड एरियाज में जहां पानी खारा सै, जहां के कुएं बंध के अन्दर आ गए और जहां जाने के लिए बरसात में रास्ता नही रहा, और जहां के लिए सरकार ने कहा थ कि प्रयरिटी बेसिज पर पानी दें गे वहां आज दो साल हो गए लोगों को पानी नही मिला । मेरे इलाके में ही रावली, मोहली, सोनपुर, बरागपुर और खड़ी आदि पांच सात गांव ऐसे हैं जिनके पानी वाले कुएं बध के अंदर आ गए थे और बरसात के अन्दर वहां जाने तक का रास्ता नहीं रहा । वे बे चारे पड़ौसी गांव से जाकर पानी लाते हैं । इन लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड रहा है । मैं समझता हूं कि इनको प्रायरिटी बे सिज पर पानी मिलना चाहिए ।

आपकी मार्फत, स्पीकर साहब, मैं अपने वजीर मुताल्लिका से अर्ज करूगा कि वे इस तरफ जल्दी से जल्दी तवज्जुह दें । यह बात उनके नोटिस में पहले भी लाई जा चुकी है । इसके बाद, स्पीकर साहब, एक बहुत ही जरूरी बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस इलाके में सवाए जमीन के मेहनत करने का और कोई तरीका नहीं जिस को लोग अपने बच्चों की कमाई का जरिया बना सकें । इस इलाके में कोई कारखान नही है जबकि कार–खाना लगाने के लिए गुजायश मौजूद हे, बहां सरसों की पैदावार बे इन्तहा होत है और वह सरसो मंडियों के जरिए कलकत्ता तक पहुंचती है । अगर बही पब्लिक सैक्टर की तरफ से आयल मिल लग जाए तो काफी लोगो को रोजगार मिल सकता है और अपनी स्टेट कई आमदनी भी बढ़ सकती है । इसी तरह से वहां कच्चा चमड़ा भी काफी तादाद में मिलता है । अगर एक दो टैनरीज वहां लग जाएं तो जहां उनसे हरिजनों और गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा वहां सरकार का रैवेन्यू मी बढेगा ।

स्पीकर साहब, इस इलाके में एक बहुत बड़े शहीद नवाब श मशुद्दीन हुए हैं । इनकी यादगार बनवाने के बारे में भी मु ख्य मंडी जी ने वायदा फरमाया था कि उसे फिरोजपुर झिरका में बनवाएगे। ये सारे वायदे, जिन्हें मैं स्पीकर साहब हाउस में अर्ज कर रहा हूं, एक पब्लिक मीटिंग में दिए गए वायदे थे लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनमें से कोई वायदा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है । तो मैं आपके द्वारा स्पी कर साहब चीफ

मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि उनकी यादगार को भी जल्दी मे जल्दी बनवाया जाए क्योंकि शहीदों की यादगार बनवाना उनकी कुर्बानी का ऐहतराम करना है । इससे लोगों को एक तालीम भी मिलती है कि मुल्क को आजाद कराने के लिए कैसी–कैसी लोगों ने कुर्बानी दी थीं और हम नई नस्ल हमारी आजादी को कायम रखने के लिए अपनी जान तक देने का एक सबक सीखती है ।

स्पीकर साहब, इन बातों में, सरकार के काम में जहां कमी रही है वहां इसके दो चार महकमों ने सराहना योग्य काम भी किया है । मैं उनकी तारीफ करता हूं । सबसे नुमाया काम जो नजर में आता सै वह फारैस्ट डिपार्टमैंट का है । आज हरियाणा की हर सड़क हरी भरी नजर आती है । यह काबिले तारीफ काम है । जो जमीन खाली पड़ी हु ई थी या सड़क, नहर और रेलवे लाईन के आस पास यों ही बेकार पडी हुई थी वहां फारैस्ट डिपार्टमैट ने दरखत लगाए हैं और सारे हरियाणा के पैसे को सही इस्तेमाल किया है । इनसे आमदनी होने की भी उम्मीद है क्योंकि इन्होने ऐसे दरख्त ऐसे दरखत लगाए हैं जिनसे कागज मिल को रा–मैटीरियल मुहैया हो सकेगा । पहाडों पर जो खु शहाली आयी है वह काबिले तारीफ हूँ । जो जनरली रेतीले इलाके थे वहां पर आज हरियाली ही हरियाली है । फोरैस्ट डिपार्टमैट ने इस थोडे से चार–पांच साल के अर्से में बहुत ज्यादा मेहनत की है । स्टेट

का इतना छोटा रकबा होने के बाबजूद बड़ी अच्छी कामयाबी हुई है।

18.00 बजे

अब मै बिजली के विषय में अर्ज करना चाहता हूं । महकमा बिजली ने जो थोड़े से अर्से में इलैक्ट्रीफिकेशन की है वह काबिले तारीफ है लेकिन जो मेंटेनैन्स है उसमें कमी के कारण लोगों को काफी तकलीफ हैं । जो तारीफ के काम हैं उनके बारे में बिल्कुल गुरेज नहीं करता लेकिन जो फील्ड वर्करज का काम है वह तसल्लीबख्श नहीं है । फील्ड में, मीटर रीडर्ज गल्त रीडिंग लेते हैं और जो सुपरवाइज करने वाला स्टाफ है वह भी बाज–औकात मीटर को तोड़ देते हें, जान–बूझ कर तोडू देते हैं । अनपढ़ किसानों को बड़ी उम्मीदें थीं कि बिजली के आने से हमारी फसल बढ़ेगी, आमदनी बढेगी, अपनी बैकवर्डनैस दूर करेंगे । आज उस गरीब आदमी को इतनी परेशानी है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता । साल–छः महीने के बाद मीटर तोड़ दिये जाते हैं । अगर वे एस ० डी० ओ ० आफिस में जाते हैं तो पांच सौ रुपया या एक हजार रुपये पैनेल्टी लगायी जाती है । इस किस्म की परेशानी लोगों को हो रही है । बोर्ड को इस बारे में सुधार करना चाहिये ताकि गरीब लोगों को राहत की बजाए मुसीबत का सामना न करना पड़े । ऐसी–ऐसी मिसालें हैं जिनमें बाकायदा रीडिंग ली जाती है । 22 तारीख के करीब रीडिंग ली जाती है, उसकी 1,400 रीडिंग है फिर ये लोगों को कहते हैं कि

तुम्हारी सील टूटी हुई है, तार लूज है । इस किस्म के इल्जाम लगाकर फील्ड के मुलाजम किसानों को तंग करते सैं । बोर्ड और बोर्ड मुतालिका वजीर साहब से यह अर्ज है कि यह जो किसानों को तकलीफ है, अवाम जो परेशान है इसका डिसक्रेडिट सरकार को जाता है, वह दूर किया जाना चाहिए । आज किसान को बिजली मिल रही है लेकिन वे बड़ी ही परेशानी का सामना कर रहे हैं । आपको याद होगा पिछली 24 या 25 तारीख को आप भी हिसार में थे और मैं भी हिसार में था । उस वक्त जनाब स्पीकर साहब किसी की हिम्मत नहीं थी कि रात के वक्त, दिन छिपने के बाद कोई घर से बाहर निकले, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सर्दी थी । उन दिनों के अन्दर किसानों को रात के वक्त बिजली दी जाती थी । इतनी सख्त सर्दी के अन्दर रात को बिजली देने का कोई फायदा नहीं हो रहा था । रात को लोग टयूबवैल्ज से पूरी तरह से सैराब नहीं कर पाये, बल्कि उनको उल्टी मुसीबत हुई, न तो उनका अपना परपज सर्व हुआ और न ही उनकी मशीनें रात को चली, कहने का मतलब यह है कि उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ । उसका कोई खास फायदा हुआ नहीं क्योंकि किसान अपनी फसल को पानी नहीं दे सके । इसलिए मैं आपकी मार्फत यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह दिन को बिजली दे दी जाये । बिजली 12 घन्टे देने की बजाए चाहे आठ घन्टे ही मिल जाये लेकिन 12 घन्टे रात की बजाए दिन में आठ घन्टे मिल जानी चाहिए । रात को जाड़े के मौसम में पानी कण्ट्रोल करना बड़ा मुश्किल है । इसलिए बिजली बोर्ड और मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि डेढ–दो

महीना चाहे छः घन्टे बिजली दे दें लेकिन रात को न दें बल्कि दिन के टाईम में दी जाये । रात को पानी की वैस्टेज होती है । किसान का टयूबवैल्ज चलता है तो बिजली भी उसकी चलती है, उसका खर्च भी होता है लेकिन प्रोपर वे में उसकी यूटेलिटी नहीं होती है । लोगों को जाड़े के कारण नमूनिया और बीमारी का शिकार होना पडता है । एक दो वाक्यात हुए हैं । डागर साहब को सप्लीमैंटरी सवाल में बताया था कि दो–तीन आदमी मौत का शिकार हुए हैं । ऐसे हालात में गवर्नमैंट और बिजली बोर्ड को खुद स्टडी करना कमी के कारण लोगों को काफी तकलीफ हैं । जो तारीफ के काम हैं उनके बारे में बिल्कुल गुरेज नहीं करता लेकिन जो फील्ड वर्करज का काम है वह तसल्लीबख्श नहीं है । फील्ड में, मीटर रीडर्ज गल्त रीडिंग लेते हैं और जो सुपरवाइज करने वाला स्टाफ है वह भी बाज–औकात मीटर को तोड़ देते हें, जान–बूझ कर तोडू देते हैं । अनपढ़ किसानों को बड़ी उम्मीदें थीं कि बिजली के आने से हमारी फसल बढ़ेगी, आमदनी बढेगी, अपनी बैकवर्डनैस दूर करेंगे । आज उस गरीब आदमी को इतनी परेशानी है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता । साल–छः महीने के बाद मीटर तोड़ दिये जाते हैं । अगर वे एस ० डी० ओ ० आफिस में जाते हैं तो पांच सौ रुपया या एक हजार रुपये पैनेल्टी लगायी जाती है । इस किस्म की परेशानी लोगों को हो रही है । बोर्ड को इस बारे में सुधार करना चाहिये ताकि गरीब लोगों को राहत की बजाए मुसीबत का सामना न करना पड़े । ऐसी–ऐसी मिसालें हैं जिनमें बाकायदा रीडिंग ली जाती है । 22 तारीख के करीब

रीडिंग ली जाती है, उसकी 1,400 रीडिंग है फिर ये लोगों को कहते हैं कि तुम्हारी सील टूटी हुई है, तार लूज है । इस किस्म के इल्जाम लगाकर फील्ड के मुलाजम किसानों को तंग करते सैं । बोर्ड और बोर्ड मुतालिका वजीर साहब से यह अर्ज है कि यह जो किसानों को तकलीफ है, अवाम जो परेशान है इसका डिसक्रेडिट सरकार को जाता है, वह दूर किया जाना चाहिए । आज किसान को बिजली मिल रही है लेकिन वे बड़ी ही परेशानी का सामना कर रहे हैं । आपको याद होगा पिछली 24 या 25 तारीख को आप भी हिसार में थे और मैं भी हिसार में था । उस वक्त जनाब स्पीकर साहब किसी की हिम्मत नहीं थी कि रात के वक्त, दिन छिपने के बाद कोई घर से बाहर निकले, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सर्दी थी । उन दिनों के अन्दर किसानों को रात के वक्त बिजली दी जाती थी । इतनी सख्त सर्दी के अन्दर रात को बिजली देने का कोई फायदा नहीं हो रहा था । रात को लोग टयूबवैल्ज से पूरी तरह से सैराब नहीं कर पाये, बल्कि उनको उल्टी मुसीबत हुई, न तो उनका अपना परपज सर्व हुआ और न ही उनकी मशीनें रात को चली, कहने का मतलब यह है कि उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ । उसका कोई खास फायदा हुआ नहीं क्योंकि किसान अपनी फसल को पानी नहीं दे सके । इसलिए मैं आपकी मार्फत यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह दिन को बिजली दे दी जाये । बिजली 12 घन्टे देने की बजाए चाहे आठ घन्टे ही मिल जाये लेकिन 12 घन्टे रात की बजाए दिन में आठ घन्टे मिल जानी चाहिए । रात को जाड़े के मौसम में पानी कण्ट्रोल करना

बड़ा मुश्किल है । इसलिए बिजली बोर्ड और मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि डेढ–दो महीना चाहे छः घन्टे बिजली दे दें लेकिन रात को न दें बल्कि दिन के टाईम में दी जाये । रात को पानी की वैस्टेज होती है । किसान का टयूबवैल्ज चलता है तो बिजली भी उसकी चलती है, उसका खर्च भी होता है लेकिन प्रोपर वे में उसकी यूटेलिटी नहीं होती है । लोगों को जाड़े के कारण नमूनिया और बीमारी का शिकार होना पडता है । एक दो वाक्यात हुए हैं । डागर साहब को सप्लीमैंटरी सवाल में बताया था कि दो–तीन आदमी मौत का शिकार हुए हैं । ऐसे हालात में गवर्नमैंट और बिजली बोर्ड को खुद स्टडी करना चाहिए । इन लोगों की तरफ, जिनके लिए सरकार बनी बैठी है, तवज्जुह देनी चाहिए ।

स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा अर्ज करूंगा कि हमारे यहां तालीम की काफी तरक्की हुई है । इससे कोई इन्कार नहीं है । सन् 1972 से पहले सरकार जो काम कर पायी है, जो तालीम के मदरसे की अपग्रेडेशन की है उसके बाद भी करनी चाहिए । पिछले साल एक स्कूल भी अप–ग्रेड नहीं हुआ और इस साल 1974– 75 में भी नहीं हो रहा है । जो बहुत से डिजरविंग हालात में हैं, जहां पर बिल्डिंग भी मुकम्मल है, गांवों के लोगों ने लिख कर भी भेजा है और मुताल्लिका महकमा ने भी कई बार लिख कर भेजा है और सिफारिश की है यह स्कूल अप–ग्रेडेशन के काबिल सै लेकिन वहां पर अप–ग्रेडेशन नहीं हुई । मेरे अपने हल्के में एक गांव नयी है, वह तहसील फिरोजपुर झिरका में है । उस गांव

की आबादी कोई छः हजार के करीब है । उसकी बिल्डिग भी मुकम्मल है । उसमें मै 50 बच्चे दाखिल हैं । उस गाव के लोग करीब दो साल से परेश हैं लेकिन उनका स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ । मैं मुताल्लिका मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि इस स्कूल को अपग्रेड किया जाये । इसी तरह से एक गांव आलीमेव तहसील नूह ब्लाक हथीन में है । यह स्कूल सन् 1936 से मिडल स्कूल है । उस गांव की आबादी कोई 11 हजार है । यह गांव महकमे की सारी कन्डीशज फुल–फिल करता है । वहां पर बिल्डिग भी है, 700– 800 के करीब बच्चे भी हैं । वे पिछली दफा वजीर साहब के पास आये थे कि हमारे स्कूल को अपग्रेड किया जाये । इसीलिए मेरी सरकार से अर्ज है कि इन दो–तीन स्कूलों को अपग्रेड कर दिया जाये । मैं सरकार का बहुत ही शुक्रगुजार हूंगा ।

इसके अलावा स्पीकर साहब, एक बात बहुत ही जरूरी है इससे सरकार और अवाम दोनों को ही फायदा होगा । यह बात मजमुई तौर पर भूल गये हैं चाहे वे ट्रैजरी बैचीज के लैजसलेटर हैं या चाहे अपोजीशन के लैंजसलेटर हैं । हरियाणा में जो कारकरदगी है, उसमें इन्साफ और इख्लाक की तरफ भी तव्वजुह देनी चाहिए । दूसरी चीजो की तरफ जहां हम चेइन्ताह पैसा खर्च करते हैं, बेइन्ताह दौड़–धूप करते हैं वहां पर इन्साफ इख्लाक की तरफ हम बड़ी सुस्तरवी से काम कर रहे हैं । यह सुस्तरवी के कारण आज मुलाजमत के लिए यह हालत हो गई है कि एक

लडका हमारा 15– 16 साल का नौजवान जो कि बाकायदा कोर्स पास करता है, डिप्लोमा हासिल कर लेता है लेकिन उसके जेहन में यह भूत सवार है कि बगैर सिफारिश के उसको मुलाजमत नहीं मिलेगी । हमारी स्टेट के तालीमयाफता लोगों का यह जेहन बन जाता है तो क्या होता है कि जब भी किसी पोस्ट की एडवरटाइजमेंट होती है तो हजारों लोग चन्डीगढ दौड़े जाते हैं । उन डिप्लोमा होल्डर्ज की अनपढ़ लोग सिफारिश करते हैं । यह स्टेट की सबसे बड़ी बैकवर्डनैस की निशानी है । इस तरह से लोगों को हौसला नहीं होता है न कोई अच्छी डिवीजन लेते हैं, न अच्छी मार्किग लेते है वे बराय नाम से इम्तहान पास कर लेते है । वे इन लोगों की बात पर ही इनहसार हैं कि सिफारिश होगी तो नौकरी मिल जायेगी । हमारी स्टेट के अन्दर जो बड़े डिजरर्विग लोग हैं, जो मेहनती भी हैं वे तो रह जाते हैं क्योंकि उनकी कोई सिफारिश नहीं होती है । स्टेट को इस बारे में वकार कायम करना चाहिए । उनको प्रायरिटी बेसीज पर, उनको सीनियरिटी बेसीज पर मुलाजमत मिलनी चाहिए । इस बात से बड़ा हैजान इलाके में है । जब भी कोई पोस्ट निकलती है तो बड़ी भीड़ लग जाती है । उनका इस बारे में यकीन है कि बगैर सिफारिश के काम नहीं होगा, मुलाजमत नहीं मिलेगी । इस तरफ आम तवज्जुह देनी चाहिए । सरकार को स्टेट का इख्लाक बुलन्द करना चाहिए और आज यानी लोगों को अपनी बात कहते हुए बरायरास्त एहसास है कि चूंकि हमारी सिफारिश नहीं हूँ इसलिए हमारी बात कोई नहीं सुनेगा । सरकार के एडमिनिस्टेरशन के मैदानी माहौल

में गरीब आदमी परेशान हैं और जो सफेदपोश यानी अपना पेशा अपना चुके हैं कि बगैर पशीने के, बगैर मेहनत के रखे हुए हैं यानी दलाली का पे शा रखे हुए हैं वे आज इलाकों में और थानों में, तहसील हैडक्वाटर्ज पर छाये हुए हैं और अवाम इतनी परेशान है कि अपनी बात सही मायनों में नहीं कर पाती है । उसके जरिए आयेगा यानी रिश्वत देगा तब काम होगा । एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सुधार होना चाहिए ताकि जरुरतमन्द लोगों को मौका मिले । इस तरह से हालत रही तो स्पीकर साहब टाईम तो गुजर रहा है लेकिन सरकार के डिसक्रेडिट में कोई कसर नहीं रहेगी । सरकार ने यूनिवर्सिटी बनाने का भी बडा ही नुंमाया रोल अदा किया हूँ । वह काबिले तारीफ काम है । हमारे हस्पताल भी बडी बेहतरीन हालत में हैं । हमारा फिरोजपुर झिरका गुड़गांव से 52 मील था । वहां पर पहले एक्सरे की फैसिलटी प्रोवाइड नहीं थी । बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था । एक्सरे कराने के लिए 150 रुपया खर्च हो जाता था । जो काम हुआ है उसकी जितनी तारीफ की जाये वह थोड़ी ही है । इसके साथ–साथ जहां हमने तरक्की की है वहां तनजअली भी नुमाया की है उसकी तरफ भी हमें तवज्जुह देनी चाहिए । मैं आपकी मार्फत मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करुंगा कि जरा स्टाफ में सुधार किया जाए क्योंकि स्टाफ मन–मानी करता है । सरकार ने कई–कई लाख रुपये की बिल्डिग बनाकर, लाखों रुपये की सालाना मैडीसन्ज देकर और हजारों रुपये की ऐम्पलायमैंट दैकर इतना बड़ा सरमाया स्टेट में लगा रखा है लेकिन अगर एक नौकर या मुलाजिम अवाम से अच्छा

बीहेव नहीं करता तो उससे स्टेट को डिसक्रैडिट मिलता है । यदि उन अस्पतालों में बीसियों लाख रुपया लगाने के बावजूद भी सरकार को बदनामी मिले तो उससे क्या फायदा है? मैं आपकी मार्फत सरकार से यह अर्ज करूंगा कि स्टाफ की चौकिंग करें । इसके अलावा एक बात इस सिलसिले में मैं और कहूंगा । बाज–वक्त जो स्टाफ के लोग हैं, कई केसिज में हमने यह देखा है कि एक–दो बैठे रहते हैं और बाकी सब स्टाफ आपसी मेल–मिलाप करके बाजारों में घूमते–फिरते हैं । इसलिये मेरी अर्ज यह है कि स्टाफ की चौकिंग अवश्य की जाये' । रोडवेज के बारे में किसी को कोई शुबहा नहीं है कि इसमें तरक्की हुई है । जो आमदो–रफ्त में कन्ट्रोल हुआ है, वह काबिले तारीफ है लेकिन अब भी जो छोटे– मोटे नुक्स मौजूद हैं, जब तक चौकिंग नहीं होती, वे दूर नहीं होंगे । हमारे यहां गुड़गांव डिपो में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले कन्डक्टर होते थे लेकिन अब उन्हें कन्डक्टर से तरक्की देकर आर्जी तौर पर इन्सपैक्टर बना दिया गयॉ है । बोर्ड़ से इन्सपैक्टर मांगे गए थे लेकिन किन्ही बजुहात से उनकी सिलैक्शन नहीं हो सकी है इसलिये उन्हें आर्जी तौर पर इन्सपैक्टर बना दिया गया है ।' अपनी' नौकरी पक्की रखने के लिए वे लोग ख्वामखाह चालान करते हैं । जिस बस में बच्चे हों, उस बस के कन्डक्टर का वे ख्वामखाह चालान कर देते है । इस तरह से वे हरेक कन्डक्टर के खिलाफ एक–दो केस महीने में बना देते है । जो कन्डक्टर उनके साथ मिल जाता है उससे वे बड़ी–बड़ी रिश्वते लेते है । जो रिश्वत उन्ह मिलती है वह हमारी स्टेट की आमदनी

में से कटती है क्योंकि वह कन्डक्टर जो उन्हें रिश्वत देगा, वह टिकंटो की चोरी करेगा । या तो टिकट नहीं काटेगा या फिर पैसैन्जर को परेशान करेगा । इसलिये मेरी. अर्ज यह है कि इस बारे में काफी सुधार की जरूरत हूँ । यह जरूरत है कि उनकी चौकिंग की जाये और इस बारे में कोई सख्त ताकीद की जाये ताकि स्टेट का भी नुकसान न हो और काम भी ठीक ढ़ंग से चलता रहे ।

इसके अलावा एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं । हमारे यहां जो गुडगांवा की वर्कशाप है, मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं वे कृपया इस ओर ध्यान दे, उसकी बड़ी पुअर कन्डीशन है । हालाकि गाड़ी की फिटनेस की रिपोर्ट मिल जाती है कि हमने इसको चौक कर लिया है लेकिन फिर भी खड़–खड़ करके गाड़ी निकलती है और हिलती जाती है । यदि कोई पुर्जा गाडी का हिल गया हो तो वर्कशाप उसको लगाने के लिए पाबन्द नहीं है । आप ही देखिये कितनी लापरवाही है । अगर एक प्लेट के चार बौल्ट्स हैं और उसका सक बोल्ट गिर गया हो तो उसके न लगने कि वजह से दूसरे बोल्ट भी गिर जाते हैं और प्लेट गिर जाती है । (घण्टी)

Mr. Speaker : Please wind up.

चौधरी अब्दुर रजाक खाँ : जब गाड़ी कीसही मायनों में मुरम्मत नहीं होती तो वह आवाज करती हैऔर उसकी वजह से नुकसान बढ्ता है । हमने यह बात डिपो के मैनेजर को नोट

करवायी थी लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ । हमने इस बारे में कर्नल साहब से भी कहा था कि जो मुरम्मत करने का ढंग है, वह ठीक नहीं है, इस की तरफ खास तवज्जुह दी जानी चाहिए ।

इसके अलावा, मैं ए क और बात अर्ज करना चाहता हूं । मेरे इलाके में एक गांव ढेकली है । मलाई ब्रान्च और इस गाव के बीच में जो जगह है वहां पर पानी खड़ा रहता है । वहाँ पर एक नहर निकलती है और साईफन भी है । वहां के लोगों ने पिछली दफा मिनिस्टर साहब से भी इस बारे में दरख्वास्त की थी । मेरी अर्ज है कि ऐसा इन्तजाम किया जाए ताकि जो पानी वहां पर खड़ा रहता है वह बाहर चला जाये । मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री के. एन. गुलाटी (फरीदाबाद) : माननीय स्पीकर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिये कुछ टाईम दिया । सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने जो बजट पेश है, उसके लिये मैं तेहदिल से अपने चीफ मिनिस्टर साहब, फाइनैसं मिनिस्टर साहब और सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है । थें तो यह सोच रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब, फाइनैसं मिनिस्टर और सरकार ने अपना पूरा दिमाग लगाकर जनता के हित को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया है । एक बार फिर मैं बजट की दाद देते हुए कुछेक बातें सुझाव के रूप में

कहना चाहता हूं । आपको यह पता ही है कि जब कोई काम करता है तो काम में थोड़ी बहुत गल्तियां जरूर हो जाती हैं । नुक्ताचीनी करना बड़ा आसान है मगर अमली तौर पर काम करना बड़ी हिम्मत की बात होती है । स्पीकर साहब, इस बात में सच्चाई है कि हरियाणा में पिछले 4– 5 सालों के अर्से में, जबसे यह स्टेबल मिनिस्ट्री आयी है, बहुत काम हुआ है । इस बात में जरा भी शक नहीं है और हरियाणा में हुई तरक्की इस बात को मुह बोलती तस्वीर है । हम मैम्बरान का भी यह फर्ज हो जाता हे और वक्त की भी यह पुकार है कि अच्छे आदमी को ऐनकरेज किया जाये और गलत आदमी को डिसकरेज किया जाये लेकिन काम करते हुए किसी आदमी को यू ही डिसकरेज किया जाये या ख्वाम–खाह उसकी नुक्ताचीनी की जाये तो यह सरासर काम में रुकावट डाल ने वाली बात है । स्गई कर साहब, मैं ठी क बातों की तारीफ करने के साय–साथ कुछेक बाते फरीदाबाद के बारे में कहना चाहता हूं क्योकि मैं फरीदाबाद का नुमायंदा हूं । मैं फरीदाबाद का जिक ज्यादा और दूसरों का जिक्र कम करूंगा । सबसे पहले मैं आपकी मार्फत अपने चीफ मिनिस्टर साहब और फाइनैस मिनिस्टर साहब से एक अर्ज करना चाहता हूं । थोड़े से दिन पहले की बात है मुझे खुशी हुई जब चीफ मिनिस्टर साहब ने यह वायदा किया कि फरीदाबाद को एक खुबसुरुरत शहर बनाया जायेगा और उसके लिये 5–10 करोड़ रुपया दिया जायेगा । मैं चाहूंगा कि फाइनैंस मिनिस्टर साहब कुछ रकम बजट के अन्दर फरीदाबाद को खुबसुरत बनाने के लिये रिजर्व रखें ताकि किसी

को कोई शको–शुबह न रहे और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो वायदा किया है, वह पूरा हो । यह बात बहुत दुरुस्त है कि हमारे चीफ मिनिटर साहब बड़े फि राख दिल हैं और जो वायदा करते हैं, उसे पूरा करते हैं । मेरी गुजारिश यही है कि फरीदाबाद के लिये अगर कुछ रकम रिजर्व कर दी जाये तो बहुत अच्छी बात होगी । यह मेरी एक सजैशन है ।

फरीदाबाद में सेनीटेशन और पानी की समस्या बड़ी गम्भीर है और हमारा फरीदाबाद एक कम्पलैक्स होने के नाते हरियाणा का दिल सै । इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि फरीदाबाद को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाये और वहां पर दो–तीन मडिया खोली जायें । वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बी. एड. कालेज, एम. एड. कालेज और एक बडा अस्पताल, जैसे कि एक बार मैंने अपने चीफ मिनिस्टर की मुंह से यह सुना था कि वहां पर 500 बैड्ज का अस्पताल बनेगा, बनाया जाये । इन चीजों की वाकई वहां पर जरूरत है । जब तक इसके लिये पैसा रिजर्व नहीं किया जायेगा तब तक कैसे इसकी तरक्की की तरफ ध्यान जायेगा? मैंने जगह के बारे में गवर्नर एडैरस पर हुई डिस्कशन में भी बताया था । अब भी बताता हूं । फरीदाबाद में गाफ क्लब के पास कोई सौ एकड़ के करीब जमीन मौजूद है जो इस्तेमाल नहीं की जाती है । अगर सरकार उस जमीन को लेकर वहां पर कुछ बना दे तो फरीदाबाद वाकई एक खूबसूरत शहर बन जायेगा और फरीदाबाद की तरक्की हो जायेगी । स्पकिर साहब, आपके द्वारा

सरकार के नोटिस में मैं एक और बात लाना चाहता हूं । आज फरीदाबाद और बल्लभगढ की आबादी तकरीबन 5 लाख की हो गई है । यह लेबर का इलाका है । यहां पर एक एस० पी० की पोस्ट की सख्त जरूरत है । इस बात के लिए अगर बजट में प्रोवीजन कर दिया जाए तो सरकार की बड़ी कृपा होगी । ला एड आर्डर जो कि मैं मानता हूँ, बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी उसमें और ज्यादा तरक्की लाने के लिए फरीदाबाद में जितनी पुलिस चौकियां हैं, उनमें हरेक में टेलीफोन्ज लगाने के लिए बजट में पैसा अलाट करना चाहिए । इसके साथ–साथ मैं आपकी मारफत सरकार से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में या फरीदाबाद में जिग्ने भी इम्पौरटैंट दफतर हैं, चाहे वह फूड एड सिविल सप्लाई का दफ्तर हैं, एजुकेशन का है या दूसरे इम्पोरटैट दफतर हैं, उनके अन्दर टेलीफोन का होना बहुत जरूरी है । इसके लिए बजट में प्रोवीजन होना चाहिए । स्पीकर साहब, एजुकेशन के बारे में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह ठीक है कि जब तक सैन्ट्रल सरकार कोई और तरीका नहीं बदलती तो हरियाणा सरकार कैसे बदल सकती है लेकिन अगर हरियाणा सरकार जो मौजूदा रूल्ज एंड रेगूलेशंज हैं, उनमें थोड़ी बहुत तबदीली कर दे तो मेरे ख्याल में एजुकेशन के मामले में हरियाणा ने जितनी तरक्की अद की. है, उससे ज्यादा तरक्की करेगा । मिसाल के तौर पर 35 स्टूडैंट्स के ऊपर अगर एक टीचर मुकरर्र हे तो अवश्य ही सारे स्कूलों में 35 स्टूडैंट्स के ऊपर एक टीचर देना चाहिए । और किसी वजह से यह शर्त पूरी नहीं हो सकती है तो जो

इम्पौरटैंट सबजेक्स है जैसे बायोलोजी, इंग्लिश सौर दूसरे इम्पौरटैंट सबजैक्ट्स हैं और जहां इनके टीचर्ज की कमी हूं, वहां स्टाफ पूरा देना चाहिएं क्योंकि इम्तहान सिर पर हैं । जिन स्कूलो में फंड्ज मौजुद हैं और जहां पर सैनीटेशन की तकलीफ है, वहां पर उसकी ओर भीं ध्यान देना चाहिए । एक बात जो नैशनल करैक्टर को पूरा कर सकती है वह है कि स्कूलों में एक या आधा घंटा का पीरयड सोशल, नैशनल, और धार्मिक प्रीचिंग के लिए रखा जाए अथर इस पर कुछ बजट भी खर्च होता हो तो कोई बात नहीं वै । अगर हर स्टूडेंट को सोशल, नैशनल, धार्मिक तालीम दी जाएगी तो हरियाणा की और भी तरक्की होगी ।

मदर टीचर्ज के लिए भी बजट में प्रोवीजन होना चाहिए । जो तीन साल से सर्विस कर रही हैं उनको रेगुलर करना चाहिए । उन्होंने पिछली स्ट्राईक में भी हिस्सा नहीं लिया था जहां पर किसी स्कूल मे हजार स्ट्डैट्स से ज्यादा हैं वहां पर डबल शिफ्ट अगर कर दी जाए तो इससे स्कूल की तरक्की हो सकती है।

स्पीकर साहब, अब मै रोड़वेज की बाबत कहना चाहता हू। मैंने तो दो साल में बहुत ज्यादा सफर किया हैं मैं महसूस करता हूं कि रोडवेज की बहुत अच्छी सर्विस है लेकिन इसके साथ–साथ और बसें बढ़ाकर तरक्की की ओर कदम बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होगा । अगर एक बस फरीदाबाद से चण्डीगढ के लिए दे दी जाए तो बहुत अच्छा रहे और सोनीपत से बहादुरगढ को एक–दो बसें चला दी जाएं तो बहुत ज्यादा इन्कम होगी और

डी 0 टी 0 यू0 खुद व–खुद अपनी बसें जो वह दिल्ली से फरीदाबाद चलाती है, हटा लेगी ।

अब मैं सरकार का ध्यान लेबर की तरफ दिलाना चाहता हूं । हरियाणा के अन्दर एक लेबर ट्रिबयूनल जरूर होना चाहिए और लेबर कोर्ट एक और बढ़नी चाहिए.। शाप इन्सपैक्टरों की पोस्ट को खत्म करके लेबर इन्सपैक्टर बढ़ाने चाहिएं । फरीदाबाद में कम से कम चार लेबर इन्सपैक्टर होने चाहिएं, इस वक्त दो हैं । इस तरह अगर चार इन्सपेक्टर होंगे तो वे शाप एक्ट और लेबर एक्ट दोनों को कन्ट्रोल कर सकेंगे । स्पीकर साहब, लेबर डिपार्टमैंट को और एक्टिव होना चाहिए और जो अवार्ड निकाले उनका फौरन इम्पलीमैंटेशन होना चाहिए । एक बात देखने में आती है कि जो अवार्ड होते हैं उनको इम्पलीमैंट नहीं करते, इससे लेबर के अन्दर बड़ी अनरैस्ट आती है और गड़बड़ तथा स्ट्राईक वगैरह होती हैं । इस वक्त एस्कार्ट में हड़ताल चल रही है । छह हजार वरकर्ज अफैक्टिड हें । एक तो पहले ही पावर कट से मजदूर काफी अफैक्टिड हैं । इन सब चीजों से निपटने का एक हो तरीका है, सरकार मेरे सुझावों को नोट कर ले और वह सुझाव यह है कि अवार्ड को लेबर डिपार्टमैंट जल्दी इम्पलीमैंट करे और जो मौजूदा स्ट्राइकस हैं उन पर ज्यादा ध्यान देकर इन स्ट्राईक्स को जल्दी खत्म करना चाहिए । मैं कल फरीदाबाद में था वहां पहले हो छह हजार मजदूर स्ट्राईक पर हैं और एक लाख मजदूरों को ले–आफ पर ले जाने को स्कीम है और इसके लिए एक

पोलिटीकल पार्टी की तरफ से एक नारा लगा कि 18 तारीख को फरीदाबाद बंद हो । मेरे साथियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी और हमने दुकानदारों, और दूसरे लोगों को कहा कि फरीदाबाद बंद नहीं होगा । हम कोई ऐसी चीज नहीं चाहते जिससे कि ला एंड आर्डर खराब हो । हम नहीं चाहते कि जनता का नुक्सान हो सरकार का नुक्सान हो, इडस्ट्रिलिस्टस का नुक्सान हो, लेबर डिपार्टमैंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि लेबर में अनरैस्ट बिल्कुल न हो । अगर कही अनरैस्ट है तो उसका जल्दी मे जल्दी निपटारा किया जाए ।

स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत सरकार से अरबन एस्टेट की बाबत कहना चाहता हू । आज सीमेंट की बहुत शार्टेज है और अरबन एस्टेट की तरफ से लोगों को नोटिस दिए जा रहे है कि जल्दी मुकाम बनाओ । सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि या तौ लोगों को ज्यादा सीमेंट मुहैया की जाए या बनाने के लिए ज्यादा टाईम दिया जाए । 19 सैक्टर और 21 सैक्टर में जिन लोगों से प्लाट्स के पूरे पैसे ले लिए गए है लेकिन आज तक उनको पोजैशन नहीं मिले हैं । उनको जल्दी ही पोजैशन दी जानी चाहिए ताकि लोगो को पता चले कि हमारी क्या पोजीशन है ।

स्पीकर साहब, पावर कट की तरफ भी मैं एक मिन्ट में सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा यह ठीक है कि तमाम भारत के अन्दर पावर कट की तकलीफ चल रही है और इसके साथ ही

हरियाणा में भी चल रही है और सरकार इस कट को टूर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश भी कर रही है । मैं सरकार को सुझाव दूगा वह इस तरफ पूरा ध्यान देकर इस पावर फट को कम करे। इस पावर कट से लेबर का नुकसान है दुकानदारों का नुकसान है, इंडिस्कूयलिस्टस का नुकसान है, किसानों का नुकसान है । अगर इसको कम किया जाए तो यह सरकार के लिए शोभा की बात होगी और लोगों को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

अब मैं सरकार का ध्यान जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर दिलाना चाहता हूं । हमारा एडमिनिस्टेरशन बहुत ठीक चल रहा है । आजकल के जमाने में एक परिवार को ठीक ढंग से चलाना कितना कठिन कार्य है लेकिन मैं अपने चीफ मिनिस्टर, कैबिनैट मिनिस्टर्ज और आफिसर्ज की दाद देता हूं कि इस नाजुक दौर के अन्दर, आज कल के जमाने में बड़ी बहादुरी से हरियाणा के इस परिवार को चला रहे हैं । लोगों को कोई तकलीफ नही है । हरियाणा का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की और ज्यादा ध्यान दे । (घंटी) स्पीकर साहब, मैने रिक्वैस्ट की थी कि मुझे बीस–पच्चीस मिनट बोलने के लिए दें । अगर मुझे कल टाईम दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

18. 30 बजे ।

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 2.00 P.M. tomorrow the 15th January, 1974.

(The Sabha then adjourned till 2-00 P.M. on Tuesday the 15th January 1974)